December 2023

IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

Baba's Monthly

CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

PARLIAMENT SECURITY BREACH

CONSTITUTIONAL SECULARISM

UTTARAKHAND TUNNEL RESCUE MISSION

PEACE ARRANGEMENTS IN MANIPUR

CONFERENCE ON DISARMAMENT

UNFCCC COP 28

& MORE .....

TOPPER'S RECOMMENDED
BEST CHOICE

IAS BABA

Mohan Sir
Founder, IASbaba

baba's gurukul

- Current Affairs Daily Practice Test (Prelims & Mains)
- Super 100(Mentored by Mohan Sir & Toppers)
- Daily Comprehensive Classes
- Daily Prelims + Mains Test
- Prelims Revision Handouts & VAN
- Group Discussions & Doubt Clearing Platform
- Personalised Mentorship and Feedback
- Analyse Learn Perform (ALP)

& Much more.....

GURUKUL FOUNDATION 2025

(Prelims + Mains + Interview) Program For Freshers

BANGALORE DELHI ONLINE **ADMISSION OPEN**

Scan HERE

Bangalore-9663462015
Dehli-8826490453 Online-9169191888

विषय-सूची

PRELIMS

राजव्यवस्था और शासन

- इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023
- चुनावी बॉण्ड
- आचार समिति
- क्षेत्रीय परिषद
- अनुच्छेद 370
- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB)
- प्रवर्तन निदेशालय (ED)
- दूरसंचार विधेयक, 2023
- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सुरक्षा विधेयक 2023
- केन्द्रीय जल आयोग

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन
- कर्रार लड़ाकू ड्रोन
- एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (AIBD)
- प्रोजेक्ट प्रयास

अर्थव्यवस्था

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
- वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB)
- भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान (IICA)
- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023
- एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETFS)
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज
- सरेंडर वैल्यू
- लीड्स रिपोर्ट 2023
- सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT)
- उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0
- पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA)
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA)
- कार्ड-ऑन-फ़ाइल टोकननाइजेशन (COFT)

भूगोल

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)
- माउंट मरापी
- कंबलाकोंडा वन्यजीव अभयारण्य
- इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान (IGZP)
- वाल्मिकी टाइगर रिजर्व
- कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

- फार्लोविचनस रैपिडस
- नुगु वन्यजीव अभयारण्य
- UNFCCC COP 28
- अंतरसरकारी वार्ता समिति (INC)
- भारतीय बाइसन
- मेगामाउथ शार्क
- इंडियन टेंट टर्टल
- एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीसवायरस उपप्रकार (EEHV)
- कवल टाइगर रिजर्व
- पैन्टोइया टैगोरी
- वैंग्स गार्डन छिपकली

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- एचएच 1177 प्रणाली
- रक्तवर्णकता (Hemochromatosis)
- 'कॉस्मिक वाइन'
- गुइलेन-बैरे सिंड्रोम
- डीपफेक
- आदित्य-L1
- पर्टुसिस (काली खांसी)
- एन्थ्रोबोट्स
- वॉयेजर प्रथम
- केटामिन
- WATSONX.AI
- नोमा
- एपोफिस क्षुद्रग्रह

हेल्थ

- रूमेटाइड अर्थराइटिस
- इरिटेबल मेल सिंड्रोम
- कोविड उप-संस्करण JN.1
- डेंगू

इतिहास, कला एवं संस्कृति

- गुरुपर्व
- गरबा
- मिस्र के ममीकृत बबून
- तंजावुर
- कदलेकायी पैरिश
- गिरसू

- स्टोनहेंज
- काशी तमिल संगमम
- एंड्रियामेलो गुफा
- योगमाया मंदिर
- पंडित मदन मोहन मालवीय

रक्षा एवं सुरक्षा

- बीएसएफ स्थापना दिवस
- स्कैटरड स्पाइडर
- पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली
- विनबैक्स-2023
- भारतीय तट रक्षक
- आईएनएस इम्फाल
- हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS)

सरकारी पहल, योजनाएँ और नीतियाँ, संगठन

- "ग्राम मंचचित्र" ऐप
- इन्फिनिटी फोरम 2.0
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी (GPAI) शिखर सम्मेलन
- भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना
- राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपॉजिटरी पोर्टल
- स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2023
- 'रेल कौशल विकास योजना'
- भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम
- RAMP (एमएसएमई उत्पादकता बढ़ाना और तेज करना) कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)
- लखपति दीदी
- प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
- आंगनवाड़ी-सह-क्रेच

स्पोर्ट्स

- आईबीए जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023
- खेलो इंडिया पैरा गेम्स
- भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI)

विविध

- बुकर पुरस्कार
- एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार
- न्योहोम पुरस्कार
- एशियाई विकास बैंक

MAINS

PAPER 1

- चक्रवात मिचौंग
- महिलाओं के विरुद्ध अपराध में वृद्धि
- भारत का अत्यधिक वर्षा गलियारा

PAPER 2

- मणिपुर में शांति व्यवस्था
- भारत की बढ़ती पड़ोस संबंधी दुविधाएँ
- अधिवक्ता संशोधन विधेयक
- पीवीजीटी के लिए पीएम जनमन योजना
- संसद में सुरक्षा उल्लंघन
- डाकघर संशोधन विधेयक
- भारत-ओमान संबंध
- संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता

PAPER 3

- उत्तराखंड सुरंग बचाव मिशन
- COP28: CCS एंड CDR
- शहरों के लिए COP-28 का क्या मतलब है?
- सुरक्षा और साइबर सुरक्षा
- भारत में शिपिंग उद्योग
- आपदा राहत कोष

Practice Questions

PRELIMS

राजव्यवस्था और शासन

इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023

संदर्भ: हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन हुआ।

इसके बारे में:-

- दिनांक: 05, दिसम्बर,2023।
- स्थान: नई दिल्ली। (इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IIGF))
- यह फोरम एक बहु-हितधारक प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है।
- वर्ष 2023 के इस फोरम की थीम 'भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना' रखी गई है।
- इसके आयोजन का उद्देश्य भारत के लिए एक सुरक्षित, भरोसेमंद और लचीला साइबरस्पेस बनाने, भारत के विकास लक्ष्यों के लिए नवाचार को सक्षम करने, विभाजन को समाप्त करने और भारत के डिजिटल एजेंडे को कैलिब्रेट करने जैसे मुद्दों पर चर्चा करने का एक प्रयास करना है।
- इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी एक पहल है।
- इसके उद्घाटन सत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर भी उपस्थित रहे।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सचिव श्री एस कृष्णन द्वारा एक विशेष भाषण दिया गया, और स्वागत भाषण श्री सुशील पाल, संयुक्त सचिव, एमईआईटीवाई द्वारा दिया गया।
- भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (यूएन आईजीएफ) के साथ जुड़ा हुआ है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2021 में की गई थी।
- भारतीय चैप्टर, IIGF, सरकार, सिविल सोसाइटी, उद्योग, तकनीकी समुदाय, थिंक टैंक और उद्योग संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली 14-सदस्यीय बहु-हितधारक समिति द्वारा समर्थित है।

महत्व:-

- आईजीएफ इंटरनेट के अवसरों को अधिकतम करने और उत्पन्न होने वाले जोखिमों और चुनौतियों का समाधान करने की सामान्य समझ को सुविधाजनक बनाता है।

अवश्य पढ़ें: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

SOURCE: AIR

चुनावी बॉण्ड

संदर्भ: वर्ष 2018 में इन राज्यों में अंतिम चुनावों की तुलना में तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान गुमनाम चुनावी बांडों के माध्यम से राजनीतिक वित्त पोषण 400% से अधिक हो गया।

पृष्ठभूमि:-

- चुनावी बांड योजना के तहत नवीनतम बिक्री (29वीं किश्त) में सबसे अधिक बिक्री तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद (359 करोड़ रुपये) में हुई, इसके बाद मुंबई (259.30 करोड़ रुपये) और दिल्ली (182.75 करोड़ रुपये) का स्थान है।

चुनावी बांड के बारे में:-

IMAGE SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

- चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र की तरह होता है जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जाता है जो भारत का नागरिक हो या देश में शामिल या स्थापित किया गया हो।
- कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉण्ड खरीद सकता है।
- बांड बैंकनोट्स के समान हैं जो मांग पर वाहक को देय हैं और ब्याज मुक्त हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- चुनावी बॉण्ड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और इसे वर्ष 2018 में लागू किया गया था।

मुख्य विशेषताएं:-

- बॉण्ड दानदाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिये व्यक्तियों और संस्थाओं के लिये एक साधन के रूप में कार्य करते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के बॉण्ड जारी करता है।
- यह ब्याज मुक्त होता है और धारक द्वारा मांगे जाने पर देय होता है।
- भारतीय नागरिक अथवा भारत में स्थापित संस्थाएँ इसे खरीद सकती हैं।
- इसे व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से खरीदा जा सकता है।
- यह जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिवसों के लिये वैध होता है।
- भारतीय स्टेट बैंक इसका अधिकृत जारीकर्त्ता है।
    - चुनावी बॉण्ड नामित भारतीय स्टेट बैंक शाखाओं के माध्यम से जारी किये जाते हैं।
- चुनावी बॉण्ड डिजिटल अथवा चेक के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं।
- नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से किया जा सकता है।
    - राजनीतिक दलों को भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ अपने बैंक खाते के विवरणों का खुलासा करना अनिवार्य है।

पात्रता:-

- केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा अथवा विधानसभा के लिये डाले गए वोटों में से कम-से- कम 1% वोट हासिल किये हों, चुनावी बॉण्ड खरीदने हेतु पात्र हैं।

लाभ:-

- **जवाबदेही सुनिश्चित करना:** चुनावी बांड के माध्यम से दान केवल ईसीआई के साथ खुलासा किए गए पार्टी बैंक खाते को जमा करना होता है।
- **नकदी लेन-देन में कमी:** खरीद केवल सीमित संख्या में अधिसूचित बैंकों के माध्यम से संभव होगी और वह भी चेक और डिजिटल भुगतान के माध्यम से।
- **पारदर्शिता में वृद्धि:** यह राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग, नियामक अधिकारियों और आम जनता के साथ अधिक पारदर्शी तरीके से संचालित करने में मदद करता है।
- **गोपनीयता का संरक्षण करना:** व्यक्तियों, व्यक्तियों के समूह, गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक और अन्य ट्रस्टों को उनके विवरण का खुलासा किए बिना चुनावी बांड के माध्यम से दान करने की अनुमति है। इसलिए, दाता की पहचान को संरक्षित किया जाता है।

नुकसान:-

- **जानने के अधिकार में बाधा:** मतदाताओं को यह नहीं पता होता है कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को वित्त पोषित किया है, और कितना। चुनावी बांड की शुरुआत से पहले, राजनीतिक दलों को अपने सभी दाताओं के विवरण का खुलासा करना पड़ता है, जो 20,000 रुपये से अधिक का दान दिए होते है।
    - बदलाव नागरिक के 'पता करने का अधिकार' का उल्लंघन करता है और राजनीतिक वर्ग को और भी अधिक अस्वीकार्य बनाता है।
- **अनधिकृत दान:** ऐसी स्थिति में जहां चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त योगदान की सूचना नहीं है, यह पता नहीं लगाया जाता है कि क्या राजनीतिक दल ने आरपीए, 1951 की धारा 29 बी के तहत प्रावधान के उल्लंघन में कोई दान लिया है, जो राजनीतिक दलों को सरकारी कंपनियों और विदेशी स्रोतों से दान लेने से रोकता है।
- **क्रोनी-कैपिटलिज्म की ओर जाना:** यह व्यवसायों के लिए एक सुविधाजनक चैनल बन सकता है, जो किसी चीज के बदले में दिए गए एहसान या लाभ के लिए राजनीतिक दलों के लिए टैक्स हैवन्स में पार्क की गई नकदी को राउंड-ट्रिप करने के लिए हो सकता है।
    - गुमनाम फंडिंग से काले धन का प्रसार हो सकता है।

अवश्य पढ़े: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड पर फैसला सुनाया, भारत का चुनाव कॉमिशन

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

आचार समिति

संदर्भ: हाल ही में, लोकसभा की आचार समिति को माना जाता है कि वह अपने "अनैतिक आचरण" और "विशेषाधिकारों का उल्लंघन" के लिए लोकसभा से त्रिनमूल कांग्रेस सदस्य (सांसद) महुआ मोत्रा के निष्कासन की सिफारिश की है।

पृष्ठभूमि:-

- आचार समिति, जिसका कार्य सांसदों के अनैतिक व्यवहार की निगरानी करना है।

आचार समिति के बारे में:-

- इस समिति का गठन वर्ष 2000 में किया गया था।
- **उद्देश्य:** सदस्यों के नैतिक और नैतिक आचरण की निगरानी करना ; और सदस्यों के नैतिक और अन्य कदाचार के संदर्भ में संदर्भित मामलों की जांच करना।
- यह समिति अन्य सदस्यों द्वारा सदन के सदस्यों के खिलाफ दायर की गई शिकायतों की जांच करती है; यह एक सदस्य के माध्यम से बाहरी लोग; या अध्यक्ष द्वारा संदर्भित है।
- समिति किसी शिकायत की जांच करने का निर्णय लेने से पहले प्रथम दृष्टया जांच करती है।
- यह अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है, जो इसे विचार के लिए सदन के समक्ष रखता है।
- 'अनैतिक' शब्द परिभाषित नहीं है।
- कोई कार्य अनैतिक है या नहीं, इसका निर्णय समिति पर छोड़ दिया गया है।

विशेषाधिकार समितियाँ:-

- आचार समिति अनैतिक आचरण के मामलों को संभालती है, जबकि विशेषाधिकार समिति, या विशेष जांच समिति, किसी सदस्य के खिलाफ अधिक गंभीर आरोपों से निपटती है।
- इन समितियों की ऐतिहासिक मिसाल रही है, वर्ष 1951 में एक विशेष समिति ने एक सदस्य को वित्तीय लाभ के बदले सवालों के द्वारा व्यावसायिक हित को बढ़ावा देने का दोषी पाया।

संसद की समितियों के बारे में:-

- संसदीय समितियों को मोटे तौर पर स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- स्थायी समितियाँ स्थायी (प्रत्येक वर्ष या समय-समय पर गठित) होती हैं और निरंतर आधार पर काम करती हैं, जबकि तदर्थ समितियाँ अस्थायी होती हैं और उन्हें सौंपे गए कार्य के पूरा होने पर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
    - इसमें वित्तीय समितियाँ, विभागीय स्थायी समितियाँ, जाँच हेतु समितियाँ, जाँच और नियंत्रण के लिये समितियाँ, सदन के दिन-प्रतिदिन के कार्य से संबंधित समितियाँ और हाउस कीपिंग या सर्विस कमेटी शामिल हैं।
- तदर्थ समितियों को जांच समितियों और सलाहकार समितियों में विभाजित किया गया है।
- संसदीय समितियाँ अपना अधिकार संविधान से प्राप्त करती हैं।
- अनुच्छेद 105: यह सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 118: यह संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिये नियम बनाने का अधिकार देता है।

संसदीय समितियों के कार्य:-

- सरकार के कार्यों की समीक्षा एवं परीक्षण करना।
- मंत्रियों और अधिकारियों को बुलाने की शक्ति।
- संसदीय समितियां विधेयकों को कानून में पारित करने से पहले उनकी जांच और समीक्षा करके विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- ये विधेयक में बदलाव के लिए सिफारिशें कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह संविधान और देश के कानूनों के अनुरूप है।

संसदीय समितियों का महत्व-

- अधिकांश सांसद चर्चा किये जा रहे विषयों के विषय विशेषज्ञ नहीं होते हैं, जो जनता की समस्या को समझते हैं लेकिन निर्णय लेने से पूर्व विशेषज्ञों और हितधारकों की सलाह पर भरोसा करते हैं। संसदीय समितियाँ सांसदों को विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करती हैं और उन्हें मुद्दों पर विस्तार से सोचने का समय देती हैं।
- ये समितियाँ एक लघु-संसद के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि उनके पास विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद होते हैं।
- जब इन समितियों को बिल भेजे जाते हैं, तो उनकी बारीकी से जाँच की जाती है और जनता सहित विभिन्न बाहरी हितधारकों से इनपुट मांगे जाते हैं।

MUST READ:Joint Parliamentary Committee

SOURCE: THE HINDU

क्षेत्रीय परिषद

संदर्भ: हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की।

पृष्ठभूमि:-

- बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने सभी सदस्यों से सर्वांगीण विकास के लिए सहकारी संघवाद की भावना के साथ काम करने की अपील की।

क्षेत्रीय परिषद के बारे में:-

- क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक (संवैधानिक नहीं) निकाय हैं।
- ये संसद के एक अधिनियम, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित की गई हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का विचार 1956 में भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग-III के तहत पांच क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गईं - उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी।
- पूर्वोत्तर राज्य यानी (i) असम (ii) अरुणाचल प्रदेश (iii) मणिपुर (iv) त्रिपुरा (v) मिजोरम (vi) मेघालय और (vii) नागालैंड क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं हैं।
- उनकी विशेष समस्याओं की देखभाल 1972 के उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के तहत स्थापित उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा की जाती है।
- पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत सिक्किम राज्य को भी उत्तर पूर्वी परिषद में शामिल किया गया है।

उद्देश्य:-

- क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और संघ के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है।
- ये कई विषयों पर चर्चा और सिफारिशें देती हैं।
- ये केवल परामर्शदात्री और विचार-विमर्श करने वाली संस्थाएं हैं।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने इन वैधानिक संस्थाओं की स्थापना की।
- इस अधिनियम द्वारा देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया:-
- उत्तरी क्षेत्रीय परिषद: इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख शामिल हैं।
    - मुख्यालय: नई दिल्ली
- मध्य क्षेत्रीय परिषद: इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं।
    - मुख्यालय: इलाहाबाद
- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद: इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं।

- मुख्यालय: कोलकाता
- **पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद:** इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दमन-दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली शामिल हैं।
  - मुख्यालय: मुंबई
- दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद: इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी शामिल हैं।
  - मुख्यालय: चेन्नई

संगठनात्मक ढाँचा:

- **अध्यक्ष:** केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों का अध्यक्ष होता है।
- **उपाध्यक्ष:** प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किये गए राज्यों के मुख्यमंत्री, रोटेशन से एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिये उस अंचल के आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
- **सदस्य:** मुख्यमंत्री एवं प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा नामित दो अन्य मंत्री और परिषद में शामिल किये गए संघ राज्य क्षेत्रों से दो सदस्य।

कार्य:-

- प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में एक सलाहकार निकाय है और किसी भी ऐसे मामले पर चर्चा कर सकती है जिसमें राज्यों का साझा हित हो और सरकार को सलाह दे सके।
- विशेष रूप से, एक क्षेत्रीय परिषद निम्नलिखित पर चर्चा कर सकती है और सिफारिशें कर सकती है:
  - आर्थिक और सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में सामान्य हित का कोई भी मामला;
  - सीमा विवाद, भाषायी अल्पसंख्यकों या अंतर-राज्यीय परिवहन से संबंधित कोई भी मामला;
  - राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित या उससे उत्पन्न कोई भी मामला।

अवश्य पढ़ें: उत्तर-पूर्वी भारत का एकीकरण और इसका महत्व

SOURCE: AIR

अनुच्छेद 370

संदर्भ: हाल ही में पीएम मोदी ने लिखा कि 'अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया है।

पृष्ठभूमि:-

- 11 दिसंबर 2023 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्तीकरण पर अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया।
- इस निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की संपुष्टि की, जिसे प्रत्येक भारतीय अपने मन में संजोकर रखता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का सरकार का निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिये लिया गया था न कि विघटन के लिये।
- न्यायालय ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि अनुच्छेद 370 अपनी प्रकृति में 'अस्थायी' (temporary) था।

अनुच्छेद 370 के बारे में:-

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य को कुछ विशेष शक्तियों के प्रावधान से संबंधित है।
- यह जम्मू और कश्मीर (J&K) राज्य को एक 'अस्थायी' स्वायत्त दर्जा प्रदान करता है।
- यह अनुच्छेद स्वतंत्रता के बाद कश्मीर का भारत में विलय का परिणाम था। (जम्मू-कश्मीर में परिसीमन)

अनुच्छेद 370 के प्रावधान:-

- इसने जम्मू-कश्मीर को अपना संविधान बनाने की अनुमति दी।
- इसने राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को और प्रतिबंधित कर दिया।
- इसने राज्य को अपना संविधान एवं ध्वज रखने के साथ ही रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार को छोड़कर अधिकांश मामलों में स्वायत्तता रखने की अनुमति दी।
- केंद्र सरकार के पास राज्य में वित्तीय आपात स्थिति लागू करने की कोई शक्ति नहीं थी।
  - आपातकाल केवल आंतरिक अशांति और विदेशी शत्रु से आसन्न खतरे के आधार पर ही लगाया जा सकता था।
- दूसरे राज्यों के भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर राज्य में जमीन या संपत्ति नहीं खरीद सकते।
- जो महिला किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह करती है, वह स्वामित्व का अधिकार खो देती है।

पृष्ठभूमि:-

- स्वतंत्रता के बाद: 26 अक्टूबर 1947 को कुछ विशेष प्रावधानों के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू और कश्मीर (J&K) भारत के डोमिनियन में शामिल हो गया।
- इसी तर्ज पर 1949 में भारतीय संविधान में धारा 370 जोड़ी गई।
    - इसे जम्मू और कश्मीर राज्य को कुछ छूट देते हुए एक 'अस्थायी प्रावधान' के रूप में जोड़ा गया था।
- इन प्रावधानों ने राज्य सरकार को यह नियंत्रण दिया कि उसे केंद्र सरकार की सहमति की चिंता किए बिना राज्य पर शासन कैसे करना है।

धारा 370 हटाना

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने 5 अगस्त, 2019 को संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए कार्यान्वयन) आदेश, 2019 जारी किया, जिसमें पहले जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को निरस्त कर दिया गया।

परिणाम:-

- जम्मू-कश्मीर का अब अपना संविधान, झंडा या राष्ट्रगान नहीं है।
- अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के परिणामस्वरूप इसकी आबादी के पास अब दोहरी नागरिकता नहीं है।
- जम्मू और कश्मीर अब सूचना का अधिकार अधिनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम सहित संसद द्वारा किए गए सभी विधायी संशोधनों का पालन करता है।
- जम्मू और कश्मीर पूरी तरह से भारतीय संविधान और सभी 890 केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत आता है।

जरूर पढ़ें: ऑपरेशन सद्भावना

SOURCE: THE HINDU

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB)

संदर्भ: हाल के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों से पता चला है कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की FIRs मामलें में दिल्ली सबसे आगे है।

पृष्ठभूमि:-

- वर्ष 2022 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़ी एफआईआर की दर सबसे अधिक दर्ज की गई।

इसके बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 1986
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- मंत्रालय: गृह मंत्रालय
- NCRB की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएँ प्रदान कर समर्थ बनाया जा सके।
- इसकी अनुशंसा टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स (1985) ने की थी।
- NCRB को अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) परियोजना की निगरानी, समन्वय तथा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। (आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022)

NCRB के प्रकाशन:

- क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट
- आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या
- जेल सांख्यिकी
- भारत में गुमशुदा महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट

MUST READ:CBI and ED

SOURCE: HINDUSTAN TIMES

प्रवर्तन निदेशालय (ED)

संदर्भ: हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमीन के बदले नौकरी मनी लांड्रिंग मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया है।

पृष्ठभूमि:-

- उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपने बयान दर्ज करने के लिए जांच एजेंसी के दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

इसके बारे में:-

- यह वर्ष 2002 में एनडीए सरकार द्वारा पारित भारत की संसद का एक आपराधिक कानून है।
- प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कानून बना और 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ।
- इसके पास संपत्तियों को जब्त करने, निवेश करने, तलाशने और संलग्न करने के लिए PMLA के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपी गई व्यापक शक्तियां हैं।
- इसे मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए वियना कन्वेंशन में भारत की प्रतिबद्धता के कारण पेश किया गया था। (पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला)
- पीएमएलए सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जिसमें व्यक्ति, कंपनियां, फर्म, साझेदारी फर्म, व्यक्तियों के संघ या निगम और उपर्युक्त व्यक्तियों में से किसी के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कोई भी एजेंसी, कार्यालय या शाखा शामिल है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बारे में:-

- स्थापित: वर्ष 1956 में
- मंत्रालय: राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- प्रवर्तन निदेशालय एक बहु-विषयक संगठन है।
- यह एक कानून प्रवर्तन संगठन है जिसका काम आर्थिक कानूनों को लागू करना और भारत में मनी लॉन्ड्रिंग तथा विदेशी मुद्रा अनियमितताओं जैसे आर्थिक अपराध से निपटना है।

कार्य:-

- निदेशालय के कार्यों में निम्नलिखित अधिनियमों का प्रवर्तन शामिल है:-
  - धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)
  - (धन शोधन निरोधक अधिनियम (पी.एम.एल.ए.) 2002)
  - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा): यह एक नागरिक कानून है जिसके तहत ईडी विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करता है। (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम)
  - विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973
  - 1974 विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत प्रायोजक संगठन
  - भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA): इस कानून के तहत ED को उन भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क करना अनिवार्य है जो गिरफ्तारी का वारंट लेकर भारत से भाग गए हैं और केंद्र सरकार को उनकी संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान है।

संरचना:-

- प्रवर्तन निदेशक:-
  - केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसके सदस्यों में सतर्कता आयुक्त, गृह सचिव, सचिव डीओपीटी और राजस्व सचिव शामिल होते हैं।
  - कार्यकाल: 5 वर्ष तक
- अन्य अधिकारियों की भर्ती:-
  - अन्य अधिकारियों को अन्य जांच एजेंसियों से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से भर्ती किया जाता है।
  - यह भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पुलिस, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर विभागों के प्रतिनिधियों से बना है।

ईडी की शक्तियां:-

- ईडी जांच अधिकारी (आईओ) के समक्ष दर्ज किए गए बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अदालत में सबूत के रूप में स्वीकार्य हैं।
- PMLA के तहत सभी अपराध, जिनसे ईडी निपटता है, उन्हें गैर-जमानती के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ईडी की हिरासत में व्यक्तियों को उनकी स्थिति की परवाह किए बिना, निकटतम पुलिस स्टेशन की हवालात में भेज दिया जाता है।

- एक बार जब ईडी किसी आरोपी की संपत्तियों को जब्त कर लेता है, तो उन संपत्तियों को पुनः प्राप्त करना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होता है।
- नियमित आपराधिक कानून के विपरीत, पीएमएलए के तहत, सबूत का बोझ अभियोजक के बजाय अभियुक्त पर होता है।
- आरोपी व्यक्तियों को अपने बचाव में सबूत प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिससे ईडी की जांच से निपटना कठिन हो जाता है।

MUST READ: **CBI and ED**

SOURCE: AIR

दूरसंचार विधेयक, 2023

संदर्भ: हाल ही में दूरसंचार विधेयक, 2023, संसद में पारित किया गया।

पृष्ठभूमि:-

- राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर यह विधेयक तीन पुराने कानून जैसे 1885 का टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 का भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम और टेलीग्राफ वायर्स (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम, 1950 का स्थान ले लेगा।

दूरसंचार विधेयक, 2023 के बारे में:-

- इसका उद्देश्य वायरलेस नेटवर्क और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए कानून को मजबूत करना और दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस तथा परमिट के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
- यह विधेयक दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं के प्राधिकरण को नियंत्रित करता है, स्पेक्ट्रम की नीलामी के साथ-साथ प्रशासनिक आवंटन का भी प्रावधान करता है, और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति में केबल जैसे दूरसंचार बुनियादी ढांचे को बिछाने के लिए मार्ग के अधिकार का प्रयोग करने के लिए तंत्र को परिभाषित करता है।
- इसमें कहा गया है कि दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने, दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करने और रेडियो उपकरण रखने के लिए केंद्र सरकार से पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता होगी।
- मौजूदा लाइसेंस अनुदान अवधि या अनिर्दिष्ट होने पर पांच साल तक वैध रहते हैं।
- इसमें आपातकालीन उपाय भी बताए गए हैं जो सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में उठा सकती है जैसे संदेशों को रोकना, दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करना और साथ ही किसी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क पर अस्थायी कब्ज़ा लेना।
- इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, परिवहन, उपग्रह सेवाओं (डीटीएच और उपग्रह टेलीफोनी), BSNL, MTNL और सार्वजनिक प्रसारण जैसे निर्दिष्ट उपयोगों को छोड़कर, स्पेक्ट्रम केवल नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा।
- विधेयक में यह भी कहा गया है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए 'डू नॉट डिसट्रब' रजिस्टर की स्थापना के साथ नियम बनाए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें पूर्व सहमति के बिना संदेशों की एक निर्दिष्ट श्रेणी प्राप्त न हो।
- धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के उपाय के रूप में संस्थाओं को अपने उपयोगकर्ताओं का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना भी अनिवार्य किया गया है।
- विधेयक सरकार को संभावित प्रतिकूल देशों से दूरसंचार उपकरणों के आयात पर अंकुश लगाने की अनुमति देता है।
- विधेयक में दूरसंचार सेवाओं के अनधिकृत प्रावधान या नेटवर्क/डेटा तक पहुंच के लिए कारावास, जुर्माना या दोनों से दंड का प्रावधान है। (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई))
- केंद्र सरकार नागरिक अपराधों के लिए एक निर्णायक अधिकारी (संयुक्त सचिव और उससे ऊपर का पद) नियुक्त करेगी।
- नामित अपील समिति और दूरसंचार विवाद निपटान तथा अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) में अपील।
- **क्षेत्रीय प्रयोज्यता:** अब इसका विस्तार भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भी होता है, यदि विचाराधीन अपराध में भारत में प्रदान की गई दूरसंचार सेवा शामिल हो।

महत्व:-

- पुरातन कानूनों को प्रतिस्थापित करता है।
- सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए स्पष्टता प्रदान करता है।
- शासन के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रदान करता है।

अवश्य पढ़ें: भारत में दूरसंचार उद्योग

SOURCE: THE HINDU

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सुरक्षा विधेयक 2023

संदर्भ: हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को अपनी

सहमति दी है।

पृष्ठभूमि:-

- ये तीन नये आपराधिक न्याय विधेयक संसद द्वारा पारित किये गये।

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के बारे में:-

भारतीय न्याय संहिता, विधेयक 2023 के प्रमुख प्रावधान:-

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 का स्थान लिया, जो देश में आपराधिक अपराधों पर प्रमुख कानून है।
- नया अधिनियम सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में जोड़ता है। (भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए)
- पहली बार आपराधिक न्याय प्रणाली में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है।
- **राजद्रोह:** आईपीसी के तहत, धारा 124-ए राजद्रोह के अपराध से संबंधित है और इसमें आजीवन कारावास या कारावास की सजा का प्रावधान है जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है। BNS विधेयक में, 'राज्य के खिलाफ अपराध' से संबंधित अध्याय के तहत प्रावधान 150 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के बारे में चर्चा करता है।
- मानहानि के अपराध में अब दो साल तक की साधारण कैद, या जुर्माना, या दोनों या सामुदायिक सेवा का प्रावधान है।
- पहली बार मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है, इसके अलावा अपराध को 7 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
- इसमें शादी, नौकरी, प्रमोशन के बहाने या पहचान छिपाकर महिलाओं का यौन शोषण अपराध माना जाएगा।
- व्यभिचार: नया विधेयक व्यभिचार के अपराध के प्रावधान को हटा देता है।
- समलैंगिकता: नए विधेयक में 'पुरुषों के खिलाफ अप्राकृतिक यौन अपराधों' के लिए कोई सजा शामिल नहीं है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 के प्रमुख प्रावधान:-

- भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) का स्थान लिया है।
- CrPC गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत की प्रक्रिया प्रदान करता है।
- लोक सेवकों और पुलिस अधिकारियों सहित परीक्षणों, अपील की कार्यवाही और गवाही की रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकती है।
- आरोपी का बयान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जा सकेगा।
- सम्मन, वारंट, दस्तावेज़, पुलिस रिपोर्ट और साक्ष्य के बयान इलेक्ट्रॉनिक रूप में किए जा सकते हैं।
- विधेयक में "संचार उपकरण" सहित इलेक्ट्रॉनिक संचार को जोड़ा गया है।
- किसी अदालत या पुलिस अधिकारी के निर्देश पर, किसी व्यक्ति को पूछताछ के उद्देश्य से कोई भी दस्तावेज़/उपकरण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है जिसमें डिजिटल साक्ष्य होने की संभावना होती है।
- एक पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय हथकड़ी का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है यदि वह आदतन अपराधी (repeat offender) है जो हिरासत से भाग गया हो, या उसने संगठित अपराध, आतंकवादी कार्य, राज्य के खिलाफ अपराध आदि किया हो।
- मौत की सजा के मामलों में दया याचिका दायर करने की समय सीमा के लिए प्रक्रियाओं का प्रावधान है।
- किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने या अस्वीकार करने का निर्णय अनुरोध प्राप्त होने के 120 दिनों के भीतर सरकार को देना होगा। यदि सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, तो मंजूरी प्रदान की गई मानी जाएगी।
    - यौन अपराध, तस्करी आदि सहित मामलों में किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है।
- पुलिस के लिए निवारक कार्रवाई के हिस्से के रूप में दिए गए निर्देशों का विरोध करने, इनकार करने या अनदेखी करने वाले किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने या हटाने के प्रावधान हैं।
- भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 के प्रमुख प्रावधान:-
- भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लिया।
    - यह अधिनियम भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करता है।
    - यह सभी सिविल और आपराधिक कार्यवाहियों पर लागू होता है।
- यह आईईए के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है जिनमें स्वीकारोक्ति, तथ्यों की प्रासंगिकता और सबूत का बोझ शामिल होता है।
- IEA दो प्रकार के साक्ष्य प्रदान करता है - दस्तावेजी और मौखिक।

- दस्तावेजी साक्ष्य में प्राथमिक (मूल दस्तावेज़) और द्वितीयक (जो मूल की सामग्री को साबित करते हैं) शामिल हैं। यह विशिष्टता बरकरार रखता है। यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेजों के रूप में वर्गीकृत करता है।
- IEA के तहत, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत करता है।
- यह सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी संचार उपकरण (स्मार्टफोन, लैपटॉप) में संग्रहीत जानकारी को शामिल करने के लिए ऐसे रिकॉर्ड का विस्तार करता है।
- इसमें निम्नलिखित को शामिल करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य का विस्तार किया गया है: (i) मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति, और (ii) उस व्यक्ति की गवाही जिसने दस्तावेज़ की जांच की है और दस्तावेजों की जांच में कुशल है।

MUST READ: Rape and sexual crimes law in India

SOURCE: AIR

केन्द्रीय जल आयोग

संदर्भ: हाल ही में केरल राज्य सरकार ने केंद्रीय जल आयोग के साथ एक बैठक की।

पृष्ठभूमि:-

- राज्य सरकार ने केंद्र से इडुक्की जिले के मुल्लापेरियार में एक नया बांध बनाने के उपायों में तेजी लाने का आग्रह किया है।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 1945
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग।
- उद्देश्य: अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और योग्यता का उपयोग करके भारत के जल संसाधनों के एकीकृत और सतत विकास तथा प्रबंधन को बढ़ावा देना एवं सभी हितधारकों का समन्वय करना।
- इस पर संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नेविगेशन, पेयजल आपूर्ति और जलविद्युत विकास के लिए देश भर में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए योजनाओं को शुरू करने, समन्वय करने और आगे बढ़ाने का कार्य सौंपा गया है।
- साथ ही, यह ऐसी योजनाओं के लिए आवश्यक अनुसंधान, विकास और कार्यान्वयन भी करता है।

संरचना:-

- CWC की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है जो भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में भी कार्य करता है।
- आयोग का काम तीन श्रेणियों में व्यवस्थित है: डिजाइन और अनुसंधान (डी एंड आर), नदी प्रबंधन (आरएम), और जल योजना और परियोजनाएं।
- भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव के पद पर एक पूर्णकालिक सदस्य प्रत्येक विंग का नेतृत्व करता है।
- एक मुख्य अभियंता के नेतृत्व में एक विशिष्ट मानव संसाधन प्रबंधन इकाई, सीडब्ल्यूसी के मानव संसाधन प्रबंधन या विकास, वित्तीय प्रबंधन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक मुद्दों की देखरेख करती है।

केंद्रीय जल आयोग के कार्य:-

- योजना एवं विकास।
- जल संसाधन आकलन।
- बाढ़ का पूर्वानुमान।
- जलाशय संचालन।
- नदी प्रबंधन।
- बांध सुरक्षा।
- जल विज्ञान सूचना प्रणाली।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

अवश्य पढ़ें: कलासा-बंडूरी परियोजना

SOURCE: THE HINDU

अंतरराष्ट्रीय संबंध

निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन

संदर्भ: हाल ही में, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता पर चर्चा की।

पृष्ठभूमि:-

- उनकी बातचीत हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में वैश्विक प्रगति पर केंद्रित थी, जिसमें हाल ही में 78वीं यूएनजीए प्रथम समिति में चर्चा की गई प्रमुख पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

निरस्त्रीकरण सम्मेलन (सीडी) के बारे में:-

- **स्थापना:** वर्ष 1979 में
- **मुख्यालय:** जिनेवा में पैलैस डेस नेशंस
- यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण मंच है।
- **उद्देश्य:** हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण समझौतों पर बातचीत करना।
- इस सम्मेलन की प्रतिवर्ष बैठक जिनेवा में तीन अलग-अलग सत्रों में होती है।
- **सदस्य:** इस सम्मेलन में 65 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें पांच एनपीटी परमाणु हथियार संपन्न राज्य और प्रमुख सैन्य महत्व के 60 अन्य राज्य शामिल हैं।
- सीडी में प्रत्येक वर्ष तीन सत्र होते हैं।
- सीडी सर्वसम्मति से अपना कार्य संचालित करती है।
- इसके जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के महानिदेशक निरस्त्रीकरण सम्मेलन के महासचिव होते हैं।
- सीडी और उसके पूर्ववर्तियों ने प्रमुख बहुपक्षीय हथियार सीमा और निरस्त्रीकरण समझौतों पर बातचीत की है जैसे:-
  - परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (एनपीटी)
  - बैक्टीरियोलॉजिकल (जैविक) के विकास, उत्पादन और भंडारण के निषेध पर कन्वेंशन
  - विषाक्त हथियार और उनके विनाश पर (BWC)
  - रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण और उपयोग तथा उनके विनाश पर प्रतिबंध पर कन्वेंशन (CWC)
  - व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (CTBT)।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- निरस्त्रीकरण सम्मेलन (सीडी) को संयुक्त राष्ट्र महासभा (एसएसओडी-I) (1978) के निरस्त्रीकरण पर दसवें विशेष सत्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में मान्यता दी गई थी।
- यह अन्य जिनेवा-आधारित वार्ता मंचों में सफल रहा, जिसमें निरस्त्रीकरण पर दस-राष्ट्र समिति (1960), निरस्त्रीकरण पर अठारह-राष्ट्र समिति (1962-68), और निरस्त्रीकरण समिति का सम्मेलन (1969-78) शामिल हैं।
- वर्ष 1984 में इसका नाम बदलकर निरस्त्रीकरण सम्मेलन कर दिया गया।

कार्य:-

- परमाणु हथियारों की होड़ और परमाणु निरस्त्रीकरण की समाप्ति।
- परमाणु युद्ध की रोकथाम, जिसमें सभी संबंधित मामले शामिल हैं।
- बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम।
- गैर-परमाणु-हथियार वाले राष्ट्रों को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी के खिलाफ आश्वस्त करने के लिए प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था।
- सामूहिक विनाश के नए प्रकार के हथियार (रेडियोलॉजिकल हथियार) और ऐसे हथियारों की नई प्रणालियाँ
- निःशस्त्रीकरण का व्यापक कार्यक्रम।
- आयुध निर्माण में पारदर्शिता। (भारत का परमाणु सिद्धांत)

अवश्य पढ़ें: परमाणु निरस्त्रीकरण की नाजुक स्थिति

SOURCE: AWAZ

कर्रार लड़ाकू ड्रोन

संदर्भ: हाल ही में, ईरान ने उन्नत कर्रार लड़ाकू ड्रोन का अनावरण किया।

पृष्ठभूमि:-

- खातम अल-अंबिया वायु रक्षा अकादमी में एक समारोह के दौरान ड्रोन का प्रदर्शन किया गया।

इसके बारे में:-

- कर्रार इंटरसेप्टर ड्रोन को शुरुआत में वर्ष 2010 में प्रस्तुत किया गया था।
- अब इसमें 'माजिद' थर्मल मिसाइल शामिल है, जिसकी कथित तौर पर मारक क्षमता 08 किलोमीटर है।
- यह मिसाइल पूरी तरह से ईरान के अंदर ही बनी है।
- यह ईरान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंपनी (HESA) द्वारा निर्मित एक ईरानी जेट-संचालित लक्ष्य ड्रोन है।
- कर्रार में एक छोटा, क्लिप्पड डेल्टा विंग, एक बेलनाकार, ब्लंट नोज़ड फ्यूजलेज (हवाई जहाज़ का ढांचा) और ट्विन आरोहेड शेप्ड टेलफिन हैं।
- इसमें इंजन के लिए डोर्सल एयर इनटेक है और टेकऑफ़ के लिए एक रॉकेट-सहायता प्रणाली का उपयोग करता है, जिसे पैराशूट द्वारा पुनर्प्राप्त किया जाता है।
- यह ऊंची और निचली ऊंचाई पर उड़ान भरने, दिन और रात में ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होते है।
- इसमें आईएनएस और/या जीपीएस मार्गदर्शन के साथ एक ऑटोपायलट प्रणाली होने की बात कही गई है।
- कर्रार कई प्रकार के हथियार ले जा सकता है, जिसमें एमके 82 सामान्य प्रयोजन बम, एंटी-शिप मिसाइल जैसे बम शामिल हैं।

MUST READ: MQ-9B predator Drone

SOURCE: HINDUSTAN TIMES

एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (AIBD)

संदर्भ: हाल ही में भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (AIBD) जनरल कॉन्फ्रेंस (GC) के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है।

पृष्ठभूमि:-

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि एआईबीडी के इतिहास में यह पहली बार हुआ है।
- इस कदम से एशिया प्रशांत और दुनिया भर के प्रसारण संगठनों को भारत पर भरोसा दिखा।

इसके बारे में:-

- स्थापित: वर्ष 1977 में
- मेजबान: मलेशिया सरकार
- सचिवालय: कुआलालंपुर
- उद्देश्य: नीति और संसाधन विकास के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक जीवंत और सामंजस्यपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वातावरण प्राप्त करना।
- सदस्यता: इसमें 44 देशों के 92 सदस्य संगठन हैं, जिनमें 26 सरकारी सदस्य (देश) शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 48 प्रसारण प्राधिकरण और प्रसारक करते हैं।
- इसमें एशिया, प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका, अरब राज्यों एवं उत्तरी अमेरिका के 28 देशों व क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 44 सहयोगी (संगठन) भी हैं।
- भारत इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
- प्रतिनिधि संस्था: प्रसार भारती एआईबीडी में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रतिनिधि संस्था है।
- इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के तत्वावधान में की गई थी।
- यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UN-ESCAP) के देशों की सेवा करने वाला एक अद्वितीय क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
- यह संस्थान अपने सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्रसारण संगठनों के साथ-साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के भीतर उपलब्ध बौद्धिक तथा तकनीकी संसाधनों को जुटाकर इस जनादेश को पूरा करना चाहता है।
- यह एक अच्छी तरह से स्थापित बुनियादी ढांचे और नेटवर्किंग तंत्र के माध्यम से करता है जिसमें सरकारी एजेंसियां, गैर-सरकारी संगठन, उच्च शिक्षा संस्थान, निजी क्षेत्र और व्यक्तिगत पेशेवर शामिल हैं।

अवश्य पढ़ें: ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट (बीआईएनडी) योजना

SOURCE: THE HINDU

प्रोजेक्ट प्रयास

संदर्भ: हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी ने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया।

पृष्ठभूमि:-

- इसे भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया था।

प्रोजेक्ट प्रयास के बारे में:-

- द्वारा लॉन्च: इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) ने विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट PRAYAS (युवा और कुशल पेशेवरों के लिए नियमित और सहायक प्रवासन को बढ़ावा देना) लॉन्च किया।
- यह IOM इंडिया और इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (ICWA) के बीच एक संयुक्त सहयोग है।
- उद्देश्य: भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा प्रदान करना।
- इसमें राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन चक्र से संबंधित मामलों पर विदेश मंत्रालय के साथ बढ़ी हुई भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक रोडमैप के विकास की परिकल्पना की गई है।
- यह सुरक्षित, व्यवस्थित और सुप्रबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के लिए सभी राज्य-स्तरीय पहलों को समेकित करता है।
- यह परियोजना ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन (जीसीएम) तथा प्रवासन गवर्नेंस फ्रेमवर्क (एमआईजीओएफ) के उद्देश्यों का पालन करती है।
- यह लोगों के व्यवस्थित, सुरक्षित, नियमित और जिम्मेदार प्रवासन तथा गतिशीलता की सुविधा के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए 2030 एजेंडा के लक्ष्य 10.7 के साथ भी संरेखित है।

महत्व:-

- यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन प्रशासन को मजबूत करेगा।
- 32 मिलियन से अधिक भारतीय और भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहते हैं।

अवश्य पढ़ें: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट 2022

SOURCE: THE ECONOMICS TIMES

अर्थव्यवस्था

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)

संदर्भ: हाल ही में, नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) निवेशक अब अधिकतम रिटर्न के लिए कई फंड मैनेजर चुन सकते हैं।

पृष्ठभूमि:-

- पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एनपीएस ग्राहकों को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के लिए तीन फंड मैनेजरों का चयन करने की अनुमति देते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

NPS के बारे में:-

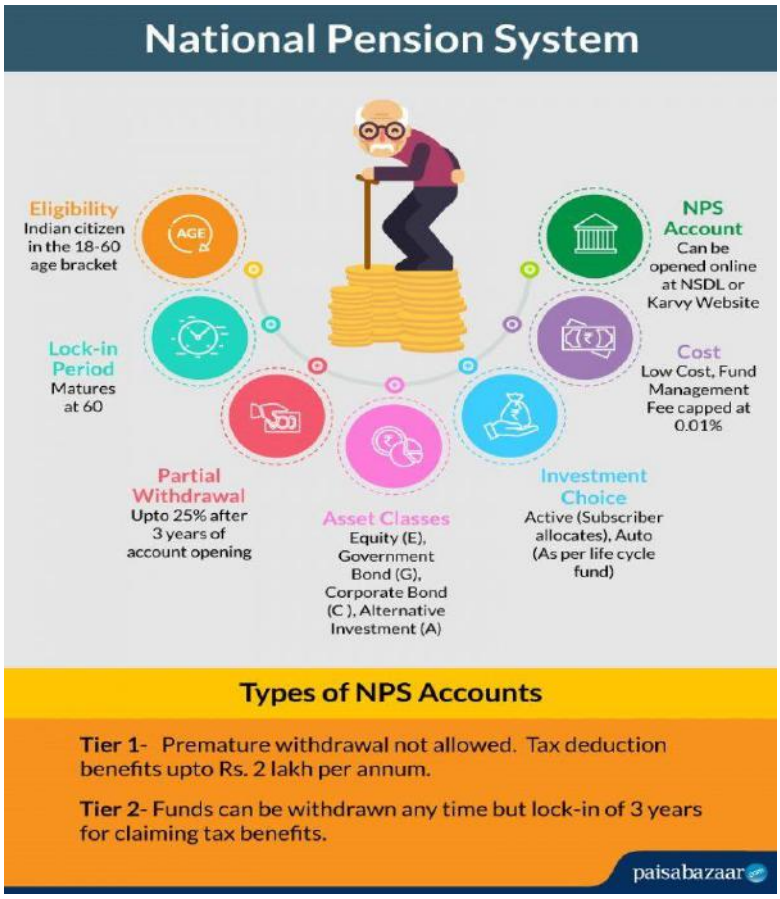

IMAGE SOURCE: NPS: National Pension Schemes Eligibility, Types, Calculator (paisabazaar.com)

- NPS एक सरकार प्रायोजित पेंशन योजना है, जिसे 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया और 2009 में इसे सभी वर्गों के लिए ओपन किया गया था।

कार्यान्वयन और विनियमन एजेंसी:

- PFRDA (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) - PFRDA अधिनियम, 2013 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

पात्रता:-

- एनपीएस में 18 से 60 वर्ष के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक (निवासी और अनिवासी दोनों) शामिल हो सकता है।
- इसमें एक शर्त यह है कि व्यक्ति को अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों का पालन करना होगा।
- पात्र न होना: इसमें ओसीआई (भारत के विदेशी नागरिक) और पीआईओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) कार्डधारक तथा हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) पात्र नहीं हो सकते है।

एनपीएस के लाभ:-

- एनपीएस एक पारदर्शी और लागत प्रभावी है।
- यह पोर्टेबल है - प्रत्येक कर्मचारी की पहचान एक अद्वितीय नंबर से होती है और उसके पास एक अलग स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) होता है जो पोर्टेबल होता है यानी, अगर कोई कर्मचारी किसी अन्य कार्यालय में स्थानांतरित हो जाता है तो भी वही रहेगा।

- यह विनियमित है - एनपीएस को पीएफआरडीए द्वारा विनियमित किया जाता है।

अवश्य पढ़ें: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)

SOURCE: TIMES NOW

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB)

संदर्भ: हाल ही में, वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में मल्टी-फंक्शन क्रिप्टो-परिसंपत्ति मध्यस्थों (एमसीआई) से जुड़े जोखिमों का आकलन किया।

पृष्ठभूमि:-

- क्रिप्टो-परिसंपत्ति मध्यस्थों पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की नवीनतम रिपोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों के बीच सीमा पार सहयोग और सूचना साझा करने के लिए उपायों की मांग की।

इसके बारे में

- स्थापना: यह अप्रैल 2009 में लंदन में जी 20 शिखर सम्मेलन के बाद वित्तीय स्थिरता मंच के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था।
- मुख्यालय: बेसल, स्विट्जरलैंड।
- इस बोर्ड में सभी G20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।
- FSB एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली के बारे में सिफारिश और मॉनिटर करता है।
- सदस्य: FSB में 68 सदस्य संस्थान शामिल हैं।
  - इसमें कई केंद्रीय बैंक, वित्त के मंत्रालय, और 25 न्यायालयों से पर्यवेक्षी तथा नियामक अधिकारियों के साथ -साथ 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं छह क्षेत्रीय परामर्शदाता समूह (आरसीजी) शामिल हैं।
  - भारत FSB का एक सक्रिय सदस्य है, जिसमें सचिव (आर्थिक मामलों के विभाग), उप-गवर्नर-आरबीआई तथा अध्यक्ष-सेबी द्वारा प्रतिनिधित्व की गई अपनी पूर्णता में तीन सीटें हैं।
  - एफएसबी के फैसले कानूनी रूप से इसके सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं।

उद्देश्य:-

- वैश्विक वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने वाली कमजोरियों का आकलन करने के साथ-साथ एक मैक्रो-प्रूडेंशियल परिप्रेक्ष्य के भीतर समय पर और चल रहे आधार पर, इन कमजोरियों और उनके परिणामों को संबोधित करने के लिए आवश्यक नियामक, पर्यवेक्षी और संबंधित कार्यों की पहचान और समीक्षा करना।
- वित्तीय स्थिरता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के बीच समन्वय और सूचना विनिमय को बढ़ावा देना।

मॉनिटर और सलाह

- बाजार के विकास और नियामक नीति के लिए उनके निहितार्थ।
- विनियामक मानकों को पूरा करने में सर्वोत्तम अभ्यास।

कार्य:-

- यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है और दुनिया की वित्तीय प्रणाली को मजबूत करता है।
- यह क्षेत्रों और न्यायालयों में नीतियों के सुसंगत कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करके एक स्तर के कार्य को बढ़ावा देता है।

मल्टीफ़ंक्शन क्रिप्टो-परिसंपत्ति मध्यस्थों (MCI) के बारे में:-

- MCI व्यक्तिगत फर्म हैं, या संबद्ध फर्मों का समूह हैं, जो क्रिप्टो-एसेट सेवाओं, उत्पादों और कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को जोड़ते हैं, यह आमतौर पर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के संचालन पर केंद्रित होते हैं।
- यह आम तौर पर कई सेवाओं को जोड़ती है, जिसमें विनिमय, ब्रोकरेज, डीलिंग, मार्केट-मेकिंग, हिरासत, क्लीयरिंग और एसेट मैनेजमेंट गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं; तथाकथित स्टैबेलोइन सहित क्रिप्टो-एएसटी को जारी करना, बढ़ावा देना और वितरण करना शामिल है।
- इसके अतिरिक्त, कुछ MCI में पर्याप्त मालिकाना व्यापार और निवेश कार्य हैं।

संरचना:-

- वे एक वैश्विक वेबसाइट का उपयोग करके अपने प्लेटफार्मों का संचालन करते हैं जो सेवाओं के लिए एक प्राथमिक प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है।
- कुछ ने अपने मुख्य संचालन से अलग कानूनी संरचनाओं के साथ अपने प्लेटफार्मों के देश-विशिष्ट स्थानीय संस्करण बनाने के लिए चुना है।
- कुछ MCI स्थानीय सहायक कंपनियों को भी स्थापित करते हैं, जो घरेलू निवासियों को क्रिप्टो-परिसंपत्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए कुछ स्तर की नियामक अनुमति प्राप्त कर सकते हैं, हालाँकि अभी भी वैश्विक मंच से जुड़ रहे हैं।

शासन:-

- MCI आमतौर पर अपने आंतरिक शासन का खुलासा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे मजबूत संकेत हैं जो स्वतंत्र और मजबूत जोखिम प्रबंधन कार्यों की कमी है।

MCI की कमजोरियां:-

- **लीवरेज:** MCI अपने स्वयं के ट्रेडिंग प्लेटफार्मों पर मालिकाना व्यापार या बाजार-निर्माण में संलग्न होने से उत्तोलन के निर्माण को बढ़ा सकता है।
- **लिक्विडिटी मिसमैच:** MCI निवेश कार्यक्रम, जिसमें स्टेकिंग-एज-ए-सर्विस और यील्ड/कमाई कार्यक्रम शामिल हैं, लिक्विडिटी बेमेल बनाते हैं।
- **तकनीकी और परिचालन कमजोरियां:** MCI कई तकनीकी और परिचालन कमजोरियों के लिए अतिसंवेदनशील हैं।

मस्ट रीड: क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन

SOURCE: THE HINDU

भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान (IICA)

संदर्भ: हाल ही में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (IICA) 'रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट 2023 पर राष्ट्रीय सम्मेलन' आयोजित करेगा।

पृष्ठभूमि:-

- IICA 14 और 15 दिसंबर 2023 को 'जिम्मेदार व्यवसाय आचरण 2023: भारत में ईएसजी को अपनाना' पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) के बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 2008 में
- मंत्रालय: कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय
- वर्ष 2008 में IICA को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- यह एक स्वायत्त संस्थान है।
- यह अनुसंधान, शिक्षा और वकालत के अवसर प्रदान करने का कार्य करता है।
- यह एक थिंक टैंक भी है जो नीति निर्माताओं, नियामकों के साथ-साथ कॉर्पोरेट मामलों के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य हितधारकों के लिए डेटा और ज्ञान का भंडार तैयार करता है।
- उद्देश्य: भारत में सभी कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में लगातार सुधार करना है।

अवश्य पढ़ें: दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020

SOURCE: PIB

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023

संदर्भ: हाल ही में, भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 7वें स्थान पर है।

पृष्ठभूमि:-

- भारत पिछले से एक स्थान ऊपर है और सर्वोच्च प्रदर्शन करने वालों में भी बना हुआ है।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) के बारे में:-

- जर्मनी स्थित जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा 2005 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।
- **उद्देश्य:** अंतरराष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाना और अलग-अलग देशों द्वारा किए गए जलवायु संरक्षण प्रयासों एवं प्रगति की तुलना करके संभव बनाना।
- CCPI 59 देशों (जिनमें से वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 92% हिस्सा है) और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी साधन है।
- जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन चार श्रेणियों में किया जाता है:
    - GHG उत्सर्जन (कुल स्कोर का 40%),
    - नवीकरणीय ऊर्जा (कुल स्कोर का 20%),
    - ऊर्जा उपयोग (कुल स्कोर का 20%) और
    - जलवायु नीति (कुल स्कोर का 20%)।

मुख्य विचार:-

- डेनमार्क ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा, एस्टोनिया और फिलीपींस ने दूसरे और तीसरे स्थान पर है।
- सऊदी अरब सबसे निचले 67वें स्थान पर है।
- मेजबान देश संयुक्त अरब अमीरात 65वें स्थान पर है।

भारत का प्रदर्शन:-

- सूचकांक में कहा गया है कि हालांकि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है।
- भारत की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतें अभी भी तेल और गैस के साथ-साथ कोयले पर भारी निर्भरता से पूरी हो रही हैं।
- **सुझाव:-**
  - नीतियां काफी हद तक शमनकारी हैं, फिर भी उन्हें परिवर्तनकारी अनुकूलन और आपदा जोखिम प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
  - नीति निर्माताओं को पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित समाधान भी अपनाना और समानता पर विचार करना चाहिए।

अवश्य पढ़ें: जलवायु परिवर्तन को कम करना

स्रोत: इंडिया टुडे

एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETFS)

संदर्भ: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अक्टूबर तक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में 27,105 करोड़ रुपये का निवेश किया है, संसद को हाल ही में सूचित किया गया।

पृष्ठभूमि:-

- श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ईटीएफ में 53,081 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जो 2021-22 के 43,568 करोड़ रुपये से अधिक है।

एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को समझना

- ईटीएफ इक्विटी या बांड जैसे निवेशों का संग्रह हैं।
- ये विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में बड़े पैमाने पर निवेश की अनुमति देते हैं।
- ईटीएफ में अक्सर सस्ती फीस होती है और अधिक आसानी से व्यापार किया जाता है।
- ईटीएफ सभी के लिए एक आकार में फिट होने वाला समाधान नहीं है।

ईटीएफ के लाभ:

- व्यापार करना आसान, कर कुशल और विविध निवेश पोर्टफोलियो की पेशकश।
- यह सावधानीपूर्वक चयनित स्टॉक के साथ एक विविध पोर्टफोलियो प्रदान करता है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से किसी भी समय तरलता प्रदान करता है।

ईटीएफ के जोखिम:

- ट्रेडिंग लागत: मामूली निवेशकों के लिए नो-लोड फंड कम महंगे हो सकते हैं।
- बाजार जोखिम: बाजार में उतार-चढ़ाव और अस्थिरता के अधीन।
- तरलता जोखिम: यह कम व्यापार मात्रा या व्यापक बिड-आस्क का प्रसार तरलता और कीमत को प्रभावित कर सकता है।
- नियामक जोखिम: यह बदलते कानूनों और विनियमों के अधीन होता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का अवलोकन

- यह भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन होता है।
- यह दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है।
- 15 नवंबर 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश के साथ स्थापित किया गया।
- कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 द्वारा प्रतिस्थापित है।
- वर्ष 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के रूप में पेश किया गया।

ईपीएफओ योजनाएं

- ईपीएफ योजना 1952: यह सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर संचय प्लस ब्याज प्रदान करती है।
- पेंशन योजना 1995 (ईपीएस): यह सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति, विकलांगता, उत्तरजीवी, विधवा और बच्चों के लिए मासिक लाभ प्रदान करती

है।

- बीमा योजना 1976 (ईडीएलआई): कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में लाभ प्रदान करती है।
    - अधिकतम लाभ 6 लाख है।

अवश्य पढ़ें: वैकल्पिक निवेश कोष और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप

SOURCE: THE ECONOMIC TIMES

सोशल स्टॉक एक्सचेंज

संदर्भ: हाल ही में उन्नति (Unnati) सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई बनी।

पृष्ठभूमि:-

- NSE SSE के साथ 38 और एनपीओ पंजीकृत हैं, और अगले कुछ महीनों में और अधिक लिस्टिंग हो सकती हैं।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में:-

- यह निवेशकों के लिए चुनिंदा सामाजिक उद्यमों या पहलों में निवेश करने का एक मंच है।
- मौजूदा स्टॉक एक्सचेंजों के अंदर एक अलग खंड के रूप में कार्य करता है।
- सोशल एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म (SEIP) को 2019-20 में केंद्रीय बजट द्वारा प्रस्तावित किया गया था और वर्ष 2019 में इशात हुसैन की अध्यक्षता में SEBI द्वारा इसका निर्माण किया गया था।

मुख्य विशेषताएं:

- यह अधिक पूंजी लगाकर निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्र के प्रदाताओं को सेवा प्रदान करता है।
- खुदरा निवेशक केवल लाभकारी सामाजिक उद्यमों द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूतियों में ही निवेश कर सकते हैं।
- संस्थागत और गैर-संस्थागत निवेशक एसई द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं।

पात्रता:

- कोई भी गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ) या लाभकारी सामाजिक उद्यम (एफपीएसई) जो सामाजिक इरादे की प्रधानता स्थापित करता है, उसे एक सामाजिक उद्यम (एसई) के रूप में मान्यता दी जाएगी, जो इसे एसएसई पर पंजीकृत या सूचीबद्ध होने के योग्य बनाएगा।
- एनपीओ निजी प्लेसमेंट या सार्वजनिक निर्गम से जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (जेडसीजेडपी) उपकरण जारी करके या म्यूचुअल फंड से डोनेशन के माध्यम से धन जुटाते हैं।

जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (ZCZP) उपकरणों के बारे में:

- ये एनपीओ द्वारा जारी किए जाते हैं, जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के एसएसई सेगमेंट के साथ पंजीकृत होते हैं।
- वित्त मंत्रालय ने प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 के प्रयोजनों के लिए ZCZP को प्रतिभूतियों के रूप में घोषित किया है।
- ये उपकरण SEBI द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे।

जीरो-कूपन बांड के बारे में

- इसमें कोई ब्याज नहीं है, भारी छूट पर व्यापार होगा।
- इसमें निवेशक का रिटर्न खरीद मूल्य और सममूल्य के बीच अंतर से दर्शाया जाता है।

अवश्य पढ़ें: गैर-लाभकारी संगठनों को सोशल स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने की अनुमति देने की सिफारिश करना

SOURCE: BUISINESSLINE

सरेंडर वैल्यू

संदर्भ: हाल ही में, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा एक परामर्श पत्र में जीवन बीमा कंपनियों के लिए उच्च समर्पण मूल्य और कम शुल्क का प्रस्ताव देने के बाद बीमा शेयरों में 5 प्रतिशत तक की गिरावट आई।

पृष्ठभूमि:-

- बीमा नियामक द्वारा जारी एक एक्सपोज़र ड्राफ्ट में विशेष रूप से गैर-भागीदारी वाले बीमा उत्पादों के लिए समर्पण मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि की वकालत की गई है।
- सरेंडर शुल्क की गणना के लिए कुछ संशोधनों का सुझाव दिया गया है।

इसके बारे में:-

- सरेंडर - यह पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता से पहले या बीमित घटना के घटित होने से पहले स्वैच्छिक समापन को इंगित करता है।
    - यह किसी भी लागू शुल्क या फीस को घटाकर भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का एक प्रतिशत है।

- लागू: यह सरेंडर लाभ के साथ टर्म बीमा पॉलिसियां के साथ लागू होता है।
- IRDAI टर्म प्लान धारकों को अपनी बीमा पॉलिसी सरेंडर करने की अनुमति देता है।
    - सरेंडर मूल्य भुगतान पॉलिसी प्रभावी होने के तीन साल बाद ही उपलब्ध होता है।
- मौजूदा मानदंडों के अनुसार, पॉलिसी सरेंडर अवधि के दौरान कभी भी हो सकती है, बशर्ते कि पूरे दो वर्षों के प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।
    - पहले वर्ष में, आईआरडीएआई पॉलिसीधारक को समायोजित सरेंडर वैल्यू की पेशकश करने का प्रस्ताव करता है।

भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के बारे में:-

- नोडल मंत्रालय: वित्त मंत्रालय
- मुख्य कार्यालय: हैदराबाद
- यह आईआरडीए अधिनियम 1999 के तहत स्थापित एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है।
- **उद्देश्य:** इसमें पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना, भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करना, बढ़ावा देना और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना शामिल है।
- **संरचना:** IRDAI भारत सरकार द्वारा नियुक्त 10 सदस्यीय निकाय है।
    - इसमें एक अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक सदस्य और चार अंशकालिक सदस्य होते हैं।
- **कार्य:-**
    - बीमा उद्योग का उचित विनियमन।
    - बीमा कंपनियों की विनियामक निगरानी।
    - पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा करना।
    - बीमा मध्यस्थों के लिए लाइसेंसिंग और मानदंड।

अवश्य पढ़ें: प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT)

लीड्स रिपोर्ट 2023

संदर्भ: हाल ही में LEADS रिपोर्ट 2023 जारी की गई।

पृष्ठभूमि:-

- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने 16 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में "विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस (LEADS) 2023" रिपोर्ट जारी की।
- तमिलनाडु ने विभिन्न राज्य (LEADS) 2023 रैंकिंग में लॉजिस्टिक्स सुगमता में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।

लीड्स रिपोर्ट के बारे में:-

- लॉन्च: वर्ष 2018 में
- मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- लॉन्च किया गया: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और डेलॉइट
- यह राज्यों को उनकी रसद सेवाओं और सड़क, रेल और गोदाम जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे की दक्षता, गुणवत्ता और क्षमता के आधार पर रैंक करता है जो आर्थिक विकास का संकेतक हैं।

लीड्स रिपोर्ट 2023 की मुख्य विशेषताएं:-

- LEADS वार्षिक अभ्यास के 5वें संस्करण ने प्रमुख स्तंभों - लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज और ऑपरेटिंग एवं नियामक पर्यावरण - में राज्यों के प्रदर्शन में सकारात्मक बदलाव का संकेत दिया।
- यह रिपोर्ट मई और जुलाई 2023 के बीच 36 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करते हुए आयोजित अखिल भारतीय प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित है।

प्रदर्शन की मुख्य बातें:

तटीय समूह

- उपलब्धियां: आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु
- फास्ट मूवर्स: केरल, महाराष्ट्र

- आकांक्षी (Aspirers): गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल

लैंडलॉक्ड ग्रुप

- उपलब्धियां: हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश
- फास्ट मूवर्स: मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड
- आकांक्षी: बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड

उत्तर-पूर्व समूह

- उपलब्धियां: असम, सिक्किम, त्रिपुरा
- फास्ट मूवर्स: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड
- आकांक्षी: मणिपुर, मेघालय, मिजोरम

केंद्र शासित प्रदेश

- उपलब्धियां: चंडीगढ़, दिल्ली
- फास्ट मूवर्स: अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी
- आकांक्षी: दमन और दीव/दादरा एवं नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख

अवश्य पढ़ें: लीड्स रिपोर्ट 2021

SOURCE: FINANCIAL EXPRESS

सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT)

संदर्भ: सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने हाल ही में, इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में फ्यूचर रिटेल के चेयरपर्सन किशोर बियानी और कुछ अन्य प्रमोटरों को सिक्योरिटीज मार्केट से एक साल के लिए प्रतिबंधित करने वाले नियामक सेबी के आदेश को रद्द कर दिया।

पृष्ठभूमि:-

- सेबी के आदेश को खारिज करते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि इकाइयों ने डीमर्जर से संबंधित अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) के आधार पर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के शेयरों में व्यापार नहीं किया क्योंकि ऐसी जानकारी पहले से ही कई मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में थी।

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) के बारे में:-

- स्थापित: वर्ष 2014 में
- मुख्यालय: मुंबई
- यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है।
- यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- उद्देश्य: सेबी या अधिनियम के तहत एक निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई और निपटान करना। इसमें वही शक्तियाँ हैं जो सिविल न्यायालय में निहित हैं।
- इसके अलावा, SAT निम्नलिखित द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील सुनता है और उनका निपटान करता है:-
  - पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)।
  - बीमा अधिनियम, 1938 के तहत भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई),
  - सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और
  - बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999
- संरचना: इसमें एक पीठासीन अधिकारी और दो अन्य सदस्य होते हैं।
- अपील: यदि कोई व्यक्ति SAT के निर्णय या आदेश से व्यथित महसूस करता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

अवश्य पढ़ें: (सेबी) ने कृषि वस्तुओं पर व्यापार प्रतिबंध बढ़ाया

SOURCE: THE ECONOMICS TIMES

उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0

संदर्भ: हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0 का उद्घाटन किया गया।

पृष्ठभूमि:-

- भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को बदलने के लिए अगस्त 2019 में संसद द्वारा पारित

किया गया था।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0 के बारे में:-

- लॉन्च: वर्ष 2023 में
- मंत्रालय: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
- उद्देश्य: भारतीय उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए टेलीफोनिक सलाह, सूचना और मार्गदर्शन प्रदान करना और व्यवसायों को विश्व स्तरीय मानकों को अपनाते हुए उपभोक्ता चिंताओं और शिकायतों को दूर करने के लिए अपनी नीति और प्रबंधन प्रणालियों को फिर से तैयार करने के लिए राजी करना।

मुख्य विशेषताएं:-

- मामला पंजीकरण और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले के स्तर पर किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0 एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के रूप में कार्य करता है।
- यह 17 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है।

एनसीएच के लाभ:-

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन निम्नलिखित द्वारा उपभोक्ताओं की सहायता करती है:-

- कंपनियों और नियामक प्राधिकरणों से संबंधित जानकारी प्रदान करना।
- डिफ़ॉल्टर सेवा प्रदाताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करना।
- उपभोक्ताओं को उपलब्ध उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाना, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करना।

अवश्य पढ़ें: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)

SOURCE: PIB

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA)

संदर्भ: हाल ही में, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) क्यूआर कोड की सुविधा के माध्यम से अपना योगदान जमा करने की अनुमति दी है।

पृष्ठभूमि:-

- D-रेमिट के लिए क्यूआर कोड - यूपीआई की शुरूआत एनपीएस योगदान को अधिक सुलभ, कुशल और लचीला बनाने की दिशा में एक सकारात्मक और क्रांतिकारी कदम है।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के बारे में:-

- स्थापित: वर्ष 2003 में
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- मंत्रालय: वित्त मंत्रालय
- उद्देश्य: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की देखरेख करना, और भारत के पेंशन क्षेत्र को विनियमित करना।
- पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 के पारित होने के साथ अंतरिम पीएफआरडीए पीएफआरडीए में परिवर्तित हो गया।
- इसमें एक अध्यक्ष और छह से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, जिनमें से कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होते है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

कार्य:-

- सेवानिवृत्त व्यक्तियों की ओल्ड ऐज फाइनेंसियल आवश्यकताओं को सुरक्षित करने के लिए पेंशन योजनाओं को बढ़ावा देना।
- पीएफआरडीए अधिनियम (एनपीएस और अटल पेंशन योजना) के तहत पेंशन योजनाओं का विनियमन।
- टियर-1 और टियर-2 खातों का संचालन और पर्यवेक्षण करना।
- सेंट्रल रिकॉर्ड-कीपिंग एजेंसी (सीआरए), पेंशन फंड मैनेजर आदि जैसे मध्यस्थों का पंजीकरण और विनियमन।
- शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना।
- विनियमित परिसंपत्तियों का विनियमन।

अवश्य पढ़ें: पुरानी पेंशन बनाम नई पेंशन योजना (NPS)

SOURCE: PIB

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA)

संदर्भ: हाल ही में, प्रधान मंत्री ने इन्फिनिटी फोरम 2.0 में अपने भाषण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को सतत वित्त का वैश्विक केंद्र बनाने पर जोर दिया।

पृष्ठभूमि:-

- IFSCA ने भारत और अन्य विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई की दिशा में पूंजी प्रवाह को सुविधाजनक बनाने हेतु IFSC में वित्तीय उपकरणों के विकास के लिए कई नियामक पहल की हैं।

इसके बारे में:-

- स्थापित: अप्रैल 2020 में
- मुख्यालय: गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात
- यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 ("आईएफएससीए अधिनियम") के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।
- उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों ('आईएफएससी') में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करना।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- IFSCA की स्थापना से पहले, घरेलू वित्तीय नियामक, अर्थात् RBI, SEBI, PFRDA और IRDAI, IFSC में व्यवसाय को विनियमित करते थे।
- GIFT-IFSC भारत का पहला IFSC है।

मुख्य विशेषताएं:-

- इसका मुख्य उद्देश्य एक मजबूत वैश्विक संबंध विकसित करना है।
- इसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र के भीतर अंतर-नियामक समन्वय सुनिश्चित करना भी है।
- IFSCA की संरचना: इसमें 09 सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

इन्फिनिटी फोरम 2.0 के बारे में:-

- मेजबानी: आईएफएससीए और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी, गिफ्ट सिटी।
- थीम 'गिफ्ट-आईएफएससी: न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए नर्व सेंटर।
- इन्फिनिटी फोरम वित्तीय सेवाओं पर एक वैश्विक विचार नेतृत्व प्लेटफॉर्म है।

अवश्य पढ़ें: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)

SOURCE: PIB

कार्ड-ऑन-फ़ाइल टोकननाइजेशन (COFT)

संदर्भ: हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्ड जारी करने वाले बैंकों और संस्थानों के माध्यम से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (CoFT) को सक्षम किया है।

पृष्ठभूमि:-

- यह डिजिटल भुगतान को अधिक सिक्योर, सेफ और सुदृढ़ बनाना है।

इसके बारे में:-

- केंद्रीय बैंक ने CoFT को वर्ष 2022 में लागू किया।
- **उद्देश्य:** कार्डधारकों के लिए टोकन बनाने और उन्हें ई-कॉमर्स एप्लिकेशन के साथ अपने मौजूदा खातों से जोड़ने की सुविधा बढ़ाना।
- टोकनाइजेशन वास्तविक क्रेडिट और डेबिट कार्ड विवरण को "टोकन" नामक एक वैकल्पिक कोड के साथ प्रतिस्थापित करना है, जो कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के संयोजन के लिए अद्वितीय होगा।
- **महत्व:** इस कदम से कार्डधारकों के मौजूदा खातों में ई-कॉमर्स अनुप्रयोगों के साथ टोकन बनाने और जोड़ने की सुविधा मिलेगी।

टोकनाइजेशन के लाभ:-

- बचाव और सुरक्षा में वृद्धि

- तीव्र चेकआउट
- नो मोर 'फॉल्स डिक्लाइन'
- आसान कार्ड प्रबंधन

अवश्य पढ़ें: डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC)

SOURCE: **BUSINESS STANDARD**

भूगोल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

संदर्भ: हाल ही में, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है।

पृष्ठभूमि:-

- इसने तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की भी भविष्यवाणी की है।

इसके बारे में:-

- स्थापित: वर्ष 1875 में
- मंत्रालय: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- आईएमडी मुख्यालय: नई दिल्ली
- यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है।

उद्देश्य:-

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात, नॉर्थवेस्टर, धूल भरी आँधी, भारी बारिश और बर्फ, ठंड तथा ग्रीष्म लहरें आदि जैसी गंभीर मौसम की घटनाओं, जो जीवन एवं संपत्ति के विनाश का कारण बनती हैं, के प्रति चेतावनी देना।
- मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों में अनुसंधान का संचालन एवं प्रचार करना।
- कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, उद्योगों, तेल की खोज और अन्य राष्ट्र-निर्माण गतिविधियों के लिये आवश्यक मौसम संबंधी आँकड़े प्रदान करना।

आईएमडी 4 रंग कोड का उपयोग करता है:-

- हरा (सब ठीक है): कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है।
- पीला (सावधान रहें): पीला रंग कई दिनों तक चलने वाले गंभीर रूप से खराब मौसम का संकेत देता है।
- ऑरेंज/एम्बर (तैयार रहें): ऑरेंज अलर्ट बेहद खराब मौसम की चेतावनी के रूप में जारी किया जाता है।
- रेड (कार्रवाई करें): जब बेहद खराब मौसम की स्थिति निश्चित रूप से परिवहन और बिजली को बाधित करने वाली होती है और जीवन के लिए महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न करती है, तो रेड अलर्ट जारी किया जाता है।

MUST READ: **The India Meteorological Department (IMD) may introduce new monsoon models**

SOURCE: **AIR**

माउंट मरापी

सन्दर्भ: हाल ही में माउंट मारापी ज्वालामुखी फट गया।

पृष्ठभूमि:-

- इंडोनेशिया में माउंट मरापी (फायर ऑफ़ माउंट) में विस्फोट हुआ, जिसमें 23 लोग मारे गए।

माउंट मरापी के बारे में:-

- स्थान: पश्चिम सुमात्रा, इंडोनेशिया (प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित)।
- मेरापी एक स्ट्रैटोवोलकानो है, जो दो जावानीस शब्दों का संयोजन है: "मेरु" जिसका अर्थ है "पर्वत" और "एपि" जिसका अर्थ है "आग"।
- माउंट मेरापी एक सबडक्शन क्षेत्र पर स्थित है जहां इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है।
- मेरापी दक्षिणी जावा का सबसे नया ज्वालामुखी है।
- यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भी है।

अवश्य पढ़ें: माउंट मौना लोआ

SOURCE: **INDIA TODAY**

कंबलाकोंडा वन्यजीव अभयारण्य

संदर्भ: हाल ही में, कंबलाकोंडा वन्यजीव अभयारण्य की परिधि पर स्थित अपनी तरह का पहला पूर्वी घाट नेचर इंटरप्रेटेशन सेंटर खोला गया।

पृष्ठभूमि:-

- नया नेचर इंटरप्रेटेशन सेंटर, पीएम पालेम के पास हाल ही में उद्घाटन किए गए पूर्वी घाट जैव विविधता केंद्र में एक अलग खंड, इस क्षेत्र के

विविध पारिस्थितिक तंत्रों के माध्यम से घूमने का एक गहन अनुभव है जो लंबे समय से व्यवस्थित दस्तावेज़ीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है।

इस अभयारण्य के बारे में:-

- स्थान: यह विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में है। इस अभयारण्य का नाम स्थानीय पहाड़ी, कम्बलकोंडा से लिया गया है।
- वनस्पति: शुष्क सदाबहार वन और झाड़ियाँ।
- इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत 1970 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था।

जैव विविधता:-

- यह भारतीय तेंदुओं, हिरण प्रजातियों, जंगली सूअर, सियार, सरीसृप, पक्षियों और औषधीय पौधों का घर है।
- वनस्पति: मुख्य रूप से नम पर्णपाती पैच वाले शुष्क सदाबहार वन।
- जीव-जंतु: सूचक प्रजाति भारतीय तेंदुआ है। यहां पाई जाने वाली अन्य प्रजातियां इंडियन क्लाउडेड गेको, बुलबुल, बार्बेट्स, कोयल, फ्लाईकैचर, हॉर्नबिल और लीफबर्ड, स्टारलिंग हैं।

अवश्य पढ़ें: कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य (KWS)

SOURCE: THE HINDU

इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान (IGZP)

संदर्भ: हाल ही में, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान (IGZP) को पशु विनिमय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वारंगल चिड़ियाघर से दो नई प्रजातियाँ मिलीं।

पृष्ठभूमि:-

- एक्सचेंज के हिस्से के रूप में, IGZP को माउस डियर और चौसिंगा (चार सींग वाला मृग) मिला।
- इसके बदले में, चिड़ियाघर हॉग हिरण, भौंकने वाले हिरण और लुटिनो पैराकीट्स को पाल रहा (sparing) है।

इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान (आईजीजेडपी) के बारे में:-

- स्थान: आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम जिला, सीताकोंडा रिजर्व फॉरेस्ट के बीच स्थित है।
- केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त एक बड़ी श्रेणी का चिड़ियाघर होने के नाते इसमें स्तनधारी, मांसाहारी, कम मांसाहारी, कैनिड्स, अनगुलेट्स, सरीसृप, पक्षी और तितलियों जैसे 843 जानवरों की 123 प्रजातियों को प्राकृतिक वातावरण में रखा गया है।
- कंबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य के निकट वन क्षेत्र में होने के कारण यह स्थान कई स्वतंत्र जानवरों और पक्षियों का भी घर है।

अवश्य पढ़ें: वन्यजीव संरक्षण

SOURCE: TIMES OF INDIA

वाल्मिकी टाइगर रिजर्व

संदर्भ: हाल के आंकड़ों के अनुसार, खनन प्रतिबंध सहित कम मानवीय गतिविधियों ने वाल्मिकी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाने में मदद की है।

पृष्ठभूमि:-

- बिहार के वाल्मिकी टाइगर रिजर्व (वीटीआर) के अधिकारियों ने संरक्षित क्षेत्र (पीए) में बड़ी बिल्लियों की संख्या में वृद्धि का श्रेय मानवीय गतिविधियों में कमी को दिया है, जिसमें इसके पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रतिबंध भी शामिल है।

वाल्मिकी टाइगर रिजर्व के बारे में:-

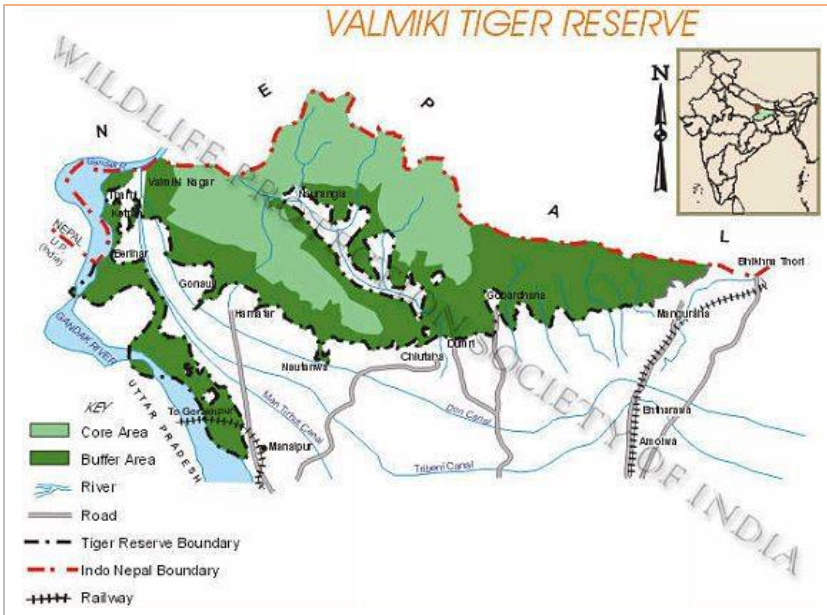

IMAGE SOURCE: wpsi-india.org

- स्थान: पश्चिमी चंपारण जिला, बिहार
- भारत में वाल्मिकी टाइगर रिजर्व हिमालय तराई जंगलों की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है।
- वाल्मिकी टाइगर रिजर्व के जंगलों में पाए जाने वाले जंगली स्तनधारियों में बाघ, स्लॉथ भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, बाइसन, जंगली सूअर आदि शामिल हैं।
- वनस्पति: वनस्पति प्रकारों में मुख्य रूप से नम मिश्रित पर्णपाती, खुली भूमि वाली वनस्पति, उप-पर्वतीय अर्ध-सदाबहार संरचना, मीठे पानी के दलदल, नदी के तट, जलोढ़ घास के मैदान, उच्च पहाड़ी सवाना और आर्द्रभूमि शामिल हैं।
- वर्ष 1978 में इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था।

अवश्य पढ़ें: काली टाइगर रिजर्व

SOURCE: DOWN TO EARTH

कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य

संदर्भ: हाल ही में उत्तर प्रदेश के कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य के पास हाथियों ने एक चौकीदार को कुचल कर मार डाला।

पृष्ठभूमि: अधिकारियों ने कहा कि कुछ लोगों को पीड़िता का क्षत-विक्षत शव जंगल की झाड़ियों में मिला।

कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य (KWS) के बारे में:-

- स्थान: यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसे 1987 में 'प्रोजेक्ट टाइगर' के दायरे में लाया गया था।
- इसके नाजुक तराई पारिस्थितिकी तंत्र में साल और सागौन के जंगल, हरे-भरे घास के मैदान, कई दलदल और आर्द्रभूमि का मिश्रण शामिल है।
- कतर्नियाघाट जंगल भारत में दुधवा और किशनपुर के बाघ आवासों और बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान (नेपाल) के बीच रणनीतिक कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इस अभयारण्य क्षेत्र में बहने वाली गैरवा नदी को मगर और घड़ियाल के लिए अभयारण्य घोषित किया गया है।
- यह भारत के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां गंगा डॉल्फ़िन (मीठे पानी की डॉल्फ़िन) अपने प्राकृतिक आवास में पाई जाती हैं।
- जीव-जंतु: बाघ, गैंडा, दलदली हिरण, हिस्पिड खरगोश, बंगाल फ्लोरिकन, सफेद पीठ और लंबी चोंच वाले गिद्ध सहित लुप्तप्राय प्रजातियाँ शामिल है।
- वनस्पति: इसके नाजुक तराई पारिस्थितिकी तंत्र में साल और सागौन के जंगल, हरे-भरे घास के मैदान, कई दलदल और आर्द्रभूमि शामिल हैं।

अवश्य पढ़ें: भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII)

SOURCE: HINDUSTAN TIMES

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

फार्लोविचनस रैपिडस

संदर्भ: हाल ही में, वैज्ञानिकों ने ब्राज़ील में पैरों के निशान से डायनासोर की एक नई प्रजाति, फ़ार्लोविचनस रैपिडस की खोज की।

पृष्ठभूमि:-

- शोधकर्ताओं के अनुसार, नई प्रजाति, जिसे फार्लोविचनस रैपिडस कहा जाता है जो कि एक आधुनिक सेरीमा पक्षी के आकार का या लगभग 2 से 3 फीट लंबा एक छोटा मांसाहारी जानवर हो सकता था।

इसके बारे में:-

- यह एक छोटा मांसाहारी जानवर था, यह रेगिस्तान में रहता था।
- पाए गए पैरों के निशानों के बीच की लम्बी दूरी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक बहुत तेज़ सरीसृप था जो प्राचीन टीलों के पार दौड़ता था।
- प्रारंभिक क्रेटेशियस काल (Cretaceous period) 100 से 145 मिलियन वर्ष पूर्व तक फैला था।

महत्व:-

- यह खोज न केवल प्राचीन रेगिस्तानी पारिस्थितिकी प्रणालियों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है।
- यह जीवाश्म अभिलेखों की निरंतर खोज और विश्लेषण के महत्व को भी रेखांकित करता है।

अवश्य पढ़ें: खारे पानी का मगरमच्छ

SOURCE: BBC

नुगु वन्यजीव अभयारण्य

संदर्भ: हाल ही में, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने अधिकारियों से सिफारिश की है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व से सटे नुगु वन्यजीव अभयारण्य को मुख्य महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान घोषित किया जाए।

पृष्ठभूमि:-

- इसके बाद सहायक वन महानिरीक्षक, एनटीसीए और सुश्री हरिनी वेणुगोपाल ने साइट का दौरा किया। यह यात्रा संरक्षण कार्यकर्ता गिरिधर कुलकर्णी द्वारा बांदीपुर से संबंधित कई मुद्दों को उठाने के बाद हुई।

नुगु वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:-

- **स्थान:** मैसूरु जिला, कर्नाटक।
- भौगोलिक क्षेत्र: वर्ष 1974 में नुगु को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और यह 30.32 वर्ग किमी में फैला है और 1000 मिमी वर्षा होती है।
- वनों में अधिकांश वनस्पति शुष्क, पर्णपाती, बीच-बीच में वृक्षारोपण के टुकड़ों से युक्त होती है।
- जहां तक मानव-हाथी संघर्ष का सवाल है, नुगु एक संवेदनशील क्षेत्र है।
- इसे वर्ष 2003-2004 में नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व में जोड़ा गया था।
- **वनस्पति:** एनोजीसस लैटिफोलिया, टेक्टोनिया ग्रैंडिस, टर्मिनलिया टोमेंटोसा आदि।
- **जीव-जंतु:** हाथी, तेंदुआ, जंगली बिल्लियाँ, जंगली सुअर, चित्तीदार हिरण, सांभर हिरण, भौंकने वाला हिरण, आदि।

अवश्य पढ़ें: तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य

SOURCE: THE HINDU

UNFCCC COP 28

संदर्भ: अनुकूलन कोष प्रमुख ने UNFCCC COP 28 में पर्याप्त धन नहीं मिलने पर चिंता व्यक्त की।

मुद्दे की पृष्ठभूमि:-

- अनुकूलन कोष, वैश्विक निकाय जो विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कमजोर समुदायों के लिए परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है।

- इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत की गई थी।
- यह उन परियोजनाओं और कार्यक्रमों को वित्तपोषित करता है जो विकासशील देशों में कमजोर समुदायों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनने में मदद करते हैं।

- चल रहे COP28 में इसे न्यूनतम आवश्यकता की तुलना में लगभग आधी धनराशि ही प्राप्त हुई है।
- मार्च में, अनुकूलन निधि बोर्ड ने गणना की है कि कम से कम $300 मिलियन की आवश्यकता है और उम्मीद है कि COP28 में निधि जुटाई जाएगी।
- लेकिन अभी तक, केवल लगभग 165 मिलियन डॉलर का ही वादा किया गया है।
- इससे पहले, अनौपचारिक परामर्श के दौरान, विकासशील देशों ने निराशा व्यक्त की थी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की वित्त पर स्थायी समिति अनुकूलन वित्त को दोगुना करने हेतु आधार रेखा पर पहुंचने में विफल रही थी।

COP28 के बारे में:-

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) की 28वीं बैठक।
- पार्टियों का सम्मेलन (सीओपी) निर्णय लेने वाली संस्था है।
- यह कन्वेंशन के कार्यान्वयन की समीक्षा और मार्गदर्शन करता है।
- 'पार्टियाँ' वे सरकारें हैं जिन्होंने UNFCCC पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यूएनएफसीसीसी 2015 पेरिस समझौते और 1997 क्योटो प्रोटोकॉल की मूल संधि है।
- सीओपी पांच संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूहों के बीच सीओपी अध्यक्ष के कार्यालय को रोटेट करता है।
- अपेक्षित फोकस: स्थायी ऊर्जा उत्पादन की ओर परिवर्तन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना।

COP28 के प्रमुख मुद्दे:-

- जलवायु उत्तरदायित्व में वैश्विक विभाजन: विकसित देश जलवायु कार्रवाई पर अत्यधिक बोझ महसूस करते हैं।
- 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य: यह जलवायु कार्रवाई में संसाधन और विश्वास की कमी को संबोधित करता है।
- पेरिस समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल: 'सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों' सिद्धांत को मान्यता देना।
- कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम): आयात की कार्बन सामग्री को घरेलू कीमतों के अनुरूप बनाना।
- अधूरी प्रतिबद्धता: विकसित देशों ने 2020 से जलवायु वित्त में $100 बिलियन का वादा किया।
- प्रगति: विकसित देशों से COP28 में इस वादे को पूरा करने का दावा करने की उम्मीद की जाती है, हालांकि जलवायु कार्रवाई के लिए आवश्यक खरबों की तुलना में यह अपर्याप्त है।
- **मुद्दा:** बड़ी चुनौती अगले साल से शुरू होने वाली सालाना 100 अरब डॉलर से अधिक की अतिरिक्त फंडिंग पर बातचीत करने में है।

MUST READ:COP 27: A field guide to climate jargon

SOURCE: DOWN TO EARTH

अंतरसरकारी वार्ता समिति (INC)

संदर्भ: हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत अंतर सरकारी वार्ता समिति (आईएनसी) की नैरोबी में बैठक हुई।

मुख्य विचार:-

- INC-3 प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण के लिए बातचीत में एक महत्वपूर्ण चरण था।
- UNEA संकल्प 5/14 के तहत, INC को 2025 तक एक वैश्विक प्लास्टिक संधि प्रदान करने का काम सौंपा गया है।
- समिति के सचिवालय द्वारा विकसित 'ज़ीरो ड्राफ्ट' टेक्स्ट में मुख्य दायित्वों और नियंत्रण उपायों के विकल्प शामिल थे।
- ज़ीरो ड्राफ्ट सभी स्तरों पर महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाली बातचीत के लिए एक प्रारंभिक बिंदु था: मजबूत, बाध्यकारी, मध्यम, लचीला, कमजोर और स्वैच्छिक।

अंतरसरकारी वार्ता समिति (आईएनसी) के बारे में:-

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 5वें सत्र में वर्ष 2022 में स्थापित किया गया।
- समुद्री प्रदूषण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण विकसित करने का लक्ष्य है।

- उपकरण में समुद्री, भूमि और जल प्लास्टिक प्रदूषण शामिल होना चाहिए और परिपत्र अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के माध्यम से स्थायी उत्पादन और खपत को बढ़ावा देना चाहिए।
- देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपकरण के उद्देश्यों में योगदान देने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाओं का विकास, कार्यान्वयन और अद्यतन करें।
- आईएनसी विभिन्न स्तरों पर प्लास्टिक उत्पादन की मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के साथ जुड़ती है।
- एक मजबूत वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए INC को IUCN द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

भारत में प्लास्टिक को कम करने के लिए शमन प्रयास:-

- भारत सरकार ने पर्यावरणीय हानि का कारण बनने वाली कुछ एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू किया है।
- राष्ट्रीय ढाँचे और नीतियाँ: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2016), प्लास्टिक कचरे को कम करने, पुनर्चक्रण को बढ़ाने और गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन, भारत के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की गलियों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को साफ करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जो प्लास्टिक कचरे को नगरपालिका ठोस कचरे के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में संबोधित करता है।
- **विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (EPR):** ईपीआर ढांचे के तहत, उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को उपभोक्ता के बाद के प्लास्टिक कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिससे पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे के रिसाव में कमी सुनिश्चित होती है।

अवश्य पढ़ें: प्रदूषण पर वैश्विक संधि

SOURCE: THE HINDU

भारतीय बाइसन

संदर्भ: हाल ही में, कोया जनजाति ने पूर्वी घाट के भारतीय बाइसन के संरक्षण में मदद करने के लिए पर्यावरण-अनुकूल वेव की सवारी की।

पृष्ठभूमि:-

- अपने जंगलों में भारतीय बाइसन को संरक्षित करने के एक कदम में, आंध्र प्रदेश में पापिकोंडा पहाड़ी श्रृंखला में रहने वाली स्वदेशी कोया जनजाति ने अपनी पारंपरिक बांसुरी, पर्माकोर बनाने के लिए बाइसन सींगों का उपयोग बंद करके और इसे पर्यावरण-अनुकूल ताड़ के पत्ते से बने एक उपकरण के साथ बदलकर एक अनुकरणीय परिवर्तन किया है।

इंडियन बाइसन के बारे में:-

- भारतीय बाइसन सबसे बड़े विद्यमान गोवंशों में से एक है। (भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII))
- यह जंगली मवेशियों में सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है, जिसकी कंधे की ऊंचाई 220 सेमी तक होती है।
- भारतीय गौर, एक एकान्तप्रिय जानवर है यह प्रायः जंगल में रहता है।
- ये दक्षिण से दक्षिण पूर्व एशिया की जंगली पहाड़ियों और घास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- भारत में ये नागरहोल, बांदीपुर, मासिनागुड़ी राष्ट्रीय उद्यान और बीआर हिल्स में पाए जाते हैं।

खतरा:-

- वनों की कटाई और वाणिज्यिक वृक्षारोपण के कारण भोजन की कमी, अवैध शिकार, आवास की हानि।

संरक्षण की स्थिति:-

- वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I
- प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) की लाल सूची: असुरक्षित।

कोया जनजाति के बारे में:-

- कोया आबादी मुख्य रूप से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पाई जाती है।
- वे कोया भाषा बोलते हैं, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है।
- ये पोडु प्रकार की झूम खेती करते हैं, जैसा कि वन क्षेत्रों में विभिन्न आदिवासी समूहों द्वारा किया जाता है, यह लंबे समय से आर्थिक अस्तित्व बनाम पर्यावरणीय जीविका का मुद्दा रहा है।
- छत्तीसगढ़ में एसटी का दर्जा प्राप्त है लेकिन तेलंगाना जैसे उनके विस्थापित राज्यों में उन्हें एसटी का दर्जा नहीं दिया गया।

- कोया लोग स्वयं को लोकप्रिय रूप से दोराला सत्तम (प्रभु समूह) और पुट्टा डोरा (मूल स्वामी) कहते हैं।
- गोदावरी और सबरी नदियाँ जो उनके निवास क्षेत्र से होकर बहती हैं, कोयाओं के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं।

अवश्य पढ़ें: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएजीआर) की नई नस्लें

SOURCE: THE HINDU

मेगामाउथ शार्क

संदर्भ: हाल ही में फिलीपींस के एक समुद्र तट पर पहली गर्भवती मेगामाउथ शार्क बहती हुई पाई गई थी।

पृष्ठभूमि:-

- इस 18 फुट की शार्क को फिलीपींस के अरोरा में खोजा गया था, और वह सात पप्स से गर्भवती थी जिन्हें उसके शरीर से बाहर निकाला गया।

मेगामाउथ शार्क के बारे में:-

- वैज्ञानिक नाम : मेगाचस्मा पेलागियोस
- इसे पहली बार वर्ष 1976 में हवाई के तट पर खोजा गया था।
- आकार: लंबाई 5.5 मीटर (18 फीट) तक।
- इनका बड़ा मुंह, बल्बनुमा सिर, रबरयुक्त होंठ और गहरे भूरे/काले शरीर के साथ पेट का निचला हिस्सा सफेद होता है।
- आहार: फ़िल्टर फीडर, प्लवक, जेलीफ़िश और छोटी मछली का सेवन।
- यह अपना मुंह चौड़ा करके तैरती है और प्लवक तथा जेलिफ़िश के लिए पानी फ़िलटर करती है। (जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम)
- इनके बड़े सिर और रबर जैसे होंठों से पहचाना जाता है।
- ये एक अपेक्षाकृत कमजोर तैराक, मेगामाउथ का शरीर नरम, पिलपिला होता है और इनमें दुम की कीलों का अभाव होता है।
- **संरक्षण स्थिति:-**आईयूसीएन: कम चिंतनीय।

अवश्य पढ़ें: जेब्राफिश

SOURCE: TIMES NOW

इंडियन टेंट टर्टल

संदर्भ: हाल ही में, DRI ने लखनऊ में 436 शिशु इंडियन टेंट टर्टल को बचाया।

पृष्ठभूमि:-

- राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), जोनल यूनिट, लखनऊ द्वारा विकसित विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से अंतरराज्यीय परिवहन कर रहे एक व्यक्ति से 436 बेबी इंडियन टेंट टर्टल जब्त किए गए।

इनके बारे में:-

- इन कछुओं का रंग भी प्रत्येक उपप्रजाति के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है।
- उप-प्रजाति टेंटोरिया में लाल पोस्टोकुलर स्पॉट के साथ एक ऑलिव या भूरा सिर होता है, पहले तीन कशेरुकाओं में एम्बर या हेज़ेल धारी के साथ कैरपेस भूरे रंग का होता है और प्लास्ट्रॉन काले धब्बों के साथ पीला होता है।
- यह एक अर्ध-जलीय प्रजाति जो मुख्य रूप से नदियों और संबंधित प्रणालियों में पाई जाती है।
- प्रजनन अण्डाकार होता है।
- वितरण:-
    - यह प्रजाति भारत, नेपाल और बांग्लादेश के मूल निवासी है, इस क्षेत्र से तीन उप-प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं, जैसे, पीटी टेंटोरिया, पीटी सर्कमडेटा और पीटी फ्लेविवेंटर। पीटी टेंटोरिया प्रायद्वीपीय भारत में होता है और उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश में दर्ज किया जाता है। पीटी सर्कमडेटा गंगा की पश्चिमी सहायक नदियों और गुजरात की नदियों में होता है।
- **खतरे:** नदी पर बांध बनाना, आवास का क्षरण।

संरक्षण की स्थिति:-

- IUCN: कम से कम चिंता का विषय

- IWPA: अनुसूची I
- CITES: परिशिष्ट II

अवश्य पढ़ें: राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना

SOURCE: PIB

एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीसवायरस उपप्रकार (EEHV)

संदर्भ: एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीसवायरस उपप्रकार (ईईएचवी) का हाल ही में किया गया अध्ययन निदान और उपचार विज्ञान के विकास में मदद करता है।

पृष्ठभूमि:-

- रोग-महामारी विज्ञान पर शोध या रोग के निर्धारकों, घटना और वितरण के अध्ययन से रोग के खिलाफ सीरो-डायग्नोस्टिक्स, टीके और उपचार विकसित करने में मदद मिल सकती है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबद्ध संस्थान, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) द्वारा समर्थित आईसीएआर-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (ICAR-IVRI), इज़्ज़तनगर, बरेली के अध्ययन से EEHV और इसकी सटीक स्थिति का पता चला है। इसके उपप्रकार भारत में एशियाई हाथियों की आबादी के बीच प्रचलित हैं।

एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीसवायरस उपप्रकार (ईईएचवी) के बारे में:-

- यह एक प्रकार का हर्पीसवायरस है जो युवा एशियाई हाथी में अत्यधिक घातक रक्तस्रावी बीमारी का कारण बन सकता है।
    - यह हर्पीसविरिडे परिवार से संबंधित है और विशेष रूप से हाथियों को प्रभावित करता है।
    - उपप्रकार: EEHV1A (युवा एशियाई हाथियों में सबसे आम और गंभीर बीमारी से जुड़ा हुआ), EEHV1B और EEHV2
- **ट्रांसमिशन:**
    - ईईएचवी मुख्य रूप से लार, रक्त या मूत्र जैसे संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क से फैलता है।
    - इसके अतिरिक्त, उपकरण और सतहों सहित दूषित वस्तुओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष संचरण, जोखिम उत्पन्न करता है।
    - हाथी की मृत्यु अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव और ऐसे लक्षणों से होती है जो मुश्किल से दिखाई देते हैं।

निदान:-

- शारीरिक तरल पदार्थों में वायरस का पता लगाने के लिए PCR परीक्षण, एंटीबॉडी की पहचान करने के लिए सीरोलॉजी और सूक्ष्म परीक्षण के लिए बायोप्सी।

इलाज:-

- वर्तमान में, EEHV-HD के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है।
- लक्षणों को कम करने और जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अंतःशिरा तरल पदार्थ, रक्त आधान आदि के माध्यम से सहायक देखभाल।

अवश्य पढ़ें: नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व में लुप्तप्राय एशियाई हाथी

SOURCE: PIB

कवल टाइगर रिजर्व

संदर्भ: हाल ही में कवल टाइगर रिजर्व स्मूथ-कोटेड ओटर के लिए स्वर्ग बन गया है।

पृष्ठभूमि:-

- ये जीव कदम नदी के किनारे, नहरों के बांधों पर और गोदावरी नदी के किनारों पर भी रहते हैं।

कवल टाइगर रिजर्व के बारे में:-

IMAGE SOURCE: adivasiresurgence.com

- स्थान: तेलंगाना
- कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना के उत्तर पूर्वी भाग में है।
- रिज़र्व गोदावरी नदी से घिरा हुआ है और कदम नदी (गोदावरी की एक सहायक नदी) इस क्षेत्र से होकर बहती है।
- कवल वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था।
- वनस्पति: दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन।
- फ़्लोरा: सागौन और बांस के स्टैंड, एनोजीसस लैटिफोलिया, मित्रागिना परविफ्लोरा, टर्मिनलिया क्रेनुलता, टर्मिनलिया अर्जुन, बोसवेलिया सेराटा, और कई अन्य।
- जीव-जंतु: नीलगाय, चौसिंगा, चिंकारा, काला हिरण, सांभर, चित्तीदार हिरण, जंगली कुत्ता, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, बाघ, तेंदुआ और जंगली बिल्ली आदि।

स्मूथ-कोटेड ओटर के बारे में:-

- स्मूथ-कोटेड ओटर की विशेषता यह है कि यह बहुत चिकना, चिकने पंख, मजबूत तैराक और समूहों में शिकार करता है।
- उनकी आंखें और कान छोटे होते हैं, पूंछ चपटी होती है, अंग छोटे और मजबूत होते हैं, और अगले और पिछले पंजे बड़े और अच्छी तरह से जाल वाले होते हैं।
- इन ऊदबिलावों को आम तौर पर मछली विशेषज्ञ के रूप में वर्णित किया गया है।
- यह तराई क्षेत्रों, तटीय मैंग्रोव जंगलों, पीट दलदली जंगलों, मीठे पानी की आर्द्रभूमियों, बड़ी जंगली नदियों, झीलों और चावल के खेतों में पाया जाता है।

खतरा:-

- बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण
- बस्तियों और कृषि के लिए आर्द्रभूमियों का रूपांतरण
- शिकार बायोमास में कमी
- अवैध शिकार और
- कीटनाशकों द्वारा जलमार्गों का संदूषण।
- संरक्षण स्थिति:-आईयूसीएन लाल सूची: असुरक्षित

अवश्य पढ़ें: वैश्विक संरक्षण आश्वासन|बाघ मानक (सीए|टीएस)

SOURCE: THE NEW INDIAN EXPRESS

पैन्टोइया टैगोरी

संदर्भ: हाल ही में, वैज्ञानिकों ने पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले एक जीवाणु पैन्टोइया टैगोरी की खोज की।

पृष्ठभूमि:-

- इसका नाम रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया था।

पेंटोइया टैगोरी के बारे में:-

- पैन्टोइया टैगोरी की खोज झरिया कोयला खदानों में एकत्र मिट्टी के नमूनों से की गई थी।
- बैक्टीरिया में पौधों की वृद्धि के लिए लाभकारी अद्वितीय गुण होते हैं।
- यह पोटेशियम और फॉस्फोरस को घुलनशील बनाता है और नाइट्रोजन की पूर्ति करता है जो पौधों के विकास में सहायता करने वाले गुणों को प्रदर्शित करता है।
- कोयला खदानों और उसके आसपास के किसानों को बैक्टीरिया से परिचित कराया गया है और उन्होंने सकारात्मक परिणामों पर संतुष्टि व्यक्त की है।

संभावित उपयोग:-

- यह पर्यावरण के अनुकूल और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इससे बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने में मदद मिल सकती है।
- यह जैविक खेती को बढ़ावा देता है।

अवश्य पढ़ें: काले मूंगों की नई प्रजाति

SOURCE: THE ECONOMIC TIMES

वैंग्स गार्डन छिपकली

संदर्भ: हाल ही में चीन में एक नई सरीसृप प्रजाति वैंग्स गार्डन लिज़र्ड की खोज की गई।

वैंग गार्डन छिपकली के बारे में:-

- वैज्ञानिक नाम : कैलोट्स वांगी।
- इस छिपकली का नाम कैलोट्स वांगी या वांग गार्डन छिपकली रखा गया है।
- इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर से कम है।
- इसकी जीभ नारंगी रंग की होती है जो इसे अलग पहचान देती है।
- यह नाम चेंग्दू इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के हर्पेटोलॉजी संग्रहालय के पूर्व निदेशक प्रोफेसर युएझाओ वांग को उनके योगदान के लिए सम्मानित करता है।
- यह रात में झुकी हुई झाड़ीदार शाखाओं पर रहती है और शाखाओं के करीब सोती है।
- यह विभिन्न प्रकार के कीड़े, मकड़ियों और अन्य आर्थ्रोपोड को खाती है। (वन्यजीव संरक्षण)
- यह हर साल अप्रैल से अक्टूबर तक सक्रिय रहती है, जबकि उष्ण कटिबंध में यह मार्च से नवंबर या उससे भी अधिक समय तक सक्रिय रहती है।

अवश्य पढ़ें: बंगाल मॉनिटर छिपकली

SOURCE: MSN

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

एचएच 1177 प्रणाली

संदर्भ: हाल ही में, पहली बार, खगोलविदों ने मिल्की वे आकाशगंगा के बाहर एक युवा तारे एचएच 1177 प्रणाली की झलक देखी।

पृष्ठभूमि:-

- इन परिस्थितिजन्य डिस्क वाले नवजात तारे अब तक खगोलविदों द्वारा केवल हमारी आकाशगंगा में ही देखे गए थे।

एचएच 1177 प्रणाली के बारे में:-

- यह एक रोटेटिंग डिस्क वाला एक विशाल तारा है, जिसे बड़े मैगेलैनिक क्लाउड में देखा गया था, जो एक पड़ोसी बौनी आकाशगंगा है जो लगभग 160,000 प्रकाश वर्ष दूर है।
- HH 1177 जैसा विशाल तारा तेजी से जीवित रहता है और कम समय में ही खत्म हो जाता है।
- यह छोटी समयरेखा हमारी आकाशगंगा में किसी विशाल तारे के शुरुआती चरणों का अवलोकन करना कठिन बना देती है।
- HH 1177 एक तारकीय नर्सरी के अंदर है, जिसे N180 कहा जाता है जिसमें कम धूल और कम धातु की प्रचुरता है।
- एक नवजात तारा अपने परिवेश से पदार्थ लेकर आकार में बढ़ता है।
- मजबूत गुरुत्वाकर्षण बलों के परिणामस्वरूप गैस और धूल तारे के चारों ओर एक सपाट डिस्क में जमा हो जाती है, जिसे अभिवृद्धि डिस्क के रूप में जाना जाता है।
- घूमती हुई डिस्क पदार्थ को तारे तक पहुंचाती है, जो तेजी से बड़ा होता जाता है।
- तारे का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, जिससे डिस्क में अधिक गैस और धूल आ जाएगी।

अवश्य पढ़ें: डार्क गैलेक्सी

SOURCE: CNN

रक्तवर्णकता (Hemochromatosis)

संदर्भ: हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि उच्च लौह स्तर वंशानुगत हेमोक्रोमैटोसिस (एचएच) की संभावना को बढ़ाता है।

पृष्ठभूमि:हेमोक्रोमैटोसिस या 'ब्रोंज मधुमेह', एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार जो अंग की शिथिलता का कारण बनता है, इसके कारण, संकेत और उपचार निम्नलिखित है।

हेमोक्रोमैटोसिस के बारे में:-

- यह आपके शरीर को आपके द्वारा खाए गए भोजन से बहुत अधिक आयरन अवशोषित करने का कारण बनता है।
- अतिरिक्त आयरन आपके अंगों, विशेषकर आपके लीवर, हृदय और अग्न्याशय में जमा होता है।
- बहुत अधिक आयरन जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि लीवर रोग, हृदय समस्याएं और मधुमेह।
- लक्षण:- जैसे- जोड़ों का दर्द, पेट दर्द, थकान, मधुमेह, नपुंसकता आदि।

कारण:-

- अधिकतर जीन में परिवर्तन के कारण जो आपके शरीर द्वारा भोजन से अवशोषित आयरन की मात्रा को नियंत्रित करता है।
- परिवर्तित जीन माता-पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है। यह प्रकार सबसे सामान्य प्रकार है। इसे वंशानुगत हेमोक्रोमैटोसिस कहा जाता है।

इलाज:-

- फ़्लेबोटॉमी प्राथमिक हेमोक्रोमैटोसिस के लिए मानक उपचार है।

- इसमें शरीर में आयरन जुटाने वाली मुख्य लाल रक्त कोशिकाओं को हटाकर आयरन विषाक्तता को कम किया जाता है।

अवश्य पढ़ें: भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र

SOURCE: OREGON

'कॉस्मिक वाइन'

संदर्भ: हाल ही में, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने प्रारंभिक ब्रह्मांड में 20 जुड़ी हुई आकाशगंगाओं की 'कॉस्मिक वाइन' की खोज की।

पृष्ठभूमि:-

- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) डेटा का उपयोग करने वाले खगोलविदों ने प्रारंभिक ब्रह्मांड से कम से कम 20 क्लोसेली से पैक की गई आकाशगंगाओं की एक विशाल श्रृंखला की खोज की है, और यह इस बात की अंतर्दृष्टि प्रकट कर सकता है कि ब्रह्मांड में सबसे विशाल संरचनाएं कैसे बनती हैं।

कॉस्मिक वाइन के बारे में:-

- यह एक बहुत ही प्राचीन और विशाल "बेल जैसी संरचना" है जो 20 आकाशगंगाओं को घेरती है और 13 प्रकाश वर्ष से अधिक तक फैली हुई है।
- शोधकर्ताओं ने इसे रेडशिफ्ट 3.44 पर आंका, जिसका अर्थ है कि यह प्रारंभिक ब्रह्मांड में स्थित है।

अद्वितीय विशेषतायें:-

- यह असाधारण रूप से लंबा और विशाल है, जो समान रेडशिफ्ट पर अन्य ज्ञात कॉम्पैक्ट आकाशगंगा समूहों के आकार को पार करता है।
- इसमें इतने उच्च रेडशिफ्ट पर अब तक खोजी गई दो सबसे विशाल आकाशगंगाएँ हैं - गैलेक्सी A और गैलेक्सी E, दोनों शांत अवस्था में हैं, जो स्टार निर्माण की कम दर का संकेत देती हैं।

महत्व:-

- यह विशाल आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास पर नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
- यह सुझाव देता है कि विशाल शांत आकाशगंगाएँ कुछ पुराने मॉडलों के विपरीत, बड़े पैमाने पर संरचनाओं के विस्तार के भीतर बन सकती हैं।

MUST READ:IN-SPACe

SOURCE: SPACE

गुइलेन-बैरे सिंड्रोम

संदर्भ: हाल के शोध से पता चला है कि COVID-19 के कारण 'अत्यंत दुर्लभ' गुइलेन-बैरी सिंड्रोम विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है।

गुइलेन-बैरी सिंड्रोम के बारे में:-

- सिंड्रोम एक दुर्लभ विकार है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली आपकी नसों पर हमला करती है।
- आपके हाथों और पैरों में कमजोरी और झुनझुनी आमतौर पर पहला लक्षण है।
- ये संवेदनाएं तेजी से फैल सकती हैं, अंततः आपके पूरे शरीर को पंगु बना सकती हैं।
- अपने सबसे गंभीर रूप में वे सिंड्रोम एक चिकित्सा आपातकाल है।
- अभी सटीक कारण अज्ञात है।
- लेकिन दो-तिहाई मरीज़ पिछले छह सप्ताह में संक्रमण के लक्षणों की रिपोर्ट करते हैं।
- इनमें COVID-19, श्वसन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण या जीका वायरस शामिल हैं।

लक्षण:-

- आपकी उंगलियों, पैर की उंगलियों, टखनों या कलाइयों में चुभन और सुइयों की अनुभूति होना।
- आपके पैरों में कमजोरी, चलने में अस्थिरता या चलने या सीढ़ियाँ चढ़ने में असमर्थता।

- बोलने, चबाने या निगलने सहित चेहरे की गतिविधियों में कठिनाई होना।
- दोहरी दृष्टि, तेज़ हृदय गति, निम्न या उच्च रक्तचाप, सांस लेने में कठिनाई इसके कुछ लक्षण हैं।
- मूत्राशय पर नियंत्रण या आंत्र कार्य में कठिनाई होना।

प्रकार:-

- एक्यूट इंफ्लेमेटरी डिमाइलेटिंग पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी (AIDP): यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप में सबसे आम रूप है। लक्षण: मांसपेशियों में कमजोरी
- मिलर-फिशर सिंड्रोम (MFS): इसमें आंखों में लकवा होने लगता है। यह अस्थिर चाल से जुड़ा है। यह अमेरिका में कम आम है लेकिन एशिया में अधिक आम है।
- एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी (AMAN) और एक्यूट मोटर-सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी (AMSAN): यह अमेरिका में कम आम हैं, लेकिन AMAN और AMSAN चीन, जापान और मैक्सिको में अधिक पाए जाते हैं।

इलाज:-

- इस सिंड्रोम का कोई ज्ञात इलाज नहीं है। आमतौर पर इसका इलाज अंतःशिरा इम्युनोग्लोबुलिन (आईवीआईजी) द्वारा किया जाता है, जो डोनेट किए गए रक्त से बना होता है जिसमें स्वस्थ एंटीबॉडी होते हैं।

अवश्य पढ़ें: iNCOVACC
स्रोतः ऑप्थैल्मोलॉजी टाइम्स

डीपफेक

संदर्भ: हाल ही में, सरकार ने डीपफेक पर अंकुश लगाने में सोशल नेटवर्क की प्रगति की समीक्षा की।

पृष्ठभूमि:-

- केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गलत सूचना और डीपफेक से निपटने में उनके द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से मुलाकात की और जोर देकर कहा कि प्लेटफार्मों द्वारा 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अगले दो दिनों में सलाह जारी की जाएगी।

डीपफेक के बारे में:-

- डीपफेक शब्द की उत्पत्ति 2017 में हुई, जब एक गुमनाम Reddit उपयोगकर्ता ने खुद को "डीपफेक" कहा।
- यह शब्द डिजिटल अभ्यावेदन (वीडियो और चित्र) को संदर्भित करता है, जो मूल वीडियो में व्यक्ति को किसी और के साथ बदलने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित किया जाता है।
    - उन्होंने प्रौद्योगिकी का उपयोग किया: गहन शिक्षण एल्गोरिदम, विशेष रूप से जेनरेटिव एडवरसैरियल नेटवर्क (जीएएन) और ऑटोएनकोडर मॉडल।
- यह शक्तिशाली कंप्यूटर और गहन शिक्षण का उपयोग करके वीडियो, छवियों और ऑडियो में हेरफेर करने की एक विधि है।
- इसका उपयोग फर्जी खबरें उत्पन्न करने और अन्य गलत कामों के अलावा वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है।
- डीपफेक के एल्गोरिदम इतने बुद्धिमान होते हैं कि वे स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

अनुप्रयोग:-

- मनोरंजन उद्योग: मनोरंजन उद्योग में उपयोग किया जाता है, जो फिल्मों और वीडियो गेम में आकर्षक दृश्य प्रभाव, डिजिटल डबल्स और यथार्थवादी चरित्र एनिमेशन के निर्माण को सक्षम बनाता है।
- सोशल मीडिया और गलत सूचना: इसने गलत सूचना के प्रसार के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि हेरफेर किए गए वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग जनता को धोखा दे सकते हैं और जनता की राय को प्रभावित कर सकते हैं।
- साइबर सुरक्षा खतरे: यह साइबर सुरक्षा खतरे उत्पन्न करता है, क्योंकि दुर्भावनापूर्ण अभिनेता इस तकनीक का उपयोग पहचान की चोरी, प्रतिरूपण और धोखाधड़ी के लिए कर सकते हैं, जिससे व्यक्तियों और संगठनों की सुरक्षा और गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है।

- राजनीतिक हेरफेर और दुष्प्रचार: यह राजनीतिक हेरफेर और दुष्प्रचार अभियानों के लिए उपयोग किया जाता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता और राजनीतिक संस्थानों में जनता के विश्वास के बारे में चिंता उत्पन्न करता है।

चुनौतियाँ:-

- इसके संभावित दुरुपयोग के कारण चिंताएं बढ़ गई हैं, जिससे समाज के विभिन्न पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं।
- इसने फर्जी समाचार, धोखाधड़ी, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफ़ी और पहचान की चोरी में अपने अनुप्रयोगों के लिए ध्यान आकर्षित किया है।

डीपफेक पर भारत का वर्तमान रुख:-

- भारत में डीपफेक को विनियमित करने के लिए समर्पित एक व्यापक कानूनी ढांचे का अभाव है।
- भारत पहले से मौजूद कानूनों पर निर्भर है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000) की धारा 67 और 67ए, जो मानहानि और स्पष्ट सामग्री प्रसार पर लागू हो सकते हैं।
- मानहानि का प्रावधान: भारतीय दंड संहिता (1860) की धारा 500 मानहानि के लिए सजा का प्रावधान करती है।
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (2022): व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यह डीपफेक के मुद्दे को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करता है।

अवश्य पढ़ें: डीपफेक तकनीक और चीन

SOURCE: PTI

आदित्य-L1

संदर्भ: हाल ही में, आदित्य-L1 जहाज पर पेलोड ने सूर्य की पूर्ण-डिस्क छवियां लीं।

पृष्ठभूमि:-

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने घोषणा की कि आदित्य-एल1 अंतरिक्ष यान पर लगे सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप (एसयूआईटी) उपकरण ने सूर्य की पहली पूर्ण-डिस्क छवियों को सफलतापूर्वक कैप्चर किया है।

आदित्य-एल1 के बारे में:-

- यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष-आधारित भारतीय मिशन होगा।
- लॉन्च किया गया: इसरो द्वारा।
- प्रक्षेपण यान: PSLV-XL।
    - गंतव्य स्थल: सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 (एल1 की स्थापना: जोसेफ लुईस लैग्रेंज द्वारा की गई थी) के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाना है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है।
    - लैग्रेंज बिंदु: अंतरिक्ष में वे स्थान जहां दो बड़े पिंडों, जैसे कि एक ग्रह और उसका चंद्रमा या एक ग्रह और सूर्य, के गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण संतुलन के उन्नत क्षेत्रों का निर्माण करते हैं।
    - सूर्य-पृथ्वी प्रणाली में पांच प्राथमिक लैग्रेंजियन बिंदु हैं, जिन्हें L1 से L5 तक लेबल किया गया है।
- आदित्य एल1 का महत्व: यह वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभाव को देखने में अधिक लाभ प्रदान करेगा।

आदित्य L1 के उद्देश्य:-

- सौर ऊपरी वायुमंडलीय गतिशीलता और क्रोमोस्फेरिक तथा कोरोनल हीटिंग का अध्ययन, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल द्रव्यमान इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स।
- सौर कोरोना के भौतिकी और कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा के निदान का अध्ययन: तापमान, वेग और घनत्व।
- सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप का अध्ययन करना।

आदित्य L1 में पेलोड्स:-

- बोर्ड पर कुल सात पेलोड हैं: - यानी उनमें से चार सूर्य की रिमोट सेंसिंग करते हैं और उनमें से तीन इन-सीटू अवलोकन करते हैं।

रिमोट सेंसिंग पेलोड:-

- दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ (VELC)
- सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप (SUIT)
- सौर निम्न ऊर्जा एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (SoLEXS)
- उच्च ऊर्जा L1 कक्षीय एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (HEL1OS)

इन-सीटू पेलोड:-

- आदित्य सौर पवन कण प्रयोग (ASPEX)
- आदित्य (PAPA) के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज
- उन्नत त्रि-अक्षीय उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर

अवश्य पढ़ें: शुक्रयान

स्रोत: द हिंदू

पर्टुसिस (काली खांसी)

संदर्भ: यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के अनुसार, जुलाई और नवंबर के बीच पर्टुसिस के 716 मामले सामने आए, जो 2022 की इसी अवधि की तुलना में तीन गुना अधिक है।

पृष्ठभूमि:-

- रिपोर्टों के बाद, एजेंसी के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के उप निदेशक डॉ. गायत्री अमृतलिंगम ने कहा कि सामाजिक दूरी और लॉकडाउन नियमों के कारण COVID-19 महामारी के दौरान संक्रमण की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन वर्तमान में यह बढ़ रही है।

पर्टुसिस के बारे में:-

- यह काली खांसी के नाम से प्रसिद्ध है, यह बैक्टीरिया बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन संक्रमण है।
- लंबे समय तक खांसने से आपके फेफड़ों से हवा बाहर निकल जाती है। जब आप खांसी के दौरे के बाद तेजी से और गहराई से हवा के लिए हांफते हैं, तो हवा के अंदर जाने के साथ-साथ काली खांसी की आवाज भी आ सकती है। यह ध्वनि एक तेज़, उच्च स्वर वाली "हूपिंग" ध्वनि है। यहीं से पर्टुसिस का नाम मिलता है।
- इस रोग से केवल मनुष्य ही प्रभावित होते हैं।
- पर्टुसिस मुख्य रूप से खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है।
- यह बीमारी शिशुओं में सबसे खतरनाक है, और इस आयु वर्ग में बीमारी और मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण है।

लक्षण:-

- पहले लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 7 से 10 दिन बाद दिखाई देते हैं।
- शुरुआती काली खांसी के लक्षण सामान्य सर्दी के समान होते हैं। ये लक्षण एक से दो सप्ताह तक बने रह सकते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं:-
    - हल्का बुखार
    - हल्की या कभी-कभार खांसी होना
    - नाक बहना
    - शिशुओं में सांस लेने में रुकावट (एपनिया)
- पहला या दूसरा सप्ताह बीत जाने के बाद काली खांसी के लक्षणों में आमतौर पर शामिल हैं:
    - लंबे समय तक, बार-बार या तीव्र खांसी के एपिसोड (पैरॉक्सिस्म्स) जो रुक-रुक कर 10 सप्ताह या उससे अधिक समय तक दोहराए जाते हैं।
    - खांसी बंद होने के बाद सांस लेते समय घरघराहट की आवाज आना।
    - उल्टी होना।
    - लंबे समय तक खांसी के कारण थकावट होना।

इलाज:-

- काली खांसी का इलाज निदान के बाद यथाशीघ्र शुरू कर देना चाहिए। (रोग निगरानी प्रणाली)
- बीमारी को फैलने से रोकने में मदद के लिए एक प्रदाता एंटीबायोटिक्स की सलाह देगा। लेकिन एंटीबायोटिक्स आपकी खांसी को रोक नहीं सकते या उसका इलाज नहीं कर सकते।
- कफ सिरप और अन्य दवाएं आपकी खांसी से राहत नहीं दिला सकती हैं, इसलिए आपको अपने लक्षणों को रोकने के लिए घरेलू उपचार के अन्य रूपों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
- 1950 के दशक में एक ऐसा टीका विकसित किया गया जिसने इसके प्रभाव को काफी कम कर दिया।
- काली खांसी से बचाव के लिए काली खांसी का टीका लगवाना सबसे अच्छा तरीका है।

अवश्य पढ़ें: गैर संचारी एवं संचारी रोग

SOURCE: FREE PRESS JOURNAL

एन्थ्रोबोट्स

सन्दर्भ: वैज्ञानिकों ने हाल ही में एन्थ्रोबोट्स बनाये हैं।

पृष्ठभूमि:-

- एक नए अध्ययन के अनुसार, ये मानव कोशिकाओं से बने छोटे जीवित रोबोट हैं जो लैब डिश में घूम सकते हैं और एक दिन घावों या क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने में मदद करने में सक्षम हो सकते हैं।

एंथ्रोबोट्स के बारे में:-

- एंथ्रोबोट मानव श्वासनली कोशिकाओं से निर्मित नवीन बायोइंजीनियर्ड रोबोट हैं।
- इन बायोबॉट्स में स्वायत्त रूप से विभिन्न रूपों और आकारों में कॉन्फ़िगर करने की उल्लेखनीय क्षमता होती है।

कार्यरत:-

- इस प्रक्रिया में पैडल के रूप में कार्य करने वाले सिलिया से सुसज्जित एंथ्रोबोट बनाने के लिए मानव श्वासनली त्वचा कोशिकाओं के समूहों को विकसित करना शामिल है।
- जब क्षतिग्रस्त तंत्रिका ऊतक पर तैनात किया जाता है, तो एंथ्रोबोट्स एक 'सुपरबोट' में मिल जाते हैं, जिससे आनुवंशिक परिवर्तन की आवश्यकता के बिना तीन दिनों के भीतर पूर्ण पुनर्प्राप्ति की सुविधा मिलती है।

महत्व:-

- शोधकर्ताओं ने पुनर्योजी चिकित्सा के क्षेत्र में संभावित उपयोगों को प्रदर्शित करते हुए धमनी निकासी, बलगम व्यवधान, या दवा प्रशासन जैसे विभिन्न कार्यों के लिए वैयक्तिकृत एंथ्रोबोट्स को नियोजित करने का अनुमान लगाया है।
- फ्रॉग सेलों से प्राप्त पहले के ज़ेनोबॉट्स के विपरीत, एंथ्रोबोट्स में स्वयं-संयोजन क्षमताएं होती हैं और इन्हें मानव ऊतक से तैयार किया जाता है, जो वैयक्तिकृत चिकित्सा के लिए एक आशाजनक अवसर प्रदान करता है।

MUST READ: Robo Sapiens- Future of the Work

SOURCE: INDIATIMES

वॉयेजर प्रथम

संदर्भ: वैज्ञानिकों को हाल ही में नासा के वोयाजर 1 में एक बड़ी गड़बड़ी का संदेह हुआ क्योंकि इसने पृथ्वी पर अजीब संकेत भेजे थे।

पृष्ठभूमि:-

- वोयाजर 1 को पृथ्वी ग्रह पर डेटा स्थानांतरित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष यान में एक बड़ी दरार की आशंका है।
- नासा का वोयाजर 1 पिछले 46 वर्षों से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है और 24 अरब किलोमीटर की यात्रा कर चुका है।

वोयाजर 1 के बारे में:-

- लॉन्च: 5 सितंबर, 1977
- लॉन्च साइट: केप कैनावेरल, फ्लोरिडा / लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41
- प्रक्षेपण यान: टाइटन IIIE-सेंटूर (TC-6 / टाइटन नं. 23E-6 / Centaur D-1T)।

- एजेंसी: NASA (NASA का DART मिशन)
- उद्देश्य: इसे बृहस्पति और शनि द्वारा उड़ान भरने के लिए लॉन्च किया गया था।
- वोयाजर 1 इतिहास का सबसे पुराना मानव निर्मित अंतरिक्ष यान है।
- कोई भी अंतरिक्ष यान नासा के वोयाजर 1 से अधिक दूर तक नहीं गया है।
- यह अगस्त 2012 में अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया और डेटा एकत्र करना जारी रखा।
- वोयाजर 1 45 वर्षों से अधिक समय से हमारे सौर मंडल की तलाश कर रहा है।
- जांच अब इंटरस्टेलर स्पेस, हेलिओपॉज़ के बाहर के क्षेत्र, या सूर्य से ऊर्जावान कणों और चुंबकीय क्षेत्रों के बबल में है।
- वोयाजर 1 और उसका सहयोगी जहाज वोयाजर 2 इतिहास में किसी भी अन्य अंतरिक्ष यान की तुलना में अधिक समय तक उड़ान भर रहे हैं।

अवश्य पढ़ें: स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क (स्पिन)

SOURCE: FINANCIAL EXPRESS

केटामिन

संदर्भ: हाल ही में अभिनेता मैथ्यू पेरी की मौत में केटामाइन दवा शामिल होने की सूचना मिली थी।

पृष्ठभूमि:-

- हाल के वर्षों में, अवसाद और अन्य गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए केटामाइन अपने बढ़ते उपयोग के कारण व्यापक बहस का विषय रहा है।

केटामाइन के बारे में:-

- केटामाइन एक एनेस्थेटिक है जिसे यूएस ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हेलुसीनोजेन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- यह फेनसाइक्लिडीन (पीसीपी) से प्राप्त होता है, जो एक हेलुसीनोजेनिक दवा है।
- यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में एनएमडीए रिसेप्टर को अवरुद्ध करके संचालित होता है।
- यह न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट के स्राव को बढ़ाता है।
- इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा-प्रतिरोधी रोगियों में मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है।
- इसका उपयोग मनोरंजक औषधि के रूप में भी किया जाता है।
- मनोरंजक दवा वह दवा है जिसका उपयोग आनंद उत्पन्न करने या किसी की मनःस्थिति को बदलने के लिए किया जाता है।
- **इनके प्रकारों में शामिल हैं:**
    - उत्तेजक: सतर्कता और ऊर्जा बढ़ाना। जैसे, कोकीन, मेथमफेटामाइन और कैफीन।
    - अवसाद: यह शांत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसे, शराब, मारिजुआना, और बेंजोडायजेपाइन।
    - हेलुसीनोजेन्स: यह मतिभ्रम उत्पन्न करते हैं। जैसे, एलएसडी, साइलोसाइबिन और डीएमटी।

अनुप्रयोग:-

- इसे साइकेडेलिक गुणों के साथ एक विघटनकारी संवेदनाहारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इसका उपयोग एनेस्थीसिया के लिए चिकित्सकीय देखरेख में सख्ती से किया जाता है।
- अवसाद, चिंता, PTSD, एंड ऑफ लाइफ (end-of-life distress), क्रोनिक दर्द और मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दों जैसी स्थितियों के उपचार में भी नियोजित किया जाता है।

भारत में नियामक स्थिति:-

- इसे भारत में अनुसूची X दवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- यह डॉक्टर द्वारा केस-विशिष्ट आधार पर कड़े नियंत्रण और निगरानी के अधीन है।
    - औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के तहत अनुसूची X दवाओं को "प्रतिबंधात्मक दवाओं" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। (नशीली दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कोष)
    - अनुसूची X के अंतर्गत दवाओं का वर्गीकरण उच्च स्तर के नियामक नियंत्रण और निगरानी का प्रतीक है।

अवश्य पढ़ें: बिस्फेनॉल ए

MUST READ: Bisphenol A

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

WATSONX.AI

संदर्भ: हाल ही में, COP28 में, NASA और IBM ने घोषणा की कि watsonx.ai नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल ओपन-सोर्स AI प्लेटफॉर्म हगिंग स्पेस पर उपलब्ध होगा।

पृष्ठभूमि:-

- wattsx.ai उपयोगकर्ताओं को अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी करने, पहले से हो चुके पर्यावरणीय परिवर्तनों को मापने के साथ-साथ भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने में भी मदद करेगा।

watsonx.ai के बारे में:-

- यह IBM और NASA द्वारा विकसित एक सहयोगी AI टूल है।
- उद्देश्य: अधिक सटीकता के साथ तूफान, सूखा और अन्य गंभीर मौसम की घटनाओं की भविष्यवाणी करने की क्षमता बढ़ाना।
- प्लेटफ़ॉर्म में एआई सहायकों का एक सेट है जो एक पैमाने पर मदद करता है और अपने व्यवसाय में विश्वसनीय डेटा के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव को तेज करता है।
- watsonx.ai के मामले में, NASA डेटासेट प्रदान करता है और IBM ने उनकी व्याख्या करने के लिए फाउंडेशन मॉडल बनाया है।
- मॉडल को उपयोग में बेहद सरल बनाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है।
- उपयोगकर्ता को केवल एक स्थान और एक तारीख का चयन करने की आवश्यकता होगी, और मॉडल बाढ़ के पानी, पुनर्वनीकरण प्रयासों और अन्य प्रासंगिक कारकों में परिवर्तन को उजागर करेगा।
- यह एक एंड-टू-एंड टूलकिट है जिसमें डेटा और AI गवर्नेंस दोनों शामिल हैं।
- यह उपयोगकर्ताओं को अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी करने, पहले से हो चुके पर्यावरणीय परिवर्तनों को मापने के साथ-साथ भविष्यवाणियां करने में भी मदद करेगा।
- भारत सरकार देश भर में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और सूखे के कारण मौसम पूर्वानुमान में सुधार करने के लिए जलवायु मॉडल बनाने के लिए एआई का परीक्षण कर रही है।

अवश्य पढ़ें: डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

नोमा

संदर्भ: हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (एनटीडी) की अपनी आधिकारिक सूची में नोमा को शामिल किया है।

पृष्ठभूमि:-

- मुंह और चेहरे की गंभीर गैंग्रीनस बीमारी में मृत्यु दर 90% है और यह अत्यधिक गरीबी, कुपोषण से जुड़ा है।

नोमा के बारे में:-

- इसे कैंक्रम ऑरिस या गैंग्रीनस स्टामाटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है।
- इस बीमारी का नाम ग्रीक शब्द "नोमे" से आया है, जिसका अर्थ है "खा जाना", क्योंकि अगर जल्दी इलाज न किया जाए तो नोमा चेहरे के ऊतकों और हड्डियों को खा जाता है।
- नोमा कई जोखिम कारकों से जुड़ा है, जिनमें खराब मौखिक स्वच्छता, कुपोषण, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, संक्रमण और अत्यधिक गरीबी शामिल हैं।
- यह मुंह और चेहरे की एक गंभीर गैंग्रीनस बीमारी है जिसमें मृत्यु दर लगभग 90 प्रतिशत है।
- यह अत्यधिक गरीबी, कुपोषण और स्वच्छता तथा मौखिक स्वच्छता तक खराब पहुंच से भी जुड़ा है।

- यह मुख्य रूप से 2-6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है और गरीब समुदायों में रहने वाले लोगों में सबसे अधिक पाया जाता है।
- हालांकि यह बीमारी संक्रामक नहीं है, यह तब हमला करना पसंद करती है जब शरीर की प्रतिरक्षा कमजोर होती है।
- यह रोग मसूड़ों की सूजन से शुरू होता है और माना जाता है कि यह मुंह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के कारण होता है।
- यह एचआईवी, ल्यूकेमिया और अन्य बीमारियों के कारण कमजोर प्रतिरक्षा वाले वयस्कों में भी हो सकता है।
- यह अफ्रीका, एशिया और एशिया-प्रशांत, अमेरिका, मध्य पूर्व और यूरोप में प्रचलित है।

उपचार: - इसमें व्यापक रूप से उपलब्ध एंटीबायोटिक दवाओं के नुस्खे, मौखिक स्वच्छता, कीटाणुनाशक माउथवॉश और पोषण की खुराक में सुधार के लिए प्रथाओं पर सलाह और समर्थन शामिल है।

अवश्य पढ़ें: राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण (NNMS)

SOURCE: DOWN TO EARTH

एपोफिस क्षुद्रग्रह

संदर्भ: हाल ही में, नासा ने निकट-अर्थस्टेरॉयड एपोफिस को रोकने के लिए एक मिशन शुरू किया है।

पृष्ठभूमि:-

- नासा ने "अराजकता के देवता" उपनाम वाले एक निकट-पृथ्वी क्षुद्रग्रह को रोकने के लिए एक मिशन शुरू किया है।

एपोफिस क्षुद्रग्रह के बारे में:-

- क्षुद्रग्रह एपोफिस, जिसका नाम मिस्र के अराजकता के देवता के नाम पर रखा गया है।
- क्षुद्रग्रह 99942 एपोफिस एक निकट-पृथ्वी वस्तु (NEO) है।
- अनुमान है कि यह लगभग 1,100 फीट (340 मीटर) चौड़ा है।
- जब 2004 में इसकी खोज की गई थी, तो एपोफिस को सबसे खतरनाक क्षुद्रग्रहों में से एक के रूप में पहचाना गया था जो पृथ्वी को प्रभावित कर सकता था।
- मार्च 2021 में एक रडार अवलोकन अभियान ने, सटीक कक्षा विश्लेषण के साथ, खगोलविदों को यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति दी कि कम से कम एक सदी तक एपोफिस द्वारा हमारे ग्रह को प्रभावित करने का कोई खतरा नहीं है।
- इसका अगला क्लोज पास 13 अप्रैल, 2029 को हो रहा है।
    - उस तारीख को, एपोफिस हमारे ग्रह के 20,000 मील के भीतर कुछ मानव निर्मित उपग्रहों की तुलना में करीब आ जाएगा, जिससे यह खुली आंखों को दिखाई देगा।
- इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय मिलन का विश्लेषण करने के लिए, नासा ने OSIRIS-REx अंतरिक्ष यान को पुनर्निर्देशित किया है जो हाल ही में क्षुद्रग्रह बेन्नु से लौटा है।
- अब इसे OSIRIS-APEX कहा जाता है, इसका मिशन 2029 फ्लाईबाई से पहले, उसके दौरान और उसके बाद एपोफिस का निरीक्षण करना है।

महत्व:-

- हालाँकि एपोफिस से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है, ऐसे निकट-मार्गों का विश्लेषण गुरुत्वाकर्षण तनाव के प्रति क्षुद्रग्रह की प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालते हुए तैयारियों को बढ़ाता है।
- यहां तक कि मामूली परिवर्तन से एपोफिस के भविष्य के प्रक्षेप पथ को प्रोजेक्ट करने में मदद मिल सकती है क्योंकि यह पृथ्वी और सूर्य के बीच चक्र करता है।

MUST READ: IN-SPACe

SOURCE: MSN

हेल्थ

रूमेटाइड अर्थराइटिस

संदर्भ: हाल के अध्ययनों से युवा वयस्कों में रुमेटीइड गठिया के मामले सामने आए हैं।

पृष्ठभूमि:-

- स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, आरए से पीड़ित युवा स्वयं को पुराने दर्द, थकान और सीमित शारीरिक क्षमताओं की दुनिया में नेविगेट करते हुए पा सकते हैं।

रुमेटीइड गठिया के बारे में:-

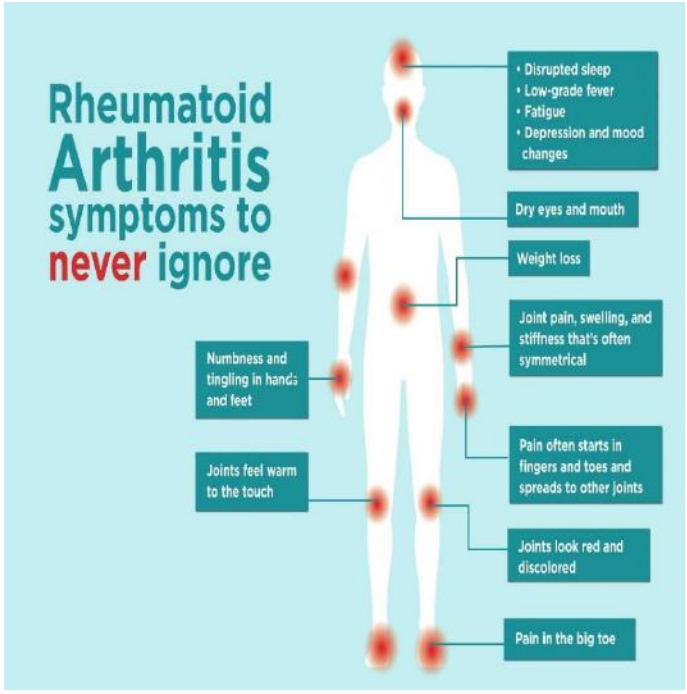

IMAGE SOURCE: CreakyJoints

- रुमेटीइड गठिया एक दीर्घकालिक सूजन संबंधी विकार (inflammatory disorder) है।
- यह एक ऑटोइम्यून विकार है, जो तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने ही शरीर के ऊतकों पर हमला कर देती है।

कारण:-

- एक स्वस्थ व्यक्ति में, प्रतिरक्षा प्रणाली बैक्टीरिया और वायरस जैसे आक्रमणकारियों से लड़ती है।
- लेकिन आरए जैसी ऑटोइम्यून बीमारी के साथ, प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की कोशिकाओं को बाहरी इन्वैडर समझती है और सूजन वाले रसायन छोड़ती है जो उन कोशिकाओं पर हमला करते हैं।
- ऑस्टियोआर्थराइटिस की टूट-फूट क्षति के विपरीत, रुमेटीइड गठिया जोड़ों की परत को प्रभावित करता है, जिससे दर्दनाक सूजन होती है जिसके परिणामस्वरूप अंततः हड्डी का क्षरण और संयुक्त विकृति हो सकती है।
- लक्षण:- कोमल, गर्म, सूजे हुए जोड़। जोड़ों में अकड़न जो आमतौर पर सुबह और निष्क्रियता के बाद बदतर होती है, थकान, बुखार, भूख न लगना।

खतरा:-

- **लैंगिक:** पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रुमेटीइड गठिया विकसित होने की संभावना अधिक होती है।
- उम्र: रुमेटीइड गठिया किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन यह आमतौर पर आधी आयु में शुरू होता है।
- पारिवारिक हिस्ट्री: यदि आपके परिवार के किसी सदस्य को रुमेटीइड गठिया है, तो आपको इस बीमारी का खतरा बढ़ सकता है।
- धूम्रपान

अवश्य पढ़ें: रोग निगरानी प्रणाली

SOURCE: HINDUSTAN TIMES

इरिटेबल मेल सिंड्रोम

संदर्भ: हाल ही में पुरुषों में इरिटेबल मेल सिंड्रोम देखा गया है।

पृष्ठभूमि:-

- लिसुन में परामर्श मनोवैज्ञानिक क्रिस्टी साजू ने बताया कि आईएमएस को अभी तक चिकित्सकीय रूप से मान्यता नहीं मिली है, हालांकि यह टेस्टोस्टेरोन के स्तर में अनियमितता का मुद्दा हो सकता है।

इसके बारे में:-

- इसकी विशेषता यह है कि पुरुष हताशा, चिंता और क्रोध का अनुभव करते हैं।
- यह कई कारकों के कारण हो सकता है, जैसे हार्मोनल परिवर्तन और तनाव।

विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ सामान्य अभिव्यक्तियों में शामिल हैं:-

- मूड में बदलाव: मूड में तेजी से और तीव्र बदलाव का अनुभव होता है।
- थकान: पर्याप्त नींद और आराम के बाद भी लगातार थकान और सुस्ती का एहसास होता है।
- कामेच्छा में कमी: उनकी यौन इच्छा और यौन गतिविधियों में समग्र रुचि में गिरावट देखी जा सकती है।
- सामाजिक अलगाव: सामाजिक संपर्क की इच्छा में कमी, जिससे प्रभावित व्यक्ति खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं।
- खराब एकाग्रता और मेमोरी: ध्यान केंद्रित करने, एकाग्रता और मेमोरी बनाए रखने में कठिनाइयाँ।

इसका निदान निम्न द्वारा किया जा सकता है:-

- लक्षणों का मूल्यांकन: व्यक्ति के लक्षणों, चिकित्सा इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी
- शारीरिक परीक्षण: लक्षणों के किसी अन्य संभावित कारण का पता लगाने और सामान्य स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए आयोजित किया जाता है।
- हार्मोन परीक्षण: विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन को रक्त परीक्षण के माध्यम से मापा जा सकता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हार्मोन का स्तर पूरे दिन अलग-अलग हो सकता है, इसलिए परीक्षण हमेशा एक निश्चित निदान प्रदान नहीं कर सकता है।
- मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन: मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना और किसी भी अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक कारकों की पहचान करना जो लक्षणों में योगदान दे सकते हैं।

इलाज:-

- जीवनशैली में संशोधन: स्वस्थ जीवनशैली अपनाना।
- परामर्श या थेरेपी: टॉक थेरेपी, जैसे संज्ञानात्मक-व्यवहार थेरेपी (सीबीटी), मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन और आईएमएस से जुड़े अन्य भावनात्मक लक्षणों के प्रबंधन में फायदेमंद हो सकती है।
- हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (एचआरटी): कुछ मामलों में, यदि रक्त परीक्षण के माध्यम से कम टेस्टोस्टेरोन के स्तर की पहचान की जाती है, तो एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की सिफारिश कर सकता है।
- लक्षण प्रबंधन: विशिष्ट लक्षणों को संबोधित करना जिसमें तनाव प्रबंधन तकनीकों जैसी रणनीतियाँ शामिल हो सकती हैं।

अवश्य पढ़ें : डेंगू

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

कोविड उप-संस्करण JN.1

संदर्भ: हाल ही में, भारत ने COVID उप-संस्करण JN.1 के 21 मामले दर्ज किए, जो अब WHO का 'रुचि का संस्करण' है।

पृष्ठभूमि:-

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का कहना है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है।

कोविड उप-संस्करण JN.1 के बारे में:-

- पहले JN.1 को उसके मूल BA.2.86 वंश के हिस्से के रूप में वर्गीकृत और ट्रैक किया गया था, जो स्वयं SARS-CoV-2 के ओमिक्रॉन या B.1.1.529 संस्करण का वंशज है, जो वायरस COVID-19 बीमारी का कारण बनता है।
- अपने मूल वंश BA.2.86 की तुलना में, इसमें स्पाइक प्रोटीन में एक अतिरिक्त उत्परिवर्तन (L455S उत्परिवर्तन) है।

- विस्तार: यह भारत, चीन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित देशों में पाया गया है।
- WHO ने कहा कि वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, "JN.1 द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को वर्तमान में कम माना गया है"।
- ट्रांसमिशन: वर्तमान में, ऐसा कोई सबूत नहीं है जो बताता हो कि JN.1 अधिक गंभीर लक्षण उत्पन्न करता है या अन्य परिसंचारी वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलता है।
- खतरा: इसके मामले हल्के रहे हैं, मरीज़ घर पर ही ठीक हो रहे हैं।

लक्षण:-

- इसमें बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिरदर्द, लॉस ऑफ़ स्मेल, और दस्त तथा पेट में ऐंठन जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं शामिल हैं।
- JN.1 वैरिएंट वाले व्यक्तियों में अत्यधिक थकान की सूचना मिलती है।
- COVID-19 वैक्सीन संरचना पर WHO तकनीकी सलाहकार समूह के अनुसार, पिरोला और JN.1 दोनों को संक्रमित और टीका लगाए गए व्यक्तियों के सीरम द्वारा प्रभावी ढंग से बेअसर कर दिया गया है।

वैरिएंट ऑफ कंसर्न (वीओसी):-

- JN.1 को दुनिया भर में "इसके तेजी से बढ़ते प्रसार" के कारण रुचि के एक अलग प्रकार (VOI) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- WHO ने मार्च 2023 में वैरिएंट ऑफ कंसर्न (वीओसी), वीओआई और निगरानी के तहत वेरिएंट (वीयूएम) के लिए अपनी कार्यशील परिभाषाओं को अद्यतन किया।
- वीओआई परिभाषित करता है: वैरिएंट को आनुवंशिक परिवर्तनों वाला SARS-CoV-2 वैरिएंट माना जाता है, जो वायरस की विशेषताओं जैसे कि संचरणशीलता, विषाणु, एंटीबॉडी इवेज़न, चिकित्सीय के प्रति संवेदनशीलता और पता लगाने की क्षमता को प्रभावित करने के लिए अनुमानित या ज्ञात होते है।

भारत में कोविड उप-संस्करण JN.1:-

- केरल में कोरोना वायरस उप-संस्करण JN.1 के पहले मामले की पहचान के बाद।
- INSACOG: महाराष्ट्र और गोवा में एक मामले के साथ, JN.1 वैरिएंट के 19 अनुक्रमों का पता लगाया।
    - भारत SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG), एक बहु-प्रयोगशाला और बहु-एजेंसी नेटवर्क, सक्रिय रूप से निगरानी प्रयासों में शामिल है।

MUST READ:iNCOVACC
SOURCE: DOWN TO EARTH

डेंगू

संदर्भ: हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि अल नीनो प्रभाव के कारण विश्व स्तर पर डेंगू के मामले बढ़े हैं।

पृष्ठभूमि:-

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के एक विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 2000 और 2019 के बीच डेंगू के मामलों में दस गुना वृद्धि हुई है।

डेंगू के बारे में:-

- डेंगू एक वेक्टर जनित रोग है।
- इसका कारण: डेंगू वायरस (DENV)।
- संक्रमित मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से संचरण होता है।
    - मच्छर तब संक्रमित हो जाता है जब वह वायरस से संक्रमित व्यक्ति का खून पीता है।
    - डेंगू सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता।
- वायरस के 4 सीरोटाइप हैं जो डेंगू का कारण बनते हैं: DEN-1, DEN-2, DEN-3 और DEN-4।
- यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अधिक सामान्य है।
- यह अधिकतर शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में होता है।

लक्षण:-

- तेज बुखार (40°C/104°F), गंभीर सिरदर्द और आंखों के पीछे दर्द।
- मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द
- उल्टी के साथ जी मिचलाना
- ग्रंथियों में सूजन
- उपचार:-डेंगू बुखार के अधिकांश मामलों का इलाज घर पर दर्द की दवा से किया जा सकता है।

रोकथाम:-

- सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।
- मच्छर निरोधक का प्रयोग करें।
- मच्छरों के रहने का स्थान कम करें।
- **डीएनए टीके:-**डीएनए टीकों को अक्सर तीसरी पीढ़ी के टीके के रूप में जाना जाता है।

अवश्य पढ़ें: वोल्बाचिया बैक्टीरिया का उपयोग करके डेंगू को नियंत्रित करना

SOURCE: DOWN TO EARTH

इतिहास, कला एवं संस्कृति

गुरुपर्व

संदर्भ: हाल ही में ढाका के नानकशाही गुरुद्वारे में गुरुपर्व मनाया गया।

पृष्ठभूमि:-

- गुरु नानक देव की 554वीं जयंती ढाका के ऐतिहासिक नानकशाही गुरुद्वारे में मनाई गई।
- गुरुद्वारा नानकशाही ढाका का एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है।
- गुरु नानक देव ने वर्ष 1506-07 में ढाका का दौरा किया।
- गुरुद्वारे का निर्माण 1830 में गुरु नानक की यात्रा की स्मृति में किया गया था।
- गुरु तेग बहादुर भी दो साल से अधिक समय तक ढाका में रहे थे।
- ढाका के नानकशाही गुरुद्वारे में दो महत्वपूर्ण अवशेष हैं जिनमें गुरु तेग बहादुर की लकड़ी की चप्पल और गुरु ग्रंथ साहिब की दो हस्तलिखित प्रतियां शामिल हैं।

गुरुपर्व के बारे में:-

- गुरु नानक गुरुपर्व को गुरु नानक जयंती या गुरु नानक प्रकाश उत्सव भी कहा जाता है।
- यह दिन सिख धर्म के पहले गुरु, गुरु नानक के जन्म का उत्सव मनाता है। (गुरु नानक जयंती)
- उनकी शिक्षाओं और जीवन ने समानता, सामाजिक न्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण के सिद्धांतों पर आधारित एक एकेश्वरवादी धर्म सिख धर्म की नींव रखी।
- गुरु नानक का जन्म बिक्रमी कैलेंडर के अनुसार कटक के पूरनमासी में हुआ था।
- उनका जन्म तलवंडी, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ था।
- उनका जन्म वर्ष 1469 में हुआ था।
- हालाँकि, भाई बाला जन्मसाखी का दावा है कि गुरु नानक का जन्म कार्थी (एक चंद्र माह) की पूर्णिमा को हुआ था।
- इसी कारण से, कुछ सिख नवंबर महीने में गुरु नानक जयंती मनाते हैं।
- वर्ष 2023 को गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती है।
- उनका जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के पंद्रहवें चंद्र दिवस पर हुआ था।
- ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर में आता है।

अवश्य पढ़ें : सिख अलगाववाद

स्रोत: AIR

गरबा

सन्दर्भ: हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में गुजरात के गरबा का नाम अंकित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुशी जताई।

पृष्ठभूमि:-

- प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया; "गरबा जीवन, एकता और हमारी गहरी परंपराओं का उत्सव है। अमूर्त विरासत सूची में इसका शिलालेख दुनिया को भारतीय संस्कृति की सुंदरता को दर्शाता है। यह सम्मान हमें भावी पीढ़ियों के लिए अपनी विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। इस वैश्विक स्वीकृति के लिए बधाई।"
- गरबा, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया।

गरबा के बारे में:-

- गरबा गुजरात का एक पारंपरिक नृत्य है। (मोहिनीअट्टम)
- गरबा यूनेस्को सूची में शामिल होने वाली भारत की 15वीं सांस्कृतिक आइटम है।
- यह एक पारंपरिक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से हिंदू देवी दुर्गा की पूजा के लिए नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है।
- यह प्रजनन क्षमता (Fertility) का जश्न मनाता है, नारीत्व (Womanhood) का सम्मान करता है।
- "गरबा" शब्द "गर्भ" (गर्भ) और "दीप" (दीपक) से आया है।
- नृत्य एक केंद्रीय दीपक या देवी के प्रतिनिधित्व के आसपास किया जाता है, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है।
- प्रकाश (गरबा दीप) या देवी दुर्गा की तस्वीर को संकेंद्रित रिंग के बीच में रखा जाता है, और लोग इसके चारों ओर नृत्य करते हैं, हर कदम के साथ बग़ल में झुकते हैं और अपनी बाहों से व्यापक इशारे करते हैं, यह हर मूवमेंट तालियों के साथ समाप्त होता है।
- महिलाएं चनिया चोली (एक रंगीन, कढ़ाई वाला स्कर्ट सेट) पहनती हैं और पुरुष केडियू और धोती या पायजामा पहनते हैं, जो अक्सर शीशे और कढ़ाई से अलंकृत होता है।
- गरबा के बाद अक्सर डांडिया रास होता है, जो लाठी (डांडिया) का उपयोग करने वाला एक अन्य नृत्य है, खासकर यह आरती (पूजा अनुष्ठान) के बाद होता है।

अवश्य पढ़ें: कथकली नृत्य

SOURCE: PIB

मिस्र के ममीकृत बबून

संदर्भ: मिस्र के ममीकृत बबून की रहस्यमय उत्पत्ति का रहस्य हाल ही में सुलझा लिया गया है।

पृष्ठभूमि:-

- वैज्ञानिकों ने हाल ही में मिस्र में गब्बानत अल-कुरुद स्थल पर पाए गए एक ममीकृत बबून से प्राचीन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) प्राप्त किया है, जो इसकी उत्पत्ति की खोज में मदद करेगा।

मिस्र के ममीकृत बबून के बारे में:-

- मिस्र के देवता थोथ का प्रतिनिधित्व एक बबून द्वारा किया गया था - जो अजीब है क्योंकि बबून मिस्र के मूल निवासी नहीं हैं।
- वर्ष 1905 में, मिस्रविज्ञानी लुईस लोर्टेट और क्लाउड गिलार्ड ने गब्बानत अल-कुरुद (जिसे 'बंदरों की घाटी' के रूप में भी जाना जाता है) में ममीकृत बबून की खोज की।
- बबून वर्तमान तटीय इरिट्रिया के प्राचीन शहर एडुलिस के थे, जो पहली और सातवीं शताब्दी ईस्वी के बीच एक व्यापार केंद्र था।
- पंट (Punt) का खोया हुआ शहर इसके उद्गम के संभावित स्थानों में से एक हो सकता है।
    - इस शहर का उल्लेख ग्रीको-रोमन इतिहासकारों के खातों में किया गया था और यह तेंदुए की खाल, सोने और विदेशी जानवरों के जीवन के व्यापार से जुड़ा था।

खोज का महत्व:-

- यह अध्ययन भारत, मिस्र और यूरोप के बीच व्यापार संबंधों में लाल सागर के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

बबून के बारे में:-

- बबून दुनिया के सबसे बड़े बंदरों में से कुछ हैं जिनके मजबूत धड़, थूथन जैसा चेहरा, लंबे, तेज नुकीले दांत और शक्तिशाली जबड़े होते हैं।

- वितरण: अफ्रीका और अरब
- पर्यावास: ये सवाना और अन्य अर्ध-शुष्क आवासों को प्राथमिकता देते हैं, हालांकि कुछ उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं।
- बबून का सामाजिक व्यवहार मातृसत्तात्मक होता है, जिसमें प्रजाति की मादा सदस्यों द्वारा सामाजिक संबंधों का एक नेटवर्क तीन पीढ़ियों तक बनाए रहती है।

अवश्य पढ़ें: भारत-मिस्र संबंध

SOURCE: THE HINDU

तंजावुर

संदर्भ: प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी तंजावुर यात्रा पर हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस की एक सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब दिया।

पृष्ठभूमि:-

- प्रधान मंत्री ने कहा: "तंजावुर वास्तव में सुंदर है! और, भारत में देखने के लिए और भी बहुत कुछ है जो दुनिया भर के पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देगा।"

तंजावुर के बारे में:-

- तंजावुर (तंजावुर या तंजौर) दक्षिणी भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में एक मंदिर स्थल है।
- तंजावुर महान चोल (कोला) राजा राजराज प्रथम की राजधानी थी, जिन्होंने 11वीं शताब्दी की शुरुआत में इस स्थान पर भव्य मंदिर, बृहदीश्वर का निर्माण कराया था।
- तंजावुर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

बृहदीश्वर मंदिर के बारे में:-

- बृहदीश्वर (या बृहदीश्वर) मंदिर का निर्माण 995 और 1025 ईस्वी के बीच चोल युद्ध की लूट और श्रीलंका से मिली श्रद्धांजलि का उपयोग करके किया गया था।
- यह मंदिर हिंदू भगवान शिव को समर्पित था।
- परिसर के अंदर विभिन्न माध्यमिक मंदिर और एक स्मारकीय दोहरा प्रवेश द्वार (गोपुर) हैं।
- दो मंजिला बृहदेश्वर मंदिर एक ऊंचे दादो-आधार मंच (dadoed-base platform) पर बना है।
- ग्रेनाइट टॉवर (विमान), पवित्र गर्भगृह (आंतरिक मंदिर) के ऊपर तेरह घटते स्तरों पर उभरता है।
- इसके शीर्ष पर एक गुंबददार संरचना है जो लगभग 80 टन वजन वाले 7.7 मीटर वर्ग के ग्रेनाइट ब्लॉक पर टिकी हुई है।
- मंदिर को 16 x 16 वर्गों की एक सटीक योजना पर बनाया गया था, एक डिज़ाइन जिसे दक्षिणी भारत के द्रविड़ वास्तुकला में पद्मगर्भमंडल के रूप में जाना जाता है।
- गर्भगृह में 4 मीटर लंबा शिव लिंग (फाल्लस) है।
- भित्तिचित्र आंतरिक दीवारों को सजाते हैं, और, एक बार बाद के नायक काल के चित्रों द्वारा छिपाए गए, इनमें राजराजा प्रथम, उनके आध्यात्मिक सलाहकार या गुरु और उनकी तीन रानियों की बेहतरीन छवियां शामिल हैं।
- अन्य विषयों में नटराज (नृत्य के भगवान के रूप में शिव) शामिल हैं जो चोलों के कुल देवता (कुलदेवता) थे।

अवश्य पढ़ें: होयसल मंदिर

SOURCE: PIB

कदलेकायी पैरिश

संदर्भ: कदलेकायी पैरिश हाल ही में शुरू हुआ।

पृष्ठभूमि:-

- इस महोत्सव के द्वारा प्लास्टिक मुक्त रखने का प्रयास किया जा रहा है।

कदलेकायी पैरिश के बारे में:-

- यह मूंगफली मेला बेंगलुरु के मध्य में बसवना गुड़ी के पास आयोजित किया जाता है।
- यह डोड्डा बसव या नंदी को पहली फसल का प्रसाद है जिनका मंदिर बिगुल चट्टान के ऊपर है। इस त्योहार के दौरान बुल टेम्पल में विशेष पूजा और प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं।
- यह मूंगफली की फसल की पहली उपज का स्वागत करता है और इसे मूंगफली उत्सव के रूप में जाना जाता है।

- यह प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के अंतिम सोमवार को आयोजित किया जाता है।
- बेंगलुरु के बसवनगुडी में कदलेकायी पैरिश 9 दिसंबर 2023 से 11 दिसंबर 2023 तक है।
- कर्नाटक के किसान अच्छी फसल का आशीर्वाद लेने के लिए हर साल बुल टेम्पल में एकत्र होते हैं।
- त्योहार के दौरान, आगंतुक बाजार दरों से सस्ती कीमतों पर सीधे किसानों से थोक में मूंगफली खरीदते हैं।

MUST READ:Sari Festival "VIRAASAT

SOURCE: HINDUSTAN TIMES

गिरसू

संदर्भ: हाल ही में, इराक के प्राचीन मेगासिटी गिरसू में दो मंदिरों की खोज की गई।

पृष्ठभूमि:-

- पुरातत्वविदों को दो मंदिर मिले, यह एक दूसरे के ऊपर दबा हुआ था।

गिरसू के बारे में:-

- स्थान: इराक
- यह सुमेर सभ्यता का शहर था और इसकी खोज उन्नीसवीं सदी में हुई थी।
- सुमेर सभ्यता सबसे प्रारंभिक ज्ञात सभ्यताओं में से एक थी, जो दक्षिणी मेसोपोटामिया के ऐतिहासिक क्षेत्र में लगभग 4100 और 1750 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी।
  सुमेरियन बहुत अधिक तकनीकी प्रगति के लिए उत्तरदायी थे, जिसमें समय की माप के साथ-साथ लेखन भी शामिल था।
  - उन्होंने पहले ज्ञात शहरों का निर्माण किया और साथ ही कानून की पहली ज्ञात संहिता भी बनाई।
- पहली खुदाई 1880 के दशक में फ्रांसीसी पुरातत्वविद् अर्नेस्ट डी सार्ज़ेक द्वारा की गई थी।
- यह उल्लेखनीय था क्योंकि इसने सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता के अस्तित्व को दुनिया के सामने प्रकट किया था।
- इसने मेसोपोटामिया की कला और वास्तुकला के कुछ सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों को भी प्रकाश में लाया।

अवश्य पढ़ें: सिंधु घाटी सभ्यता में भाषा

SOURCE: LIVESCIENCE

स्टोनहेंज

संदर्भ: हालिया रिपोर्टों के अनुसार, अगर A303 सुरंग आगे बढ़ती है तो स्टोनहेंज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में 'डी-लिस्ट' किए जाने का खतरा है।

पृष्ठभूमि:-

- हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम में स्टोनहेंज के ग्रेट सर्कल के करीब दो मील की सड़क सुरंग के निर्माण को रोकने के प्रयासों को कार्यकर्ताओं द्वारा देखा गया था। (भारत की यूनेस्को विश्व की अस्थायी सूची में नई साइटें जोड़ी गईं)

स्टोनहेंज के बारे में:-

- स्थान: इंग्लैंड में सैलिसबरी मैदान।
- यह स्पष्ट नहीं है कि स्टोनहेंज का निर्माण किसने करवाया था। स्टोनहेंज नामक स्मारक 3000 और 1520 ईसा पूर्व के बीच छह चरणों में बनाया गया था।
- इस स्थल का उपयोग लगभग 8000-7000 ईसा पूर्व से औपचारिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था।
- स्टोनहेंज का निर्माण सरसेन पत्थरों से किया गया है, जो इंग्लैंड में पाया जाने वाला एक प्रकार का सिलिकीकृत बलुआ पत्थर है, और ब्लूस्टोन, पश्चिमी वेल्स से निकाले गए डोलोमाइट का एक प्रकार है।
- इस साइट का उपयोग औपचारिक उद्देश्यों के लिए किया गया है और अलग-अलग समय पर लोगों के कई अलग-अलग समूहों द्वारा संशोधित किया गया है।
- पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि साइट का पहला संशोधन प्रारंभिक मेसोलिथिक हंटर-संग्रहकर्ताओं द्वारा किया गया था। (भीमबेटका गुफा)
- शोधकर्ताओं और अन्य लोगों के अनुसार, स्टोनहेंज को पहले एक ड्रूयूड मंदिर माना जाता था, लेकिन अब यह एक दफन स्मारक, प्रमुखों के बीच एक बैठक स्थल या यहां तक कि एक खगोलीय "कंप्यूटर" भी हो सकता है।

अवश्य पढ़ें: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

SOURCE: BBC

काशी तमिल संगमम

संदर्भ: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर 2023 को काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन किये।

पृष्ठभूमि:-

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में काशी तमिल संगमम मंच को 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत करने वाला, भारत की एकता और विविधता का प्रमाण बताया।

काशी तमिल संगमम के बारे में:-

- दिनांक: 17 से 30 दिसंबर 2023
- स्थान: वाराणसी
- उद्घाटन: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नमो घाट पर इसका उद्घाटन किया।
- काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण पवित्र शहर काशी (वाराणसी) में शुरू होगा।
- यह भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध के कई पहलुओं का उत्सव मनाएगा।
- तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों से लगभग 1400 (प्रत्येक 200 व्यक्तियों के 7 समूह) लोगों के यात्रा करने की उम्मीद है।
- छात्रों (गंगा), शिक्षकों (यमुना), पेशेवरों (गोदावरी), आध्यात्मिक (सरस्वती), किसानों और कारीगरों (नर्मदा), लेखकों (सिंधु) और व्यापारियों और व्यवसायियों (कावेरी) के 7 समूहों का नाम सात पवित्र नदियों के नाम पर रखा गया है। भारत के लोग चेन्नई, कोयंबटूर और कन्याकुमारी से काशी तक यात्रा करेंगे।
- आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

काशी और तमिलनाडु के बीच संबंधों का इतिहास:-

- तमिलनाडु में कई परिवारों ने अपने बच्चों के नामकरण के लिए कैलासनाथ और काशीनाथ के नाम अपनाए, जैसे कि काशी और उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग।
- पांड्य राजवंश के राजा अधिवीर राम पांडियन ने काशी की तीर्थयात्रा के बाद तमिलनाडु के तेनकासी में एक शिव मंदिर समर्पित किया, जिनके पूर्वजों ने शिवकाशी की स्थापना की थी।
- तमिलनाडु के तुथुकुडी जिले के श्री वैकुंडम के संत कुमारगुरुपारा ने साहस के साथ काशी की सल्तनत के साथ सौदेबाजी में महारत हासिल की।
- संत कुमारगुरुपारा ने काशी पर कविताओं की एक व्याकरणिक रचना "काशी कलांबकम" लिखी है।

अवश्य पढ़ें: भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण

SOURCE: PIB

एंड्रियामेलो गुफा

प्रमुख विशेषताऐं:-

- मेडागास्कर गुफा कला अफ्रीका और एशिया के बीच प्राचीन संबंधों का संकेत देती है।
    - चित्रात्मक कला की खोज की गई है, जिसमें मानव और पशु-जैसी आकृतियों के साथ प्रकृति की छवियों का चित्रण किया गया है।
    - पहले, मेडागास्कर की रॉक कला में मुख्य रूप से बुनियादी प्रतीकों को प्रदर्शित किया जाता था। नए निष्कर्ष अधिक जटिल दृश्यों और आकृतियों को दर्शाते हैं।
- कुछ दृश्य मिस्र के टॉलेमिक काल (300-30 ईसा पूर्व) के रूपांकनों से मिलते जुलते हैं।
- प्रमुख छवियां होरस, थोथ, मा'अट और अनुबिस जैसे मिस्र के देवताओं का संकेत देती हैं।
- प्रतीक और लेख इथियोपियाई तथा अफ्रीकी-अरब दुनिया के साथ सांस्कृतिक संबंधों का सुझाव देते हैं।
- यह कला बोर्नियो की दो सहस्राब्दी पुरानी गुफा कला शैली से समानता रखती है।
- इस कला में मेडागास्कर के कम से कम तीन विलुप्त जानवरों को दर्शाया जा सकता है, जिसमें एक विशाल स्लॉथ लेमुर, एलीफैंट बर्ड और एक विशाल कछुआ शामिल है।

- सर्वव्यापी एम-आकार का प्रतीक अम्हारिक् वर्णमाला के "हॉट (hawt)" से मेल खाता है और कुछ ऑस्ट्रोनेशियन भाषाओं में "ब्रीथ ऑफ़ लाइफ" की अवधारणा से जुड़ा हुआ है।
- इस कला में ईसाई, मुस्लिम, हिंदू प्रतीकों और आधुनिक रूपांकनों का अभाव है, जो इसकी प्राचीन उत्पत्ति का संकेत देता है।
- महत्व: मालागासी के प्रारंभिक इतिहास के पुनर्निर्माण में इस खोज का महत्व है। (रत्नागिरी की पूर्व-ऐतिहासिक रॉक कला)

इस गुफा के बारे में:-

- यह मेडागास्कर के पश्चिमी भाग में स्थित है।
- यह गुफा Paysage Harmonieux Protege de Beanka के कार्स्टीकृत चूना पत्थर इलाके में स्थित है, जो इसकी अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचना में योगदान करती है।
- इसमें पार्क नेशनल डी बेमराहा शामिल है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- इसकी विशेषता चूना पत्थर जैसी घुलनशील चट्टानों के विघटन से उत्पन्न जटिल भूमिगत संरचनाएं हैं।

अवश्य पढ़ें: मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में बौद्ध गुफाएँ, मंदिर

स्रोत: द हिंदू

योगमाया मंदिर

संदर्भ: हाल ही में, योगमाया मंदिर के अब परित्यक्त हिस्से को दिल्ली की समन्वित जड़ों के प्रमाण के रूप में खोजा गया था।

पृष्ठभूमि:-

- मुगल-प्रायोजित संरचना से कंक्रीट की इमारत तक, महरौली में योगमाया मंदिर एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारक है, माना जाता है कि यह एक प्राचीन मंदिर के स्थान पर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह महाभारत काल के दौरान बना था, लेकिन जिसका अब कोई निशान मौजूद नहीं है।

योगमाया मंदिर के बारे में:-

- स्थान: महरौली, दिल्ली
- निर्मित: 1806 और 1837 के बीच अकबर द्वितीय के दरबार के एक कुलीन लाला सिधू मल द्वारा।
- प्राचीन जैन ग्रंथों में इस क्षेत्र को योगिनीपुरा के नाम से जाना जाता था।
- कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने स्वयं अपने शहर के विनाश से कुछ समय पहले यहां एक योगिनी मंदिर का संरक्षण किया था।
- इसमें देवी योगमाया की प्रतिकृति है, जिन्हें "शुद्ध देवी" भी कहा जाता है।
    - देवी को भगवान कृष्ण की बहन और दुर्गा का अवतार माना जाता है।
    - ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण महाकाव्य युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों द्वारा किया गया था।
- यह मंदिर कथित तौर पर मामलुक शासकों द्वारा नष्ट किए गए 27 मंदिरों में से एक था।
- इस्लामी शासकों द्वारा मंदिर को नष्ट किये जाने के बाद इसके जीर्णोद्धार का श्रेय हिंदू राजा सम्राट विक्रमादित्य हेमू को दिया जाता है।
- अनोखा त्यौहार 'फूलवालों की सैर' मनाया जाता है।

महत्व:-

- यह विविध समुदायों के बीच एकता का प्रतीक है।
- यह दिल्ली की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है।

अवश्य पढ़ें: होयसल मंदिर

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

पंडित मदन मोहन मालवीय

संदर्भ: हाल ही में प्रधानमंत्री ने पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर याद किया।

पृष्ठभूमि:-

- महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 'कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय' की 11 खंडों की पहली श्रृंखला का विमोचन किया।

पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में:-

- इनकी जयंती 25 दिसंबर को मनाई जाती है।

- वह एक भारतीय शिक्षाविद् और राजनीतिज्ञ हैं जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए उल्लेखनीय हैं।
- उन्हें एक उत्कृष्ट विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है।

योगदान:-

- उन्होंने 1906 में हिंदू महासभा की स्थापना की और 1915 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की स्थापना की।
- उन्होंने 1919 से 1938 तक कुलपति के रूप में कार्य किया।
- वह 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और चार बार - 1909, 1918, 1932 और 1933 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे।
- वह एक सफल लेजिस्लेटर थे, जिन्होंने 11 वर्षों (1909-20) तक इंपीरियल विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया।
- उन्होंने मुफ़्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का समर्थन किया, ब्रिटिश साम्राज्य में गिरमिटिया मज़दूरी की व्यवस्था का विरोध किया और रेलवे के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया।

उपलब्धियाँ:-

- उन्हें 'महामना' कहा जाता है।
- वर्ष 2015 में सरकार ने मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया।
- वर्ष 2016 में, भारतीय रेलवे ने नेता के सम्मान में वाराणसी-नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस शुरू की।
- पुस्तकें - भारतीय संवैधानिक सुधार, भाषण और लेख के मोंटागु-चेम्सफोर्ड प्रस्तावों की आलोचना।

जरूर पढ़ें: सत्येंद्र नाथ बोस

SOURCE: PIB

बचाव एवं सुरक्षा

बीएसएफ स्थापना दिवस

संदर्भ: हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएफ स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं।

पृष्ठभूमि:-

- प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया; "बीएसएफ के स्थापना दिवस पर, हम इस उत्कृष्ट बल की सराहना करते हैं, जिसने हमारी सीमाओं के संरक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हमारे राष्ट्र की रक्षा में उनकी वीरता और अटूट भावना उनके समर्पण का प्रमाण है। मैं प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों के दौरान बीएसएफ की भूमिका की भी सराहना करना चाहूंगा।

बीएसएफ स्थापना दिवस के बारे में:-

- बीएसएफ की स्थापना वर्ष 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद की गई थी।
- स्थापना दिवस वह दिन है जब बीएसएफ इकाई की स्थापना की गई थी।
- यह गृह मंत्रालय (एमएचए) के प्रशासनिक नियंत्रण में है और भारत संघ के पांच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है।
    - अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में असम राइफल्स (एआर), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) है।
    - इन्हें भारतीय सेना के साथ नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर और नक्सल विरोधी अभियानों में तैनात किया जाता है।
- बीएसएफ के पास अधिकारियों का अपना कैडर है, लेकिन इसके प्रमुख को महानिदेशक (डीजी) के रूप में नामित किया गया है, इसकी स्थापना के बाद से भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) का एक अधिकारी होता है।
- बीएसएफ प्राकृतिक आपदा के खिलाफ अभियान चलाता है और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में समर्पित सेवाओं का योगदान देता है।

जरूर पढ़ें: मोबाइल ऐप 'प्रहरी'

स्रोत: पीआईबी

स्कैटरड स्पाइडर

संदर्भ: FBI ने हाल ही में खतरनाक 'स्कैटरर्ड स्पाइडर' हैकर्स के बारे में चेतावनी जारी की।

पृष्ठभूमि:-

- संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने स्कैटरड स्पाइडर नामक हैकिंग समूह के बारे में संगठनों को चेतावनी जारी की है।

इसके बारे में:-

- यह एक हैकिंग समूह है जो दुनिया भर के विभिन्न संगठनों पर आक्रमण करने के लिए कुख्यात है।
- इस हैकर समूह को अन्य उपनामों से भी जाना जाता है, जिनमें स्टारफ्रॉड, UNC3944, स्कैटर स्वाइन और मडल्ड लिब्रा शामिल हैं।
- इसके सदस्यों की आयु 16 वर्ष से कम की हैं और प्राथमिक अंग्रेजी बोलने वाले हैं।
- इसकी तकनीकें: फ़िशिंग, पुश बॉम्बिंग, सिम स्वैप हमले और सोशल इंजीनियरिंग।
- पिछले हमलों में Riot गेम्स, डोरडैश और MailChimp जैसी प्रमुख कंपनियों को निशाना बनाया गया था।
- इसने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों का भी ध्यान आकर्षित किया।

अवश्य पढ़ें: भारत में साइबर हमले

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली

संदर्भ: हाल ही में अमेरिका ने मध्य पूर्व में सतह से हवा में मार करने वाली पैट्रियट मिसाइल प्रणाली भेजी है।

पृष्ठभूमि:-

- पेंटागन ने हाल ही में कहा कि वह क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों पर हाल के हमलों के जवाब में मध्य पूर्व में अतिरिक्त पैट्रियट वायु रक्षा

मिसाइल प्रणाली बटालियन भेजेगा।

पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के बारे में:-

- यह सतह से हवा में मार करने वाली निर्देशित मिसाइल प्रणाली है, इसे पहली बार 1980 के दशक में तैनात किया गया था।
- इसका नाम पैट्रियट (लक्ष्य पर अवरोधन करने के लिए चरणबद्ध एरे ट्रैकिंग रडार) रडार प्रणाली के नाम पर रखा गया है, जिसका उपयोग इसमें 150 किमी से अधिक की रेंज के साथ किया जाता है।
- इसने अमेरिकी सेना की प्राथमिक उच्च से मध्यम वायु रक्षा (HIMAD) प्रणाली और मध्यम सामरिक वायु रक्षा प्रणाली के रूप में क्रमशः नाइके हरक्यूलिस प्रणाली और MIM-23 हॉक प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया।
- इसे शुरुआत में अमेरिकी एयरोस्पेस और रक्षा दिग्गज रेथियॉन टेक्नोलॉजीज कॉर्प द्वारा ऊंची उड़ान वाले विमानों को रोकने के लिए एक प्रणाली के रूप में विकसित किया गया था।
- इसे बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे अन्य खतरों का मुकाबला करने के लिए 1980 के दशक में संशोधित किया गया था।
- वर्तमान में, पैट्रियट बैटरियां बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज़ मिसाइलों, ड्रोन, जेट और "अन्य खतरों" से बचाव कर सकती हैं।
- इसे अमेरिका सहित 18 देशों में तैनात किया गया है।

लिमिटेशन:-

- यह कम ऊंचाई पर उड़ने वाले छोटे ड्रोनों से सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है।
- एक पैट्रियट बैटरी को संचालित करने और बनाए रखने के लिए 90 सैनिकों की आवश्यकता हो सकती है।

अवश्य पढ़ें: S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली

SOURCE: MSN

विनबैक्स-2023

संदर्भ: भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास VINBAX-2023 के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए हनोई, वियतनाम पहुंची।

पृष्ठभूमि:-

- भारतीय दल में बंगाल इंजीनियर ग्रुप की एक इंजीनियर रेजिमेंट के 39 कर्मी और आर्मी मेडिकल कोर के छह कर्मी शामिल हैं।
- वियतनाम पीपुल्स आर्मी की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व भी 45 कर्मियों द्वारा किया जाएगा।

VINBAX-2023 के बारे में:-

- दिनांक: 11 से 21 दिसंबर 2023 तक
- स्थान: हनोई, वियतनाम
- VINBAX अभ्यास वर्ष 2018 में शुरू किया गया था और पहला संस्करण जबलपुर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था।
- यह भारत और वियतनाम में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। (सैन्य अभ्यास)
- पिछला संस्करण अगस्त 2022 में चंडीमंदिर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया था।
- उद्देश्य: सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देना, अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देना और शांति स्थापना संचालन पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत दोनों पक्षों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना।
- संयुक्त अभ्यास से दोनों टुकड़ियों के बीच समझ और अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देने और मित्र सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

अवश्य पढ़ें: भारत और वियतनाम संबंध

SOURCE: PIB

भारतीय तट रक्षक

संदर्भ: हाल ही में, भारतीय तटरक्षक बल ने दक्षिण तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अपने जहाज, विमान और आपदा राहत दल तैनात किए हैं।

पृष्ठभूमि:-

- तटरक्षक बल ने कहा, उन्होंने तूतीकोरिन और आसपास के इलाकों में बाढ़ के पानी में फंसे 200 लोगों की जान बचाई है।

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के बारे में:-

- स्थापना: अगस्त 1978

- मुख्यालय: नई दिल्ली
- मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय
- ICG, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल, 1978 के तटरक्षक अधिनियम द्वारा भारत के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में स्थापित किया गया था।
- क्षेत्राधिकार: भारत का अतिप्रादेशिक जलक्षेत्र, जिसमें इसके सन्निहित क्षेत्र और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं।
- यह एक सशस्त्र बल, सर्च एवं बचाव और समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है।
- प्रभावी कमांड और नियंत्रण के लिए, भारत के समुद्री क्षेत्रों को पांच तटरक्षक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, अर्थात्:
    - उत्तर-पश्चिम (गांधीनगर में क्षेत्रीय मुख्यालय)
    - पश्चिम (मुंबई में क्षेत्रीय मुख्यालय)
    - पूर्व (चेन्नई में क्षेत्रीय मुख्यालय)
    - उत्तर-पूर्व (कोलकाता में क्षेत्रीय मुख्यालय)
    - अंडमान और निकोबार (पोर्ट ब्लेयर में क्षेत्रीय मुख्यालय)

कार्य:-

- तस्करी को रोकना। (रक्षा अधिग्रहण परिषद)
- यह समुद्री पर्यावरण के लिए जिम्मेदार है और भारतीय जल में तेल रिसाव की प्रतिक्रिया के लिए समन्वय प्राधिकरण है।
- यह एक मजबूत तटीय सुरक्षा तंत्र स्थापित करने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में भी काम कर रहा है।

अवश्य पढ़ें: रक्षा में आत्मनिर्भरता

SOURCE: AIR

आईएनएस इम्फाल

संदर्भ: हाल ही में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने पर गर्व व्यक्त किया।

पृष्ठभूमि:-

- रक्षा में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की सराहना करते हुए, प्रधान मंत्री ने X पर पोस्ट किया:
  "भारत के लिए गर्व का क्षण क्योंकि आईएनएस इम्फाल को हमारी नौसेना में शामिल किया गया है, जो रक्षा में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का एक प्रमाण है। यह हमारी नौसेना उत्कृष्टता और इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक है। आत्मनिर्भरता के लिए इस मील के पत्थर में शामिल सभी लोगों को बधाई। हम अपनी सुरक्षा बनाए रखेंगे।" समुद्र और हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाना।"

आईएनएस इंफाल के बारे में:-

- यह स्टील्थ-निर्देशित मिसाइल विध्वंसक के प्रोजेक्ट 15बी वर्ग का तीसरा जहाज है।
    - P15B क्लास का पहला जहाज, INS विशाखापत्तनम, 2021 में चालू किया गया था।
    - दूसरा जहाज INS मोरमुगाओ 2022 में चालू किया गया था।
    - चौथा, INS सूरत, 2022 में लॉन्च किया गया था।
- इंफाल महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए आवास के साथ कमीशन किया गया पहला नौसैनिक युद्धपोत था।
- जहाज दो हेलीकॉप्टरों से सुसज्जित है और इसका निर्माण स्वदेशी स्टील "DMR 249A" का उपयोग करके किया गया है।
- यह भारत में निर्मित सबसे बड़े विध्वंसक जहाजों में से एक है।
  यह स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी रोधी हथियार और सेंसर है।
- यह सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली बराक-8 मिसाइलों से लैस है।
- दुश्मन की पनडुब्बियों, सतह के युद्धपोतों, जहाज-रोधी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के खिलाफ इसकी सर्वांगीण क्षमता इसे सहायक जहाजों के बिना स्वतंत्र रूप से संचालित करने में सक्षम बनाएगी।
- जहाज एक शक्तिशाली संयुक्त गैस और गैस प्रणोदन संयंत्र (COGAG) द्वारा संचालित है।

अवश्य पढ़ें: मोरमुगाओ: भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक

SOURCE: PIB

हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS)

संदर्भ: हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स (सीओसी) का 8वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था।

पृष्ठभूमि:-

- इस कार्यक्रम में 27 सदस्य/पर्यवेक्षक देशों के नौसेना प्रमुखों/वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने तीन सदस्यीय भारतीय नौसेना प्रतिनिधिमंडल के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया।

भारतीय महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस)-2023 के बारे में:-

- दिनांक: 19 से 22 दिसंबर, 2023
- स्थान और चाय (Venue and Chai): बैंकॉक, थाईलैंड।
- IONS की कल्पना वर्ष 2008 में भारतीय नौसेना द्वारा की गई थी।
- उद्देश्य: क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा के लिए एक खुला और समावेशी मंच प्रदान करके हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना जिससे आगे की राह पर आम समझ पैदा हो सके।
- IONS का उद्घाटन संस्करण फरवरी 2008 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय नौसेना दो साल (2008 - 2010) के लिए अध्यक्ष थी।
- एक उल्लेखनीय विकास आधिकारिक IONS फ्लैग के रूप में भारत द्वारा डिज़ाइन किए गए ध्वज का चयन था।
- वर्ष 2025 के अंत में भारत में आयोजित होने वाली 9वीं सीओसी के दौरान भारत को IONS (2025-27) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने का भी कार्यक्रम है।
- नवीनतम पर्यवेक्षक के रूप में कोरिया गणराज्य की नौसेना का स्वागत किया गया।

सदस्य समूह:-

- दक्षिण एशियाई तटीय क्षेत्र - बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, सेशेल्स, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र)।
- दक्षिण पूर्व एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई तटीय क्षेत्र - ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर-लेस्ते।
- पूर्वी अफ्रीकी तटीय क्षेत्र - फ्रांस (रीयूनियन), केन्या, मॉरीशस, मोज़ाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया।
- पश्चिम एशियाई तटीय क्षेत्र - ईरान, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात।

अवश्य पढ़ें: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास/कटलैस एक्सप्रेस 2023

SOURCE: PIB

सरकारी पहल, योजनाएँ और नीतियाँ, संगठन

"ग्राम मंचचित्र" ऐप

संदर्भ: हाल ही में, पंचायती राज मंत्रालय ने "ग्राम मंचचित्र" ऐप लॉन्च किया।

पृष्ठभूमि:-

- "ग्राम मंच" ऐप के संबंध में यह जानकारी केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

ग्राम मंचित्रा एप्लिकेशन के बारे में:-

- लॉन्च: अक्टूबर 2019
- मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय
- उद्देश्य: ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को प्रोत्साहित करना।

ग्राम मंच की मुख्य विशेषताएं:-

- यह "ग्राम मंच" जीआईएस एप्लीकेशन और मोबाइल आधारित समाधान है।
- जीआईएस एप्लिकेशन भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके योजना बनाने में ग्राम पंचायतों का समर्थन करता है।

- जीआईएस भौगोलिक रूप से संदर्भित जानकारी का विश्लेषण और प्रदर्शित करता है।
- यह विकासात्मक कार्यों की कल्पना के लिए एक एकीकृत भू-स्थानिक मंच प्रदान करता है।
- mActionSoft, एक मोबाइल-आधारित समाधान, जीपीएस निर्देशांक को शामिल करते हुए जियो-टैग के साथ तस्वीरें कैप्चर करता है।
- एसेट की जियो-टैगिंग काम से पहले, काम के दौरान और बाद में होती है।
- सूचना भंडार में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संचयन, स्वच्छता, कृषि, चेक बांध और सिंचाई चैनल जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- बेहतर विज़ुअलाइज़ेशन के लिए mActionSoft का उपयोग करके भू-टैग की गई संपत्तियां "ग्राम मनचित्र" के साथ एकीकृत होती हैं।
- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना रिपोर्ट और मिशन अंत्योदय से भी जुड़ा हुआ है। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) रिपोर्ट और मिशन अंत्योदय से भी जुड़ा हुआ है।

अवश्य पढ़ें: ई-पंचायत सुविधा

SOURCE: PIB

इन्फिनिटी फोरम 2.0

संदर्भ: हाल ही में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम - इन्फिनिटी फोरम 2.0 के दूसरे संस्करण को संबोधित किया।

पृष्ठभूमि:-

- केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिष्ठित वक्ताओं में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा रेलवे, संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए।

इन्फिनिटी फोरम 2.0 के बारे में:-

- IFSCA और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी, गिफ्ट सिटी द्वारा होस्ट किया गया।
- इन्फिनिटी फोरम-टू -गिफ्ट-आईएफएससी: नर्व सेंटर फॉर न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज विषय पर केंद्रित होगा।
- वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के प्री-कर्सर के रूप में आयोजित किया गया।
- हाइब्रिड मोड में आयोजित, गिफ्ट सिटी में केवल-आमंत्रित व्यक्तिगत कार्यक्रम और दुनिया भर में आभासी भागीदारी के साथ हुआ।
- पहला संस्करण दिसंबर 2021 में आयोजित किया गया।
- इसमें भारत और विश्व स्तर पर वित्तीय क्षेत्र के दिग्गजों की भागीदारी और चर्चा शामिल है।

अवश्य पढ़ें: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई)

SOURCE: AIR

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी (GPAI) शिखर सम्मेलन

संदर्भ: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट' (GPAI) का उद्घाटन किया।

पृष्ठभूमि:-

- उन्होंने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है।
- श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामाजिक विकास और समावेशी विकास के लिए है।

इसके बारे में:-

- दिनांक: दिसंबर 2023
- स्थान: भारत मंडपम, नई दिल्ली
- यह एआई पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को भरने के लिए 29 सदस्य देशों के साथ एक बहु-हितधारक पहल है।
- भारत वर्ष 2024 में GPAI का प्रमुख अध्यक्ष है।
- वर्ष 2020 में GPAI के संस्थापक सदस्यों में से एक, GPAI के वर्तमान आने वाले सपोर्ट चेयर और वर्ष 2024 में GPAI के लिए लीड चेयर के रूप में, भारत ने 12-14 दिसंबर, 2023 तक वार्षिक GPAI शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है।
- शिखर सम्मेलन के अन्य आकर्षणों में अनुसंधान संगोष्ठी, एआई गेमचेंजर्स अवार्ड और इंडिया एआई एक्सपो शामिल हैं।
- इस शिखर सम्मेलन में देश भर से 50+ GPAI विशेषज्ञ और 150+ वक्ता शामिल होंगे।
- इसके अलावा, दुनिया भर के शीर्ष एआई गेमचेंजर्स इंटेल, रिलायंस जियो, गूगल, मेटा, AWS, योटा आदि सहित विभिन्न आयोजनों में भाग लेंगे।

अवश्य पढ़ें: RAISE 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन

SOURCE: AIR

भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना

संदर्भ: हाल ही में, भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की गई।

पृष्ठभूमि:-

- इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह राष्ट्रीय वन प्रमाणन योजना देश में स्थायी वन प्रबंधन और कृषिवानिकी को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण प्रदान करती है।

इसके बारे में:-

- लॉन्च: वर्ष 2023 में
- उद्देश्य: वनों और कृषि वानिकी के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
- इस योजना में वन प्रबंधन प्रमाणीकरण, वन प्रबंधन प्रमाणन के बाहर पेड़ और हिरासत प्रमाणीकरण की श्रृंखला शामिल है।
- इसमें राज्य वन विभाग, व्यक्तिगत किसान, या कृषि वानिकी और कृषि वानिकी में लगे किसान उत्पादक संगठन, साथ ही मूल्य श्रृंखला में अन्य लकड़ी-आधारित उद्योग शामिल हैं।
- वन प्रबंधन प्रमाणन भारतीय वन प्रबंधन मानक पर आधारित है, जिसमें 8 मानदंड, 69 संकेतक और 254 सत्यापनकर्ता शामिल हैं, जो इस वर्ष की शुरुआत में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय कार्य योजना कोड 2023 का एक अभिन्न अंग है।
- वनों के बाहर एक अलग पेड़ मानक अब योजना के एक भाग के रूप में पेश किया गया है।
- **पर्यवेक्षण:** भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना की देखरेख भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन परिषद द्वारा की जाएगी, जो एक बहुहितधारक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगी।
- **कार्यान्वयन:** भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल योजना संचालन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और भारतीय वन तथा लकड़ी प्रमाणन योजना के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा।
- **प्रत्यायन:** भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाणन निकायों को मान्यता देगा जो स्वतंत्र ऑडिट करेगा तथा योजना के तहत निर्धारित मानकों पर विभिन्न संस्थाओं के पालन का आकलन करेगा।

MUST READ:Natural Farming

SOURCE: PIB

राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपॉजिटरी पोर्टल

संदर्भ: हाल ही में, खान मंत्रालय ने अन्वेषण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया।

पृष्ठभूमि:-

- लॉन्च समारोह में केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी, कोयला, खान और रेलवे राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे की उपस्थिति इसमें शामिल है।

राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल (एनजीडीआर) के बारे में:-

- शुरू हुआ : 19 दिसंबर 2023।
- द्वारा लॉन्च किया गया: खान मंत्रालय
- NGDR पोर्टल नई दिल्ली में एक समारोह में लॉन्च किया जाएगा। (राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2022)
- उद्देश्य: अन्वेषण में नवाचार को बढ़ावा देना।
- NGDR पूरे देश में भू-स्थानिक जानकारी तक पहुंचने, साझा करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन मंच है।
- इसका नेतृत्व भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइंफॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी-एन) द्वारा किया जा रहा है।
- यह महत्वपूर्ण भूविज्ञान डेटा को लोकतांत्रिक बनाने, अमूल्य संसाधनों तक अभूतपूर्व पहुंच के साथ उद्योगों और शिक्षा जगत में हितधारकों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिनिधित्व करता है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के बारे में:-

- **स्थापना:** 1851, मुख्यालय: कोलकाता
- इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता में स्थित हैं और राज्य इकाई कार्यालय देश के लगभग सभी राज्यों में हैं।
- जीएसआई खान मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।
- इसकी स्थापना मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडार खोजने हेतु की गई थी, जिसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जानकारी और खनिज संसाधन मूल्यांकन बनाने और अद्यतन करने से संबंधित था।
- उद्देश्यों को जमीनी सर्वेक्षण, वायु-जनित और समुद्री सर्वेक्षण, खनिज पूर्वेक्षण और जांच, बहु-विषयक भूवैज्ञानिक, भू-तकनीकी, भू-पर्यावरणीय और प्राकृतिक खतरों के अध्ययन, ग्लेशियोलॉजी, भूकंपीय-टेक्टोनिक अध्ययन और मौलिक अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

BISAG-N-- भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान के बारे में:-

- मंत्रालय: MeitY, भारत सरकार। (भारतीय खान ब्यूरो)
- वर्तमान में, BISAG गुजरात सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक राज्य एजेंसी है, जो गांधीनगर, गुजरात में स्थित है।
- यह 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी है।
- उद्देश्य: प्रौद्योगिकी विकास और प्रबंधन, अनुसंधान और विकास करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्षमता निर्माण को सुविधाजनक बनाना तथा भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता विकास का समर्थन करना।
- इसने प्रमुख मंत्रालयों और लगभग सभी राज्यों के लिए जीआईएस और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों को लागू किया है।
- इस उद्देश्य के लिए, भू-स्थानिक विज्ञान (जीआईएस रिमोट सेंसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, फोटोग्रामेट्री, जीपीएस, सेल फोन आदि), सूचना विज्ञान प्रणाली (एमआईएस, डेटाबेस, ईआरपी, परियोजना प्रबंधन, वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि) और गणित विज्ञान प्रणाली (ज्यामिति, द्रव, यांत्रिकी, त्रिकोणमिति, बीजगणित आदि) को बीआईएसएजी द्वारा इन-हाउस एकीकृत किया गया है।

अवश्य पढ़ें: 'भारत के आर्द्रभूमि' पोर्टल

SOURCE: PIB

स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2023

संदर्भ: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 19 दिसंबर, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ चर्चा किये।

पृष्ठभूमि:-

- इस अवसर पर श्री मोदी प्रतिभागियों को संबोधित भी किया।

स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2023 (SIH) के बारे में:-

- लॉन्च: अगस्त 2023
- उद्देश्य: उत्पाद नवाचार की संस्कृति और समस्या-समाधान की मानसिकता विकसित करना।
- SIH छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करने की एक राष्ट्रव्यापी पहल है। (एग्री इंडिया हैकथॉन)
- यह शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और इंटर-इंस्टीट्यूशनल इनक्लूसिव इनोवेशन सेंटर (i4C) की एक पहल है।
- उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए एसआईएच 2017 से हर साल दो प्रारूपों, एसआईएच सॉफ्टवेयर और एसआईएच हार्डवेयर संस्करणों में आयोजित किया जाता है।
- SIH 2023 का ग्रैंड फिनाले 19 से 23 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है।
- थीम: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्मार्ट शिक्षा, आपदा प्रबंधन, रोबोटिक्स और ड्रोन, विरासत और संस्कृति और अन्य सहित विभिन्न विषयों पर समाधान प्रदान करने के लिए इस वर्ष ग्रैंड फिनाले के लिए कुल एक हजार 282 टीमों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

अवश्य पढ़ें: 'हैक द क्राइसिस-इंडिया' हैकथॉन

स्रोत: AIR

'रेल कौशल विकास योजना'

संदर्भ: हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे की 'रेल कौशल विकास योजना' के स्नातकों को रेलवे की नौकरियों के लिए

प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

पृष्ठभूमि:-

- यह बयान प्रशिक्षित युवाओं के लिए नौकरी की प्राथमिकताओं के संबंध में भाजपा सांसद नारायण कोरगप्पा के एक प्रश्न के उत्तर के रूप में आया है।

रेल कौशल विकास योजना के बारे में:-

- लॉन्च: सितंबर, 2021
- मंत्रालय: रेल मंत्रालय
- उद्देश्य: गुणात्मक सुधार लाने के लिए युवाओं को कई व्यवसायों में प्रशिक्षण कौशल प्रदान करना।
- यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत एक उप-योजना है।

मुख्य विशेषताएं:-

- कौशल विकास योजना चौदह (14) उद्योग-प्रासंगिक तकनीकी ट्रेडों जैसे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, फिटर आदि में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करती है।
- इस योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।
- प्रतिभागियों का चयन मैट्रिक के अंकों के आधार पर ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में से किया जाएगा।
- जिन अभ्यर्थियों ने दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है और जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है, वे आवेदन करने के पात्र हैं।
- कार्यक्रम की समाप्ति के बाद, प्रशिक्षुओं को एक मानकीकृत मूल्यांकन पास करना होगा जिसके बाद राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान द्वारा आवंटित ट्रेड में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

महत्व:-

- इससे युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार होगा और साथ ही स्वरोजगार के कौशल में भी सुधार होगा।
- यह उन लोगों की भी ज़रूरतें पूरी करेगा जो री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग के माध्यम से ठेकेदारों के साथ काम कर रहे हैं।

जरूर पढ़ें: पीएम स्वनिधि योजना

SOURCE: FINANCIAL EXPRESS

भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम

संदर्भ: हाल ही में, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत-एनसीएपी) के तहत क्रैश टेस्टिंग का पहला दौर पूरा हुआ।

पृष्ठभूमि:-

- टाटा मोटर्स के घरेलू स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन (एसयूवी) टाटा सफारी और टाटा हैरियर को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत-एनसीएपी) के तहत क्रैश-टेस्ट किए जाने के बाद उच्चतम फाइव स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है।
- वे पहली दो कारें हैं जिन्हें नई प्रणाली के तहत वयस्क यात्रियों की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के लिए उच्चतम रेटिंग प्राप्त हुई है।

इसके बारे में:-

- लॉन्च: वर्ष 2023 में
- कार्यान्वयन: 1 अक्टूबर, 2023।
- मंत्रालय: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।
- उद्देश्य: भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाना।
- भारत एनसीएपी एक नया कार सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम है जो क्रैश परीक्षणों में उनके प्रदर्शन के आधार पर ऑटोमोबाइल को 'स्टार रेटिंग' देने की एक प्रणाली का प्रस्ताव करता है।
- यह 3.5 टन से कम वजन वाले और आठ लोगों तक बैठने में सक्षम यात्री वाहनों के लिए एक सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम है।

भारत एनसीएपी की मुख्य विशेषताएं:-

- यह क्रैश परीक्षणों में उनके प्रदर्शन के आधार पर ऑटोमोबाइल को 'स्टार रेटिंग' देने की एक व्यवस्था का प्रस्ताव करता है।
- यह एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (एओपी), चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (सीओपी), और सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज (एसएटी) जैसे मापदंडों पर एक और फाइव स्टार के बीच वाहनों को आवंटित करेगा।
- भारत एनसीएपी मानक वैश्विक बेंचमार्क के अनुरूप है।

- इस कार्यक्रम के लिए वाहनों का परीक्षण आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ परीक्षण एजेंसियों पर किया जाएगा।

NCAP के लाभ:

- भारत में सुरक्षा के प्रति संवेदनशील कार बाजार विकसित करना और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना।
- बढ़ी हुई सुरक्षा और निर्यात क्षमता।
- भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को आत्मनिर्भर बनाना।

अवश्य पढ़ें: इलेक्ट्रिक वाहन

SOURCE: HINDUSTAN TIMES

RAMP (एमएसएमई उत्पादकता बढ़ाना और तेज करना) कार्यक्रम

संदर्भ: हाल ही में, एमएसएमई मंत्रालय ने RAMP (एमएसएमई उत्पादकता बढ़ाना और तेज करना) कार्यक्रम के तहत 3 उप-योजनाएं शुरू कीं।

पृष्ठभूमि:-

- MSME मंत्री नारायण राणे ने व्यवसाय में टिकाऊ प्रौद्योगिकी को अपनाने को प्रोत्साहित करने, परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और विलंबित भुगतान मुद्दे को संबोधित करने के लिए मंत्रालय के मौजूदा RAMP (एमएसएमई उत्पादकता बढ़ाना और बढ़ाना) कार्यक्रम के तहत तीन उप-योजनाएं शुरू कीं।

RAMP (MSME उत्पादकता बढ़ाना और तेज करना) कार्यक्रम के बारे में:-

- लॉन्च: 30 जून 2022।
- मंत्रालय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय।
- उद्देश्य: मौजूदा एमएसएमई योजनाओं के प्रभाव को बढ़ाने के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में एमएसएमई की कार्यान्वयन क्षमता और कवरेज को बढ़ाना।

RAMP की मुख्य विशेषताएं:-

- RAMP एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- यह योजना मान्यता प्राप्त चुनौती क्षेत्रों में MSME को लक्षित हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए विनियामक, वित्तीय और कार्यान्वयन सुधारों के साथ-साथ फर्म-स्तरीय पहुंच सुधारों को लागू करेगी।
- इसका उद्देश्य संस्थानों को मजबूत करना, केंद्र-राज्य भागीदारी को बढ़ाना, विलंबित भुगतान के मुद्दों को संबोधित करना और एमएसएमई को हरित बनाना तथा मौजूदा एमएसएमई योजनाओं के प्रभाव को बढ़ाने के साथ राज्यों में कार्यान्वयन क्षमता और एमएसएमई कवरेज को बढ़ाना है।

पात्रता:-

- MSME को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- MSME के पास वैध उद्योग आधार नंबर (UAN) होना चाहिए।

लाभ:-

- MSME क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान: यह प्रतिस्पर्धात्मकता के मोर्चे पर मौजूदा एमएसएमई योजनाओं के प्रभाव को बढ़ाकर एमएसएमई क्षेत्र में सामान्य और कोविड से संबंधित चुनौतियों का समाधान करेगा।
- MSME में अपर्याप्त रूप से संबोधित ब्लॉकों को संबोधित करना: यह अन्य चीजों के अलावा क्षमता निर्माण, हैंडहोल्डिंग, कौशल विकास, गुणवत्ता संवर्धन, तकनीकी उन्नयन, डिजिटलीकरण, आउटरीच और विपणन प्रचार के अपर्याप्त रूप से संबोधित ब्लॉकों को मजबूत करेगा।
- रोजगार उत्पन्न करना: राज्यों के सहयोग से यह कार्यक्रम रोजगार प्रवर्तक, बाजार प्रवर्तक और वित्त सुविधा प्रदान करने वाला होगा और कमजोर वर्गों और हरित पहलों का समर्थन करेगा।
- व्यापक औपचारिकता की शुरुआत: उन राज्यों में जहां एमएसएमई की उपस्थिति निचले स्तर पर है, कार्यक्रम आरएएमपी के तहत कवर की गई योजनाओं के उच्च प्रभाव के परिणामस्वरूप बड़ी औपचारिकता की शुरूआत करेगा।

आत्मनिर्भर भारत मिशन को लागू करना:

- RAMP उद्योग मानकों और प्रथाओं में नवाचार और वृद्धि को बढ़ावा देकर और एमएसएमई को आवश्यक तकनीकी इनपुट प्रदान करके आत्मनिर्भर भारत मिशन का पूरक होगा।

अवश्य पढ़ें: एमएसएमई को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना

SOURCE: FINANCIAL EXPRESS

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)

संदर्भ: हाल ही में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) पर आईईसी अभियान शुरू किया।

पृष्ठभूमि:-

- देश भर के 200 जिलों में 22000 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), बहुसंख्यक जनजातीय बस्तियों और पीवीटीजी परिवारों तक पहुंचने के उद्देश्य से, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत एक सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान की शुरुआत की है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के बारे में:-

- लॉन्च: दिसंबर, 2023।
- मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय+ 8 अन्य मंत्रालय।
- उद्देश्य: जागरूकता बढ़ाना और पीवीटीजी बहुसंख्यक आदिवासी बस्तियों में सरकारी योजनाओं की 100% संतृप्ति सुनिश्चित करना।
- 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फैले 75 समुदायों की पहचान पीवीटीजी के रूप में की गई है।
- फोकस क्षेत्रों में शामिल हैं।
- फोकस क्षेत्रों के साथ 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप- आवास, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कनेक्टिविटी।
- मिशन अगले तीन वर्षों तक संचालित होगा।

मुख्य विशेषताएं:-

- आईईसी अभियान प्रारंभ में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 100 जिलों, 15,000 पीवीटीजी बस्तियों में शुरू हो गया है।
- दूसरे चरण में शेष जिलों को कवर किया जाएगा।
- इस अभियान का उद्देश्य पीवीटीजी परिवारों को व्यक्तिगत अधिकारों और बस्तियों को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करना है।
- आधार कार्ड, सामुदायिक प्रमाण पत्र और जन धन खाते प्रदान किए जाएंगे क्योंकि ये अन्य योजनाओं जैसे आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड आदि के लिए बुनियादी आवश्यकताएं हैं।
- यह हर उस पीवीटीजी परिवार को कवर करेगा जो अभी तक पहुंच से बाहर है और उनके डोर पर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- इन कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए हाट बाजार, CSC, ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी, बहुउद्देशीय केंद्र, वन विकास केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र जैसे स्थानों का उपयोग किया जाएगा।

अवश्य पढ़ें: सतत विकास में जनजातीय संस्कृति का महत्व

SOURCE: PIB

लखपति दीदी

संदर्भ: हाल ही में, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया।

पृष्ठभूमि:-

- इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है क्योंकि स्वयं सहायता समूह समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों, विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

लखपति दीदी योजना के बारे में:-

- **लॉन्च:** वर्ष 2023 में
- **उद्देश्य:** ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम शुरू करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें सशक्त बनाना।
- यह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना और संचालन में महिलाओं को प्रेरित करने तथा समर्थन करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- यह योजना ग्रामीण गांवों की 2 करोड़ महिलाओं को कवर करती है, उन्हें कौशल विकास पहल के माध्यम से सशक्त बनाती है।
- महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से अधिक कमा सकें।
- कवर किए गए कौशल: प्लंबिंग, एलईडी बल्ब बनाना, और ड्रोन का संचालन और मरम्मत करना, अन्य।

- इस पहल का उद्देश्य कृषि परिदृश्य को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है और लगभग 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन के संचालन और मरम्मत में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

लाभ:-

- यह प्रशिक्षण न केवल आय सृजन के नए मार्ग तैयार करेगा बल्कि महिलाओं को अत्याधुनिक कौशल से भी लैस करेगा। (राष्ट्रीय महिला आयोग)

अवश्य पढ़ें: स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) की पुनर्कल्पना

SOURCE: PIB

प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)

संदर्भ: केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली मंत्री ने हाल ही में बताया है कि प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के मुख्य उद्देश्य क्या हैं।

पृष्ठभूमि:-

- इनमें कृषि क्षेत्र का डी-डीजलीकरण, किसानों को जल और ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना, किसानों की आय में वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाना शामिल है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के बारे में:-

- लॉन्च: वर्ष 2019 में
- मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)।

पीएम कुसुम के उद्देश्य:-

- कृषि के लिए सौर सिंचाई पंप स्थापित करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसानों को सब्सिडी देना।
- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) के हिस्से के रूप में 2030 तक गैर-जीवाश्म-ईंधन स्रोतों से विद्युत ऊर्जा की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता का सम्मान करना।
  O ये UNFCCC के तहत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में इच्छित कटौती हैं।
- प्रत्येक किसान को ट्यूबवेल और पंप सेट स्थापित करने के लिए 60% सब्सिडी मिलेगी।
- उन्हें कुल लागत का 30% सरकार की ओर से ऋण के रूप में भी मिलेगा।

पीएम कुसुम के लाभ:-

डिस्कॉम के लिए:-

- कृषि के लिए बिजली पर अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है और इसे अक्सर डिस्कॉम की खराब वित्तीय स्थिति का मुख्य कारण कहा जाता है।
- यह योजना कृषि क्षेत्र पर सब्सिडी का बोझ कम करके डिस्कॉम के वित्तीय स्वास्थ्य का समर्थन करेगी।

राज्यों के लिए:-

- यह योजना विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी और ट्रांसमिशन घाटे को कम करेगी।
- राज्य सरकारों के लिए, यह सिंचाई के लिए उनके सब्सिडी परिव्यय को कम करने का एक संभावित तरीका है।
- इससे राज्यों को आरपीओ (नवीकरणीय खरीद दायित्व) लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

किसानों के लिए:-

- यदि किसान अतिरिक्त बिजली बेचने में सक्षम हैं, तो उन्हें बिजली बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इसका मतलब है कि वे भूजल का कुशल उपयोग करेंगे और किसानों को जल सुरक्षा प्रदान करेंगे।

पर्यावरण के लिए:-

- विकेन्द्रीकृत सौर-आधारित सिंचाई प्रदान करने से प्रदूषणकारी डीजल से दूर रहने में मदद मिलेगी।
- यह छतों और बड़े पार्कों के बीच की मध्यवर्ती सीमा में सौर ऊर्जा उत्पादन में कमी की भरपाई करेगा।

अवश्य पढ़ें: भारत में सौर ऊर्जा

SOURCE: PIB

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

संदर्भ: हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के SHG को

शामिल करने के लिए रिलायंस रिटेल के JioMart के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

पृष्ठभूमि:-

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने में मदद करने के अपने प्रयासों के तहत रिलायंस रिटेल के जिओमार्ट के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि ग्रामीण एसएचजी कारीगरों को सशक्त बनाया जा सके।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के बारे में:-

- **लॉन्च:** जून 2011
- **मंत्रालय:** ग्रामीण विकास मंत्रालय
- **उद्देश्य:** 2022-23 तक चरणबद्ध तरीके से लगभग 10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंचकर गरीबी को कम करना ताकि लाभकारी स्व-रोज़गार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंच बनाई जा सके, जिसके परिणामस्वरूप गरीबों के लिए टिकाऊ और विविध आजीविका विकल्प उपलब्ध होंगे।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- DAY-NRLM को वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा पूर्ववर्ती स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (SGSY) का पुनर्गठन करके लॉन्च किया गया था।
- नए कार्यक्रम का डिज़ाइन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, केरल और तमिलनाडु राज्यों में बड़े पैमाने पर समुदाय-आधारित परियोजनाओं से प्राप्त अनुभवों पर आधारित था।
- नवंबर 2015 में, कार्यक्रम का नाम बदलकर DAY-NRLM कर दिया गया।

मुख्य विशेषताएं:-

- DAY-NRLM भारत सरकार का एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है।
- यह ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार लाने की दुनिया की सबसे बड़ी पहल है।

वैल्यू:-

- सबसे गरीबों का समावेश
- पारदर्शिता एवं जवाबदेही
- सभी चरणों में गरीबों और उनके संस्थानों का स्वामित्व और प्रमुख भूमिका - योजना, कार्यान्वयन और निगरानी
- सामुदायिक सेल्फ -रिलायंस एवं स्वावलंबन

मिशन के घटक:-चार मुख्य घटकों में निवेश:-

- सामाजिक गतिशीलता और ग्रामीण गरीबों के स्व-प्रबंधित और वित्तीय रूप से टिकाऊ सामुदायिक संस्थानों को बढ़ावा देना और मजबूत करना: प्रत्येक चिन्हित ग्रामीण गरीब परिवार से कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्क के तहत लाया जाना है।
- ग्रामीण गरीबों का वित्तीय समावेशन:-यह वित्तीय समावेशन के मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर काम करता है। मांग पक्ष पर, यह गरीबों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है और एसएचजी और उनके संघों को उत्प्रेरक पूंजी प्रदान करता है।
- सतत आजीविका:-NRLM अपने तीन स्तंभों: भेद्यता में कमी, आजीविका वृद्धि और रोजगार के माध्यम से गरीबों के मौजूदा आजीविका पोर्टफोलियो को स्थिर करने और बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास और अभिसरण:-NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण पर अत्यधिक बल देता है।

अवश्य पढ़ें: पंडित दीन दयाल उपाध्याय

स्रोत: पीआईबी

आंगनवाड़ी-सह-क्रेच

संदर्भ: पालना के अंतर्गत आंगनवाड़ी-सह-क्रैच पर योजना की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को जारी करने के लिए हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

पृष्ठभूमि:-

- इसे योजना की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करनी थी।

आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में:-

- **लॉन्च:** वर्ष 2023 में
- **मंत्रालय:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- **उद्देश्य:** आंगनवाड़ी-सह-क्रैच का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण बाल देखभाल की मांग को पूरा करते हुए सुविधाओं और महिलाओं को कार्यबल में सक्रिय रूप से भागीदारी करने में सक्षम बनाना है।

मुख्य विशेषताएं:-

- पालना योजना के तहत पहल में संशोधन किया गया और इसे अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले मिशन शक्ति के समर्थ उप-घटक के हिस्से के रूप में शामिल किया गया।
- सरकार ने मिशन शक्ति के उप-घटक, पालना योजना के हिस्से के रूप में AWCC के माध्यम से बाल देखभाल सेवाओं का विस्तार किया है।
    - पालना योजना: कामकाजी महिलाओं के बच्चों को महिला श्रम शक्ति भागीदारी बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगी।
    - इसके उद्देश्य हैं:-
        - समुदाय में कामकाजी माताओं के बच्चों (6 माह से 6 वर्ष) के लिए डे-केयर सुविधाएं प्रदान करना और बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना।
        - बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास (समग्र विकास) को बढ़ावा देना।
        - बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए माता-पिता/देखभाल करने वालों को शिक्षित और सशक्त बनाना।
    - यह योजना निम्नलिखित सेवाओं का एक एकीकृत पैकेज प्रदान करेगी:
        - सोने की सुविधाओं सहित डेकेयर सुविधाएं।
        - 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री-स्कूल शिक्षा।
        - अनुपूरक पोषण (स्थानीय स्तर पर उपलब्ध)
        - विकास निगरानी।
        - स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण।
    - मिशन शक्ति: यह भारत सरकार का एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है।
    - इसे महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक अम्ब्रेला योजना के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसकी कार्यान्वयन तिथियां 2021-22 से 2025-26 तक थीं।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्य और जिलों को पालना को संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए AWCC योजना के प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित की है।
- AWCC का लक्ष्य 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सुरक्षित सेटिंग में उच्च गुणवत्ता वाली क्रेच सेवाएं प्रदान करना है।
- आंगनवाड़ी सुविधाएं दुनिया की सबसे बड़ी बाल देखभाल संस्थाएं हैं।
- सरकार का लक्ष्य पालना योजना के तहत 17,000 क्रेच स्थापित करने का है।
- पालना योजना के तहत मौजूदा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के साथ दो अतिरिक्त क्रेच कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को तैनात किया जाएगा। (मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना)

अवश्य पढ़ें: राष्ट्रीय क्रेच योजना (एनसीएस)

SOURCE: PIB

स्पोर्ट्स

आईबीए जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023

संदर्भ: हाल ही में, भारत ने IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2023 में 3 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीते।

आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2023 के बारे में:-

- दिनांक: 23 नवंबर - 4 दिसंबर
- स्थान: MIKA स्पोर्ट्स एरेना, येरेवन
- आकांक्षा ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, परी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
- निशा ने 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
- विनी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता।
- सृष्टि साठे ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता।
- बालक वर्ग में जतिन ने 54 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता।
- जबकि 80 किलोग्राम वर्ग में हार्दिक पंवार, 54 किलोग्राम वर्ग में अमीषा केरेटा और 80 किलोग्राम भार वर्ग में प्राची टोकस को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा।

अवश्य पढ़ें: शतरंज ओलंपियाड

SOURCE: AIR

खेलो इंडिया पैरा गेम्स

संदर्भ: हाल ही में, पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में संपन्न हुए।

पृष्ठभूमि:-

- समापन समारोह को संबोधित करते हुए, केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स को मानवीय जुनून और भावना का उत्सव बताया।

खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में:-

- **दिनांक:** 10 और 17 दिसंबर, 2023
- **स्थान:** नई दिल्ली
- **मंत्रालय:** युवा मामले और खेल मंत्रालय
- देश भर से 1400 से अधिक एथलीट सात पैरा खेलों- एथलेटिक्स, शूटिंग, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और भारोत्तोलन में प्रतिस्पर्धा किये। (ग्रैंड स्लैम)
- भव्य उद्घाटन: केडी जाधव इंडोर हॉल, इंदिरा गांधी खेल परिसर।
- दिल्ली पुलिस बैंड एक भव्य प्रदर्शन किया, जिसके बाद 'वी आर वन' समूह द्वारा जीवंत नृत्य प्रदर्शन किया गया।
- खेलो इंडिया पैरा गेम्स के आयोजन के पीछे का उद्देश्य पैरा-एथलीटों को सशक्त बनाना है।

परिणाम:-

- हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य सहित 105 पदक जीते।
- उत्तर प्रदेश 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य सहित 62 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
- तमिलनाडु 20 स्वर्ण, आठ रजत और 14 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। खेलों में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीटों ने भाग लिया।

अवश्य पढ़ें: शतरंज ओलंपियाड

SOURCE: AIR

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI)

संदर्भ: हाल ही में संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) का नया अध्यक्ष चुना गया है।

पृष्ठभूमि:-

- पदाधिकारियों के चुनाव के नतीजों के बाद उन्हें चुना गया, जिसमें उन्हें 40 वोट मिले।

भारतीय कुश्ती महासंघ के बारे में:-

- **मुख्यालय:** नई दिल्ली
- भारत में कुश्ती के लिए यह शीर्ष संस्था होती है।
- यह ओलंपिक, एशियाई खेलों, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए कुश्ती खिलाड़ियों को बढ़ावा देता है।

पहलवानों के लिए WFI की अनुबंध प्रणाली:

- वर्ष 2018 में, WFI ने पहलवानों के लिए अपनी क्रांतिकारी अनुबंध प्रणाली शुरू की।
- इसे भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- यह प्रो रेसलिंग लीग, नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप जैसे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है।

अवश्य पढ़ें: स्पोर्ट्स कोड

SOURCE: AIR

विविध

बुकर पुरस्कार

संदर्भ: हाल ही में, पॉल लिंच, जो एक आयरिश लेखक हैं, ने अपने पांचवें उपन्यास 'प्रोफेट सॉन्ग' के लिए 2023 बुकर पुरस्कार जीता।

पृष्ठभूमि:-

- पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद लिंच ने कहा, "यह मेरे लिए बेहद खुशी की बात है कि मैं बुकर को आयरलैंड में अपने घर लाऊंगा।"
- बुकर पुरस्कार के बारे में:-
- वर्ष 1969 में ब्रिटिश समूह बुकर मैककोनेल द्वारा इसकी स्थापना की गयी।
- अंग्रेजी में अनुवादित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष पुरस्कार दिया जाता है।
- £50,000 की पुरस्कार राशि विजेता उपन्यास के लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित की जाती है।
- योग्य उपन्यास अंग्रेजी भाषा के होने चाहिए, यूके या आयरलैंड में प्रकाशित होने चाहिए और पुरस्कार के वर्ष में प्रकाशित होने चाहिए।
- इसके लिए पांच सम्मानित साहित्यकारों द्वारा निर्णय लिया जाता है।
- सभी योग्य उपन्यासों में से चयनित छह उपन्यासों की लघु सूची होती है।
- प्रत्येक वर्ष नवंबर में लंदन में विजेता की घोषणा की जाती है।

भारतीय मूल के लेखकों ने पहले भी बुकर पुरस्कार जीता है:-

- अरुंधति रॉय ('द गॉड ऑफ़ स्माल थिंग्स)
- सलमान रुश्दी ('मिडनाइट्स चिल्ड्रन)
- किरण देसाई ('द इनहेरिटेंस ऑफ़ लॉस')
- अरविंद अडिगा ('द व्हाइट टाइगर')

अवश्य पढ़ें: गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार

SOURCE: BBC

एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार

संदर्भ: हाल ही में एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

पृष्ठभूमि:-

- वह इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला निर्माता बनीं।
- इसके अतिरिक्त, वीर दास को डेरी गर्ल्स सीज़न 3 के साथ कॉमेडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी से सम्मानित किया गया।

एमी अवार्ड्स के बारे में:-

- एमी पुरस्कार विशेष रूप से टेलीविजन और उभरते मीडिया के लिए प्रतिष्ठित सम्मानों का एक समूह है।
- इसकी कल्पना वर्ष 1948 में की गई, पहला एमी अवार्ड्स समारोह का उद्घाटन 25 जनवरी, 1949 को हुआ।
- टेलीविजन के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र:-

प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स	टेलीविज़न अकादमी द्वारा प्रशासित, ये सम्मानित अमेरिकी टीवी शो प्राइमटाइम के दौरान प्रस होते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार	यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन कार्यक्रमों में उत्कृष्टता को पहचान
डे टाइम एमी अवार्ड्स	देर-सवेर और दोपहर के समय प्रसारित होने वाले अमेरिकी शो को पुरस्कृत किया गया।
खेल, समाचार और वृत्तचित्र एमी पुरस्कार	नेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज की देखरेख में, ये श्रेणियां खेल, समाच वृत्तचित्र प्रोग्रामिंग में उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग एमी पुरस्कार	टेलीविजन उद्योग के भीतर तकनीकी प्रगति में उपलब्धियों को पहचानना।
क्षेत्रीय एमी पुरस्कार	स्थानीय समाचार, राज्य-दर-राज्य प्रोग्रामिंग और स्थानीय रूप से निर्मित शो सहित क्षेत्रीय टेलीविजन बाजारों में उत्कृष्टता का उत्सव मनाना।

ये पुरस्कार तीन अलग-अलग संगठनों द्वारा प्रदान किए जाते हैं:-

- टेलीविजन अकादमी प्राइमटाइम एमी पुरस्कारों का प्रबंधन करती है। (प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (पीबीएसए))
- राष्ट्रीय टेलीविजन कला एवं विज्ञान अकादमी डे-टाइम, खेल, समाचार और वृत्तचित्र श्रेणियों की देखरेख करती है।
- इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज इंटरनेशनल एम्मीज़ के लिए उत्तरदायी है।

अवश्य पढ़ें: गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार

SOURCE: THE MINT

न्योहोम पुरस्कार

संदर्भ: हाल ही में, मुंबई के प्रोफेसर ने रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्योहोम पुरस्कार जीता।

पृष्ठभूमि:-

- मुंबई के होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की प्रोफेसर सविता लाडगे को रसायन विज्ञान शिक्षा में उनके योगदान के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्योहोम पुरस्कार मिला।
- प्रोफेसर लैडेज को रासायनिक शिक्षा के महत्व की वकालत के लिए पुरस्कार मिला।
- उनके प्रयासों में रसायन विज्ञान शिक्षकों को सलाह देना और देश में रसायन विज्ञान शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले प्रभावशाली शिक्षक और छात्र कार्यक्रमों का नेतृत्व करना शामिल है।
- पुरस्कार के अलावा, प्रोफेसर लैडेज को एक पदक और एक प्रमाण पत्र के साथ £5,000 से सम्मानित किया गया।

न्योहोम पुरस्कार के बारे में:-

- रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री शिक्षा स्तर, शिक्षकों, तकनीशियनों और पेशेवरों में व्यक्तियों का उत्सव मनाने के लिए एक वार्षिक पुरस्कार प्रदान करती है। वर्ष 2023 के विजेता को £5000, पदक और प्रमाण पत्र मिला, और शिक्षा पुरस्कार समिति द्वारा चुने गए यूके-आधारित व्याख्यान या कार्यशालाओं को पूरा करता है।

अवश्य पढ़ें: शास्त्र रामानुजन पुरस्कार

SOURCE: THE HINDU

एशियाई विकास बैंक

संदर्भ: हाल ही में, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत में औद्योगिक गलियारा विकास के लिए $250 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए।

पृष्ठभूमि:-

- ऋण विनिर्माण को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने, राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ संबंधों को मजबूत करने एवं अधिक तथा बेहतर नौकरियां उत्पन्न करने के लिए औद्योगिक गलियारे के विकास को समर्थन जारी रखेगा।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बारे में:-

IMAGE SOURCE: CORPORATEFINANCEINSTITUTE.COM

- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी।

- प्रथम अध्यक्ष: ताकेशी वतनबे
- मुख्यालय: मनीला, फिलीपींस
- उद्देश्य: एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। (बहु-किश्त वित्तपोषण सुविधा)
- सदस्यता: बैंक एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) तथा गैर-क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को स्वीकार करता है।
- शेयरधारक: जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (प्रत्येक के पास कुल शेयरों का 15.6%), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (6.4%), भारत (6.3%), और ऑस्ट्रेलिया (5.8%)।
- वोटिंग अधिकार: वोट सदस्यों की पूंजी सदस्यता के अनुपात में वितरित किए जाते हैं।
- एडीबी आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है।
- **भूमिकाएँ एवं कार्य:-**
    - यह समावेशी आर्थिक विकास, पर्यावरणीय रूप से स्थाई विकास और क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को कम करने के लिए समर्पित है।

प्रमुख प्रकाशन:-

- एडीबी वार्षिक रिपोर्ट 2022, एशियाई विकास आउटलुक अप्रैल 2023
- एशियाई आर्थिक एकीकरण रिपोर्ट 2023: एशिया और प्रशांत में व्यापार, निवेश और जलवायु परिवर्तन, एशिया और प्रशांत 2022 के लिए प्रमुख संकेतक भारत और एडीबी भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है।
- भारत ADB का संस्थापक सदस्य है।
- भारत बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है।
- एडीबी परिचालन निजी क्षेत्र के विकास, लिंग सशक्तिकरण, क्षेत्रीय एकीकरण, ज्ञान समाधान और क्षमता विकास को बढ़ावा देता है।
- एडीबी इसकी रणनीति 2030 और आगामी देश साझेदारी रणनीति, 2023-2027 के अनुरूप मजबूत, जलवायु लचीले और समावेशी विकास के लिए भारत की प्राथमिकताओं का समर्थन करता है।

अवश्य पढ़ें: विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बीच अंतर

स्रोत: पीआईबी

MAINS

PAPER 1

चक्रवात मिचौंग

GS I – भूगोल

संदर्भ: हाल ही में चक्रवात मिचौंग ने सुपर-चक्रवात तूफान के रूप में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में दस्तक दी।

मिचौंग के बारे में

- इसकी उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में हुई, और धीरे-धीरे तीव्र आयनिक तूफान के रूप में गहरे दमन और अंत में एक सुपर चक्रवाती तूफान में बदल गया।
- उन्हें समुद्र की सतह के गर्म तापमान और मैडेन-जूलियन दोलन, एक मौसम विसंगति जो वर्षा पैटर्न को प्रभावित करती है, से सहायता मिली।
- यह नाम म्यांमार द्वारा सुझाया गया था, जो शक्ति और लचीलेपन का प्रतीक है।
- यह वर्ष का चौथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात या वे ऑफ़ बंगाल और 1999 के बाद पहला सुपर चक्रीय स्ट्रोम है।

चक्रवात क्यों तीव्र हुआ?

- ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप उच्च तीव्रता वाले चक्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, साथ ही तीव्रता भी बढ़ी।
- इन परिवर्तनों से समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है, जो चक्रवात की तीव्रता के लिए अनुकूल होता है। एक अध्ययन के अनुसार 1979 के बाद से 85 किमी/घंटा से अधिक की हवा की गति वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संभावना 15% अधिक हो गई है।

गहनता के परिणाम

- लंबे समय तक होने वाली बारिश अधिक ऊर्जा के साथ भूस्खलन को भूमि में आगे बढ़ने, लंबे समय तक बने रहने और पहले से दुर्गम क्षेत्रों में अपनी खुद की जमीनी तबाही का विस्तार करने की अनुमति देती है।
- चक्रवात मिचौंग लैंडफॉल के समय 90-100 किमी/घंटा की रफ्तार से 110 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की चरम तीव्रता पर पहुंच गया।
- निचले इलाकों में अचानक बाढ़ के साथ चक्रवात जनरेटर, 1.5 मीटर तक मजबूत सीयर और टाइल लहरें शामिल है।
- इससे लगभग 40 लाख लोग प्रभावित हुए, कई लोग भोजन, पानी आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच के बिना बाढ़ में फंसे रहे।
- परिणामस्वरूप बुनियादी ढांचे की फसलों और आजीविका को व्यापक क्षति हुई।

चक्रवात (साइक्लोन)

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अनुसार, चक्रवात कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास के वातावरण में गड़बड़ी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जो तेजी से और अक्सर विचलित करने वाले परिसंचरण की विशेषता है।
- वायु परिसंचरण उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में होता है।
- विषुवतीय पेटी को छोड़कर पृथ्वी पर सभी कारणों से चक्रवाती चाल चलती है।
- चक्रवात के लिए स्थितियाँ
    - गर्म और नम वायु का बड़ा और निरंतर आपूर्तिकर्ता जो भारी, गुप्त ऊष्मा जारी कर सकता है।
    - मजबूत कोर को मजबूर किया जाता है, तो केंद्र पर कम दबाव की स्थिति को रोका जा सकता है।
    - क्षोभमंडल के माध्यम से अस्थिर स्थिति जो स्थानीय अशांति उत्पन्न करती है जिसके आसपास चक्रवात विकसित होता है।
    - एब्सेस (Abscess), एक मजबूत, ऊर्ध्वाधर वनस्पति, जो गुप्त ऊष्मा के ऊर्ध्वाधर परिवहन को डिस्टर्ब करता है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध में वृद्धि

GS I –वीमेन

संदर्भ: हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट 2022 में समग्र अपराध दर में गिरावट पर प्रकाश डालती है, हालांकि यह महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 4% की वृद्धि पर प्रकाश डालती है। अपराध दर 2021 में 268 प्रति लाख से घटकर 2022 में 258.1 प्रति लाख जनसंख्या हो गई, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कारण

- लैंगिक असमानता: कई समाजों में गहरी जड़ें जमा चुकी लैंगिक असमानताएं बनी हुई हैं, जिससे पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति, संसाधनों और अवसरों का असमान वितरण होता है। ये असमानताएं एक ऐसी संस्कृति में योगदान करती हैं जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाती और बनाये रखती है।
- प्रतिगामी मूल्य प्रणाली- यह महिला आंदोलनों और सशक्तिकरण को कमजोर करती है जो लैंगिक भूमिकाओं, कामुकता और नैतिकता पर रूढ़िवादी, पारंपरिक या पिछड़े विचारों को बढ़ावा देती है।
- लिंग आधारित हिंसा- बाल विवाह, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, सम्मान हत्या, दहेज हिंसा आदि, और महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में वृद्धि।
- महिलाएं एक कमोडिटी के रूप में - दहेज प्रथा ने विवाह की पवित्र संस्था को दुखद रूप से एक ठंडे व्यापारिक लेनदेन में बदल दिया है। यह महिलाओं के खिलाफ विभिन्न प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार से जुड़ा है, जैसे घरेलू हिंसा, दहेज हत्या और दुल्हन को जलाना।
- नीति पक्षाघात- भारत में महिला विशिष्ट कानून और योजनाएं हैं लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन के बीच अंतर एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।
- आघात अवशोषक (Shock absorbers) - महिलाएं असमानता, भेदभाव और अवसरों की कमी के कारण होने वाली सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का खामियाजा भुगतती हैं।
- असमानता-उच्च अपराध दर भारत में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समूहों में महिलाओं और लड़कियों द्वारा सामना किए जाने वाले लगातार भेदभाव और उत्पीड़न को दर्शाती है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकारी उपाय

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

- यह अधिनियम संविधान के तहत गारंटीकृत उन महिलाओं के अधिकारों की अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है जो परिवार में होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार हैं और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)

- NCW भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- आयोग को महिलाओं को प्रदान किए गए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और निगरानी करने का आदेश दिया गया है; जहां भी आवश्यक हो, संशोधन का सुझाव देने के लिए मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और महिलाओं के अधिकारों से वंचित होने वाली शिकायतों पर ध्यान देना।

मिशन शक्ति

- "मिशन शक्ति" एक मिशन मोड में एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, बचाव और सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप में सुधार करना है।
- योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें दुर्व्यवहार तथा खतरे से मुक्त वातावरण में अपने शरीर और दिमाग के बारे में स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करना है।

कानूनी सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे, एलएसए अधिनियम, 1987 महिलाओं और बच्चों सहित अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों की भी स्थापना करता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है।

डिजिटल शक्ति अभियान

- डिजिटल शक्ति अभियान महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त और शिक्षित करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संचालित एक अखिल भारतीय पहल है।
- महिलाओं और लड़कियों के लिए ऑनलाइन सुरक्षित स्थान स्थापित करने के अपने वादे को ध्यान में रखते हुए, डिजिटल शक्ति ऑनलाइन किसी भी अनुचित या आपराधिक व्यवहार का सामना करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल को देश के सभी जिलों में बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप के माध्यम से लागू किया जा रहा है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को नियंत्रित करने वाले कानून

- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956 का उद्देश्य महिलाओं के व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी को रोकना है।
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961 दहेज देने और लेने पर रोक लगाता है।
- महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 विज्ञापन या प्रकाशन या लेखन, पेंटिंग, आंकड़े आदि सहित महिलाओं के किसी भी प्रकार के अश्लील प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।
- सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम 1987 सती प्रथा पर रोक लगाता है, जो किसी विधवा या महिला को उसके मृत पति के शरीर के साथ जिंदा जलाने या दफनाने का कार्य या संस्कार है।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा को मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में मान्यता देता है और प्रत्येक महिला को अपनी इच्छा के अनुसार हिंसा मुक्त घर में रहने का अधिकार प्रदान करता है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए विशाखा दिशानिर्देशों के आधार पर अधिनियमित किया गया है जो कामकाजी महिलाओं को यौन उत्पीड़न की बुराई से बचाने के उपाय प्रदान करता है।

निष्कर्ष

महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने और लिंग आधारित हिंसा के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों में मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका में सुधार, पुलिस प्रशिक्षण को बढ़ाना, बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना और न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाना महत्वपूर्ण कदम हैं।

भारत का अत्यधिक वर्षा गलियारा

GS I – भूगोल

संदर्भ: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने भारत के मौसम पैटर्न की भविष्यवाणी करने में बहुत प्रगति की है, लेकिन एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि भारतीय मानसून पैटर्न वर्तमान में किए जा रहे पूर्वानुमानों की तुलना में अधिक अनुमानित है।

भारतीय मानसून से संबंधित अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- ग्लोबल वार्मिंग ने भारतीय मानसून के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है, जिससे कई दशकों में कुल मौसमी वर्षा में कमी की प्रवृत्ति हुई है।
- इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप शुष्क दौर की लंबी लेकिन कम तीव्रता, अधिक तीव्र आर्द्र दौर और मानसून की गतिशीलता में बदलाव आया है।
- ग्लोबल वार्मिंग के कारण बदलते मानसून पैटर्न के बावजूद, एक स्थिर "गलियारा" मौजूद है जहां अत्यधिक वर्षा की घटनाएं एक साथ होती हैं।
- यह गलियारा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों से लेकर गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। यह गलियारा 1901 से 2019 तक अपरिवर्तित रहा है।

अध्ययन का महत्व

- यह अध्ययन इस धारणा का खंडन करता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु प्रणालियों में स्थिर तत्व अब मौजूद नहीं हैं। इस खोज से यह भी पता चलता है कि भारतीय मानसून जलवायु परिवर्तन के प्रति पहले की अपेक्षा अधिक लचीला हो सकता है।
- यह अध्ययन शोधकर्ताओं को अत्यधिक वर्षा के अंतर्निहित तंत्र को समझने और संभावित रूप से पूर्वानुमान मॉडल में सुधार करने में मदद कर सकता है।
- अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की बेहतर भविष्यवाणी करने की क्षमता कृषि, जल प्रबंधन, ऊर्जा, परिवहन और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जोखिमों को कम करने में मदद कर सकती है।

कॉरिडोर में अत्यधिक बारिश के बारे में

- भारत के मानसून के पूर्वानुमान एल नीनो और ला नीना घटना के संबंध पर काफी हद तक निर्भर करते हैं, हालांकि यह संबंध लगभग 60% मामलों में ही बना रहता है।
- अन्य वैश्विक घटनाएं हैं जो वर्षा पैटर्न को प्रभावित करती हैं लेकिन उन प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए अतिरिक्त जानकारी और सावधानीपूर्वक मॉडलिंग प्रयोगों की भी आवश्यकता होती है।
- तथाकथित बड़े पैमाने पर अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ एक साथ या लगभग एक साथ होने वाली भारी बारिश की घटनाएँ हैं जो एक 'हाईवे' पर बिखरी हुई हैं जो पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों से लेकर गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई हैं।

- मानसून के सभी पहलुओं में प्रतीत होने वाले अराजक परिवर्तन में, चरम घटनाओं को अपेक्षाकृत संकीर्ण गलियारे में फंसाना प्रक्रिया की समझ में संभावित सुधार के लिए अच्छी खबर है, जिससे इन सिंक्रनाइज़ चरम वर्षा की घटनाओं की बेहतर भविष्यवाणियां हो सकती हैं।

PAPER 2

मणिपुर में शांति व्यवस्था

GS II – शासन

संदर्भ: केंद्र और मणिपुर सरकार ने प्रतिबंधित मैतेई चरमपंथी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। UNLF मणिपुर घाटी में स्थित सबसे पुराना सशस्त्र समूह है, जो इस समझौते को क्षेत्र के इतिहास में एक उल्लेखनीय घटना के रूप में चिह्नित करता है।

UNLF का इतिहास

- UNLF, मणिपुर का सबसे पुराना उग्रवादी समूह है, जिसकी स्थापना 1964 में अरामबाम समरेंद्र ने की थी।
- इसका उद्देश्य मणिपुर को भारत से मुक्त कराना और एक स्वतंत्र समाजवादी राज्य बनाना था।
- भारत से अलग होने, चीन के साथ गठबंधन बनाने और राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक दीर्घकालिक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया।
- म्यांमार में काबो घाटी को पुनः प्राप्त करने का लक्ष्य।
- 2005 में, इसने भारत-मणिपुर संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखा लेकिन इसे भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। प्रस्ताव में शामिल है:
  1. मणिपुर की स्वतंत्रता की बहाली के मुख्य मुद्दे पर राज्य के लोगों की राय जानने के लिए जनमत संग्रह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की देखरेख में आयोजित किया जाना चाहिए।
  2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, मणिपुर में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना तैनात की जानी चाहिए।
  3. भारतीय सैनिकों की वापसी के बाद यूएनएलएफ संयुक्त राष्ट्र सेना को हथियार सौंप देगा।
  4. जनमत संग्रह के परिणामों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र द्वारा राजनीतिक सत्ता का हस्तान्तरण।

शांति समझौते का महत्व

- 2023 के बाद से घाटी स्थित किसी प्रतिबंधित संगठन द्वारा पहली शांति वार्ता।
- UNLF हिंसा का त्याग करता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेता है।
- वर्ष 2014 से केंद्र के त्रिपक्षीय समझौतों के परिणामस्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है।
- समझौते में यूएनएलएफ के सशस्त्र कैडरों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन शामिल है।
- शांति निगरानी समिति सहमत जमीनी नियमों के प्रवर्तन की निगरानी करेगी।

शांति समझौते के साथ चुनौतियाँ

- हितधारकों की बहुलता और उनके अलग-अलग हितों तथा शिकायतों के कारण शांति समझौते को लागू करना जटिल हो सकता है।
- समझौते की शर्तें ज्ञात नहीं हैं और नवीनतम जातीय संघर्ष में उग्रवादियों की भागीदारी से मामला और जटिल हो सकता है।
- यदि आपराधिक मामले वापस ले लिए जाते हैं, तो दूसरी तरफ कुकी उग्रवादियों को भी ऐसी ही रियायतें देनी होंगी, जो कथित तौर पर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौते को जारी रखे हुए हैं।
- शांति समझौतों की कमज़ोरी इन समुदायों के भीतर चरमपंथी गुटों या विभाजित समूहों के कारण होने वाले व्यवधानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता में भी निहित है।
- शांति समझौते में उल्लिखित वादों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता में विश्वास की कमी इसकी प्रभावशीलता को कमजोर करती है।
- शांति प्रक्रियाओं का समर्थन करने में पड़ोसी देशों की अनिच्छा या बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप इस क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है।

मणिपुर में विद्रोह का इतिहास

- मणिपुर भारत के सबसे पुराने विद्रोही आंदोलनों की अंतर्धारा में रहा है।
- नागा आंदोलन देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह है जो ग्रेटर नागालैंड या नागालिम के लिए लड़ता है।
- कुकी ने पूरे मणिपुर में फैली 'स्वतंत्र कुकी मातृभूमि' के लिए भी भारत सरकार से लड़ाई लड़ी है।

- 1990 के दशक की शुरुआत में मणिपुर के नागाओं के साथ जातीय संघर्ष के बाद कुकी विद्रोह ने गति पकड़ी।
- मणिपुर में मैतेई लोगों ने 1949 में मणिपुरी राजा और भारत सरकार के बीच विलय समझौते का विरोध किया।

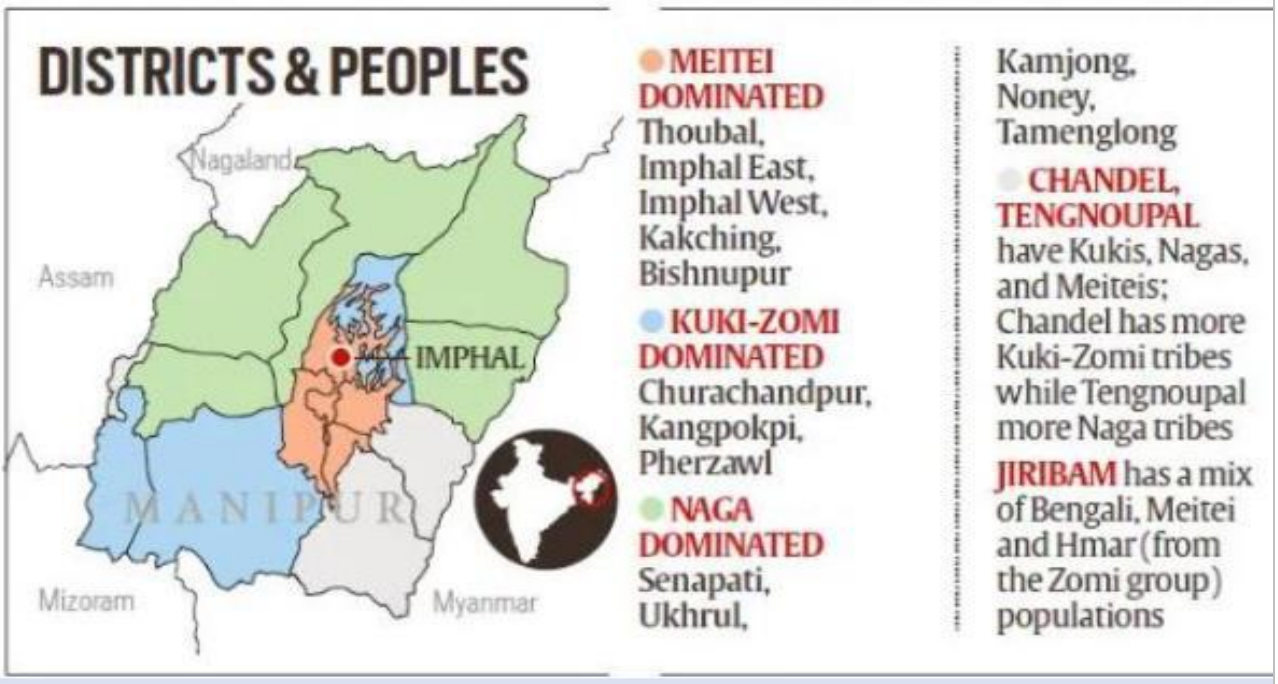

निष्कर्ष

- UNLF के साथ शांति समझौता मणिपुर में लंबे समय से चले आ रहे विद्रोह को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बातचीत और संभावित सुलह के प्रति मैतेई विद्रोही समूहों के दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है। इस समझौते की सफलता क्षेत्र में आगे शांति पहल का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जिससे मणिपुर में स्थिरता और विकास में योगदान मिलेगा।

भारत की बढ़ती पड़ोस संबंधी दुविधाएँ

GS II – अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सन्दर्भ: अटल बिहारी वाजपेई ने एक सभा में कहा था, "हम इतिहास तो बदल सकते हैं, लेकिन भूगोल नहीं।" हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं।" किसी भी बड़ी शक्ति के लिए पड़ोस कठिन होते हैं, लेकिन समकालीन भारत को अपने इतिहास में पहली बार असाधारण रूप से कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जो अपने पड़ोस में उभरती महाशक्ति के कारण जटिल है।

भारत की वर्तमान दुविधाएँ

भारत विरोधी शासन

- दक्षिण एशिया में राजनीतिक रूप से भारत विरोधी शासन देखा जाता है:
  - मालदीव - इंडिया आउट अभियान 2020 से शुरू हुआ जिसमें भारतीयों को देश छोड़ने के लिए कहा गया।
  - बांग्लादेश - विपक्षी दल ने भारत पर उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है।

आक्रामक चीन

- दक्षिण एशिया में बीजिंग का बढ़ता प्रभाव क्षेत्र के छोटे राज्यों को आर्थिक और रणनीतिक लाभ प्रदान कर रहा है।
- बेल्ट एंड रोड पहल में बुनियादी ढांचे में कई दक्षिण एशियाई देश शामिल हैं, यह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का भी उल्लंघन करता है।
- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) और चीन-मालदीव मैत्री पुल जैसी परियोजनाओं से आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव हासिल किया जाता है।
- चीन उन देशों के साथ जुड़ा हुआ है जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा अलग-थलग हैं या प्रतिबंधित हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका, उन्हें राजनयिक और सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है।
- चीन की शिकारी ऋण देने की प्रथा जिसमें गरीब देश अस्थिर ऋणों से अभिभूत हो जाते हैं और रणनीतिक संपत्तियों का नियंत्रण चीन को सौंपने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उदाहरण: श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह
- चीन ने भारत को छोड़कर अपने पड़ोसियों के साथ सीमा विवादों को सुलझाने की कोशिश की, जैसा कि भूटान के मामले में देखा गया, जहां चीन ने डोकलाम पठार के बदले में क्षेत्र की अदला-बदली की पेशकश की, जिस पर भूटान और चीन दोनों दावा करते हैं।

भू-राजनीतिक लॉक-इन

- भारत भू-राजनीतिक रूप से एक अमित्र दक्षिण एशिया में लॉक-इन हो जाएगा।
- दक्षिण एशियाई देशों पर चीन के प्रभाव से भारत के साथ अन्य देशों के द्विपक्षीय संबंध कमजोर होंगे।
- इससे रणनीतिक विकल्प और क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका सीमित हो जाएगी।

दुविधाओं का कारण

- क्षेत्रीय भू-राजनीतिक वास्तुकला की विशेषता है:
  - संयुक्त राज्य अमेरिका की घटती उपस्थिति, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में एक भू-राजनीतिक स्थिरता थी।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी से उत्पन्न शून्यता को चीन ने पूरा कर दिया है।
  - चीन का आक्रामक और जबरदस्त उदय, कम से कम अभी के लिए, इस क्षेत्र के छोटे राज्यों के लिए एक 'भूराजनीतिक बफर' के रूप में आया है, जो अपनी विदेश नीति के दावों में 'चीन कार्ड' का उपयोग करने में माहिर हो गए हैं।
  - दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे कम परस्पर जुड़े और सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक है, और इस क्षेत्र के निवासी स्वाभाविक रूप से चीन की ओर आकर्षित होते हैं जो उनकी भौतिक जरूरतों को पूरा कर सकता है।
  - चीन ने खुद को भारत के लिए एक बिना तामझाम वाले गैर-मानकीय विकल्प के रूप में पेश किया है, और इसने क्षेत्र की भारत-केंद्रित गणना को बदल दिया है।
- भारत की दुविधा के अन्य कारणों में इसकी धारणा शामिल है, एक यह कि दक्षिण एशिया पाकिस्तान को छोड़कर भारतीय भू-राजनीति के लिए उत्तरदायी होगा, दूसरी धारणा यह है कि कल्चर, सॉफ्ट पॉवर, इतिहास और जातीयता में निहित क्षेत्र के साथ भारत के विशेष संबंध से देश को इससे निपटने में मदद मिलेगी। इस क्षेत्र, अर्थात् चीन, के बारे में गहन जानकारी न रखने वालों की तुलना में पड़ोस बेहतर है।

आगे की राह

- भारत को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में मूलभूत परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए और एक नई भू-राजनीतिक वास्तविकता के ढांचे के भीतर काम करना चाहिए।
- क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मित्रवत बाहरी अभिनेताओं को सक्रिय रूप से शामिल करें।
- एक लचीला राजनयिक दृष्टिकोण अपनाएं जो भारत विरोधी भावनाओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पड़ोसी देशों में कई अभिनेताओं के साथ जुड़ता है।
- विदेश नीति के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भारत के राजनयिक कार्यबल में उल्लेखनीय वृद्धि करके राजनयिकों की कमी को दूर करना।

अधिवक्ता संशोधन विधेयक

GS II – शासन

संदर्भ: अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 और कानूनी व्यवसायी अधिनियम 1879 में संशोधन करता है। ये अधिनियम भारत में कानूनी चिकित्सकों के विनियमन के लिए केंद्रीय रहे हैं।

विधेयक में संशोधन की जरूरत होना

- इसका उद्देश्य अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करना और कानूनी व्यवसायी अधिनियम, 1879 के अप्रचलित प्रावधानों को निरस्त करना है, ताकि उन सभी अप्रचलित कानूनों या स्वतंत्रता-पूर्व अधिनियमों को निरस्त करने की सरकार की नीति के अनुरूप रखा जा सके जो अपनी उपयोगिता खो चुके हैं।
- विधेयक दलाली के अपराध को दंडनीय बनाने का प्रयास करता है और न्यायाधीशों को अपराधियों की सूची प्रकाशित करने का अधिकार देता है।
- क़ानून की किताब में अनावश्यक अधिनियमों की संख्या को कम करने और सभी अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया है।
- विधेयक का उद्देश्य कानूनी पेशे का विनियमन सुनिश्चित करना और अधिवक्ताओं और जनता के हितों की रक्षा करना है।
- यह विधेयक कानूनी पेशे के नियमन पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से परामर्श करने का प्रावधान करता है।

टाउट कौन है?

- टाउट से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो:
  - किसी भुगतान के बदले में किसी कानूनी व्यवसाय में कानूनी व्यवसायी का रोजगार प्राप्त करने या प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है या
    - ऐसे रोज़गार प्राप्त करने के लिए बारंबार स्थान जैसे दीवानी या फौजदारी अदालतों का परिसर, राजस्व-कार्यालय, या रेलवे स्टेशन।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी दलालों की सूची तैयार और प्रकाशित कर सकते हैं।
- अधिकारी अधीनस्थ अदालतों को कथित या संदिग्ध दलालों की जांच करने का आदेश दे सकते हैं।
- दलाल साबित होने पर उनका नाम सूची में शामिल किया जाएगा।
- अदालतें या न्यायाधीश किसी भी व्यक्ति को, जिसका नाम सूची में है, बाहर कर सकते हैं।
- बिना कारण बताये किसी भी व्यक्ति को सूचियों में शामिल नहीं किया जा सकता।
- सूची में नाम होने पर दलाल के रूप में कार्य करने पर 3 महीने तक की कैद या 500 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 45 में एक नया प्रावधान अवैध व्यवसायियों के लिए 6 महीने की कैद का प्रावधान करता है।

कानूनी व्यवसायी अधिनियम, 1879

- यह अधिनियम 1880 में अधिनियमित किया गया था, इसका उद्देश्य कुछ भारतीय प्रांतों में कानूनी चिकित्सकों से संबंधित कानून को समेकित करना था।
- अधिनियम ने कानूनी चिकित्सकों को किसी भी उच्च न्यायालय के एडवोकेट, वकील या अटॉर्नी के रूप में परिभाषित किया है।
- कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू 'टाउट' की परिभाषा थी, जो उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो पारिश्रमिक के लिए कानूनी चिकित्सकों के लिए ग्राहक जुटाते हैं।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961

- यह अधिनियम कानूनी चिकित्सकों से संबंधित कानूनों को एकीकृत करने और संशोधित करने तथा बार काउंसिल और एक अखिल भारतीय बार की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था।
- यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कानूनी शिक्षा, पेशेवर आचरण, कानूनी सहायता और विदेशी योग्यता की मान्यता जैसे मामलों पर नियम बनाने का अधिकार देता है।
- पहले, कानूनी व्यवसायी 1879 अधिनियम सहित कई अधिनियमों द्वारा शासित होते थे।
- स्वतंत्रता के बाद, कानून आयोग और अखिल भारतीय बार समिति द्वारा सुधारों का सुझाव दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1961 अधिनियम बना।

पीवीजीटी के लिए पीएम जनमन योजना

GS II – स्वास्थ्य

संदर्भ: हाल ही में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी प्रधान मंत्री-जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजना को प्रकाश में लाया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान के उद्देश्य से, यह पहल उनकी अनूठी चुनौतियों का समाधान करने और उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने की क्षमता रखती है।

पीएम-जनमन योजना के बारे में

- पीएम जनमन एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा में लाना है।
- यह योजना (केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर) राज्य सरकारों और पीवीटीजी समुदायों के सहयोग से जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।
- यह योजना 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा देखरेख किए जाने वाले 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो पीवीटीजी द्वारा बसे गांवों में मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी।
- इस योजना में वन उपज के व्यापार के लिए वन धन विकास केंद्रों की स्थापना, 1 लाख घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली और सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना भी शामिल है।
- इस योजना से पीवीटीजी के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण में वृद्धि होने की उम्मीद है, उनके भेदभाव और बहिष्कार के कई और प्रतिच्छेदन रूपों को संबोधित करके, और राष्ट्रीय और वैश्विक विकास में उनके अद्वितीय और मूल्यवान योगदान को पहचानकर और महत्व देकर।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- डेटा अशुद्धि-पीवीटीजी पर वर्तमान डेटा की कमी है, क्योंकि 1951 के बाद से किसी भी जनगणना में इनका अलग से हिसाब नहीं दिया गया है।
- पारदर्शिता का अभाव- वर्तमान परियोजना बेसलाइन सर्वेक्षणों के साथ आगे बढ़ रही है लेकिन परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
- जवाबदेही की कमी- इस योजना में कई मंत्रालय शामिल हैं, इससे ओवरलैपिंग या विरोधाभासी जनादेश, सेवा वितरण में अंतराल आदि

के मुद्दे हो सकते हैं।

- पारिस्थितिक विविधता का नुकसान- सड़क निर्माण जैसे कुछ हस्तक्षेप प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं।
- सांस्कृतिक विरासत का नुकसान- यह योजना शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास आदि प्रदान करती है, इससे उनकी बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत का नुकसान हो सकता है, और उनकी लचीलापन और अनुकूलनशीलता कम हो सकती है।
- स्वायत्तता का अभाव- मोबाइल कनेक्टिविटी, आंगनवाड़ी केंद्र और बंधन विकास केंद्र पीवीटीजी को राज्य और बाजार शक्ति के दायरे में ला सकते हैं और उनकी संप्रभुता और अधिकारों से समझौता कर सकते हैं।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)

- 705 एसटी में से 75 पीवीटीजी, 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैले हुए हैं।
- वर्ष 1973 में एक अलग श्रेणी के रूप में स्थापित, 2006 में इसका नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) कर दिया गया।
- छोटी आबादी, भौतिक अलगाव, सरल सामाजिक संस्थान और धीमी परिवर्तन दर के साथ अधिकतर समरूप।
- ओडिशा और आंध्र प्रदेश में उच्चतम पीवीटीजी।
- छत्तीसगढ़ में 7 पीवीटीजी हैं।
- समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वर्ष 2008 में स्थापित है।
- सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 2023-24 में प्रधान मंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया।

आगे की राह

- पीवीटीजी की स्थिति पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) 2013 की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय को विशेष रूप से पीवीटीजी समुदायों के लिए जनगणना डिजाइन और आयोजित करनी चाहिए। जनगणना में सिर्फ गिनती ही नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की स्थिति का भी पता लगाना चाहिए।

संसद में सुरक्षा उल्लंघन

GS II – संसदीय मामले

संदर्भ: 2001 के आतंकवादी हमले की 22वीं बरसी पर भारत की लोकसभा में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उल्लंघन हुआ, जिससे गंभीर सुरक्षा चूक का पता चला। यह उल्लंघन बार-बार होने वाले उल्लंघनों को रोकने और संसदीय संस्थानों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए गहन जांच, सुधारात्मक उपायों और मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। विशेषाधिकार का उल्लंघन सांसदों या संसद के विशेषाधिकारों के किसी भी उल्लंघन को संदर्भित करता है, जिसमें उन पर विचार करना भी शामिल है।

संसद आगंतुकों के लिए नियम

- लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का नियम 386 सदन की बैठकों के दौरान आगंतुकों (संसदीय शब्दों में "अजनबी" के रूप में संदर्भित) के "प्रवेश, वापसी और निष्कासन" को नियंत्रित करता है।
- नियम 387 अध्यक्ष को उपयुक्त समझे जाने पर सदन के किसी भी हिस्से से "अजनबियों" को वापस लेने की शक्ति देता है।
- अध्यक्ष द्वारा अधिकृत नियम 387ए, सचिवालय अधिकारी को सदस्यों के लिए आरक्षित सदन परिसर के भीतर किसी भी अजनबी को हटाने या हिरासत में लेने का अधिकार देता है।
- सदस्य केवल व्यक्तिगत रूप से परिचित व्यक्तियों के लिए ही विज़िटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- सुरक्षा कारणों से, आगंतुकों को प्रमाणीकरण के साथ फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।
- राज्यसभा में विजिटर एंट्री के लिए भी ऐसे ही नियम लागू हैं।
- सदस्यों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, खासकर जब किसी ऐसे व्यक्ति के प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाती है जिसका परिचय उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कराया गया हो।

संसद परिसर में सुरक्षा पर संयुक्त संसदीय समिति

- संसद परिसर में सुरक्षा पर संयुक्त संसदीय समिति भारतीय संसद की एक समिति है जो संसद परिसर के भीतर सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख और समीक्षा के लिए जिम्मेदार है।
- यह समिति संसद सदस्यों (सांसदों), संसदीय कर्मचारियों और संसद के समग्र कामकाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- आमतौर पर, समिति लोकसभा (लोगों का सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद) दोनों के सदस्यों से बनी होती है, जो सुरक्षा निरीक्षण के लिए द्विदलीय दृष्टिकोण को दर्शाती है।
- समिति संसद परिसर के भीतर सुरक्षा नीतियों और दिशानिर्देशों के निर्माण के लिए सिफारिशें कर सकती है। इसमें पहुंच नियंत्रण, निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया और प्रासंगिक सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना शामिल है।
- इस संयुक्त समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।

2001 भारतीय संसद पर हमला

- वर्ष 2001 में भारतीय संसद पर हुआ हमला एक आतंकवादी हमला था जो 13 दिसंबर 2001 को हुआ था, जब सशस्त्र आतंकवादियों के एक समूह ने नई दिल्ली में भारतीय संसद पर हमला किया था।
- हमलावर पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के थे।
- हमले में सुरक्षाकर्मियों और सरकारी अधिकारियों की मौत हो गई।
- इस हमले ने बाहरी खतरों के प्रति भारत के संसदीय लोकतंत्र की संवेदनशीलता को उजागर कर दिया और इसकी सुरक्षा व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव को प्रेरित किया।

संसदीय विशेषाधिकार

- संसदीय विशेषाधिकार का तात्पर्य एक संस्था के रूप में संसद और सांसदों को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में प्राप्त अधिकारों और उन्मुक्तियों से है, जिसके बिना वे संविधान द्वारा सौंपे गए अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं।

संवैधानिक विशेषाधिकार

- अनुच्छेद 105 - संसद, उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों आदि से संबंधित है।
- अनुच्छेद 194 - राज्यों में विधायिका के सदनों, उनके सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकारों और शक्तियों की रक्षा करता है।

सामूहिक विशेषाधिकार

- रिपोर्ट, बहस और कार्यवाही प्रकाशित करने की क्षमता, साथ ही दूसरों को ऐसा करने से रोकने की क्षमता।
- यह प्रेस की स्वतंत्रता के तहत सदन की अनुमति के बिना संसदीय कार्यवाही की सही रिपोर्ट प्रकाशित कर सकता है।
- अपनी प्रक्रिया और वाणिज्यिक गतिविधि को नियंत्रित करने के साथ-साथ ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए नियम बनाना।
- किसी सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत, दोषसिद्धि, कारावास और रिहाई की तत्काल सूचना का अधिकार।
- पूछताछ शुरू करना और किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए बाध्य करना।
- अदालतों को किसी सदन या उसकी समितियों की कार्यवाही की जांच करने की अनुमति नहीं है।
- पीठासीन अधिकारी की सहमति के बिना किसी को भी (चाहे कोई सदस्य हो या बाहरी व्यक्ति) गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और सदन की सीमाओं के भीतर कोई कानूनी प्रक्रिया (सिविल या आपराधिक) नहीं की जा सकती।

व्यक्तिगत विशेषाधिकार

- विधानमंडल के सत्र के दौरान प्रारंभ के 40 दिन पहले से समाप्ति के 40 दिन बाद तक किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा।
- सदस्यों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है।
- संसद या इसकी समितियों का कोई भी सदस्य संसद या इसकी समितियों में कही गई या वोट की गई किसी भी बात के लिए किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं है।
- यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधानों के साथ-साथ संसद के कामकाज को नियंत्रित करने वाले मानदंडों और स्थायी आदेशों द्वारा सीमित है।
- उन्हें अदालत में गवाही देने और गवाही देने से इनकार करने का अधिकार है।

निष्कर्ष

संसद परिसर में सुरक्षा उल्लंघन एक गंभीर अनुस्मारक है कि हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित नहीं किया जा सकता है।

डाकघर संशोधन विधेयक

GS II – राजव्यवस्था और संविधान

संदर्भ: डाकघर विधेयक, 2023 को विचार के लिए रखा गया है जो भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का स्थान लेता है। चूंकि डाकघर सेवाएं मेल से परे विविध हैं और डाकघर नेटवर्क नागरिक केंद्रित सेवाओं का माध्यम बन गया है।

विधेयक के प्रावधान

- भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का प्रतिस्थापन है।
- अधिनियम केंद्र सरकार को डाक द्वारा पत्र भेजने और आकस्मिक सेवाओं का विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है।
- इंडिया पोस्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में डाक लेखों और मनी ऑर्डर की डिलीवरी शामिल है।
- कुछ आधारों पर पोस्ट के माध्यम से प्रसारित लेख को रोकने की अनुमति देता है।
- डाक सेवाओं के महानिदेशक की नियुक्ति, डिलीवरी का समय और तरीका तय करने की शक्तियां।
- परीक्षा की शक्तियां हटा दी गईं, जिससे एक अधिकारी को वस्तु को सीमा शुल्क प्राधिकरण तक पहुंचाने का अधिकार मिल गया।
- अधिनियम सरकार को किसी डाक वस्तु की हानि, गलत डिलीवरी, देरी या क्षति से संबंधित दायित्व से छूट देता है।
- जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 इन छूटों को बरकरार रखता है।
- अधिनियम में विभिन्न अपराधों और दंडों को निर्दिष्ट किया गया था, जिन्हें विधेयक द्वारा हटा दिया गया था। उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान नहीं की गई राशि भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

नए बिल से जुड़े मुद्दे

- उच्च सरकारी नियंत्रण: सरकार द्वारा पार्सल को रोकने और खोलने की अनुमति देने वाला प्रावधान नियंत्रण को बढ़ा सकता है लेकिन गोपनीयता और दुरुपयोग के संभावित मुद्दों को भी बढ़ा सकता है।
- विशिष्ट विशेषाधिकारों का नुकसान: पत्र भेजने और डाक टिकट जारी करने में केंद्र सरकार के लिए विशेष विशेषाधिकारों को समाप्त करने से पारंपरिक डाक सेवाओं पर असर पड़ सकता है।
- दायित्व संबंधी चिंताएँ: अपनी सेवाओं के लिए उत्तरदायित्व को केंद्र सरकार से डाकघर पर स्थानांतरित करने से जवाबदेही और जिम्मेदारी पर सवाल उठ सकते हैं।
- डेटा गोपनीयता और सुरक्षा: विस्तारित अवरोधन शक्तियों के कारण डाक सेवा उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए मजबूत डेटा गोपनीयता और सुरक्षा उपायों की स्थापना की आवश्यकता होती है।
- कूरियर के लिए अलग-अलग कानून: कूरियर फर्मों के लिए समान कानून की अनुपस्थिति नियामक असमानताओं के बारे में चिंता उत्पन्न करती है।

निष्कर्ष

- नया डाकघर विधेयक (2023) भारत की डाक सेवाओं में स्वागतयोग्य लचीलापन और आधुनिकीकरण लाता है। हालाँकि यह कुछ प्रमुख मुद्दों को संबोधित करता है और नवाचार के द्वार खोलता है, लेकिन कूरियर कंपनियों के लिए अलग-अलग कानून जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। डिजिटल एड्रेसिंग की दिशा में कदम स्पष्ट परिभाषाओं और कुशल मेल डिलीवरी का वादा करता है, संभवतः ड्रोन डिलीवरी का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इन परिवर्तनों के साथ, डाक सेवा का लक्ष्य वैधता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लोगों और बाजार की उभरती जरूरतों के अनुरूप ढलना है।

भारत-ओमान संबंध

GS II – अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ: हाल ही में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने भारत का दौरा किया, यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि यह 26 वर्षों में किसी ओमानी शासक की पहली राजकीय यात्रा है।

भारत के लिए ओमान का महत्व

ऐतिहासिक सहयोग:

- सिंधु घाटी में सुमेरियन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बीच स्थापित समुद्री व्यापार मार्ग महान ऐतिहासिक महत्व को उजागर करते हैं।
- ओमान का भारत के साथ गुजरात के माध्यम से और मालाबार तट के साथ तमिलकम के साथ संबंध था।
- शीत युद्ध के युग के दौरान और उसके बाद, अरब जगत (जो पाकिस्तान का समर्थक था) की तुलना में ओमान भारत के प्रति अधिक मित्रवत था।

भू-रणनीतिक पहलू:

- अरब सागर के किनारे ओमानी बंदरगाह, ओमान की खाड़ी फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी का प्रवेश बिंदु है, जो ओमान के स्थान को भारत के लिए रणनीतिक महत्व का बनाता है।

आर्थिक संबंध:

- संयुक्त आयोग बैठक (जेसीएम) और संयुक्त व्यापार परिषद (जेबीसी) जैसे संस्थागत तंत्र भारत और ओमान के बीच आर्थिक सहयोग की देखरेख करते हैं।
- वर्ष 2022 के लिए ओमान के कच्चे तेल निर्यात के लिए चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है।
- भारत वर्ष 2022 के लिए ओमान के गैर-तेल निर्यात के लिए संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब के बाद चौथा सबसे बड़ा बाजार है और संयुक्त अरब अमीरात के बाद इसके आयात का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।

रक्षा संबंध:

- जेएमसीसी रक्षा के क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच जुड़ाव का सर्वोच्च मंच है।
- JMCC की वार्षिक बैठक होने की उम्मीद है, लेकिन 2018 के बाद से इसका आयोजन नहीं किया जा सका, जब 9वीं JMCC की बैठक ओमान में आयोजित की गई थी।
- सेना अभ्यास: अल नजाह
- वायु सेना अभ्यास: ईस्टर्न ब्रिज
- नौसेना अभ्यास: नसीम अल बह

भारतीय प्रवासी

- ओमान में लगभग 7 लाख भारतीय हैं, जिनमें से लगभग 4.8 लाख श्रमिक और पेशेवर हैं। ओमान में 150-200 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय परिवार रह रहे हैं।

हाल की यात्रा में मुख्य बातें

- मनी लॉन्ड्रिंग, संबंधित अपराध और आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान में सहयोग पर वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) और राष्ट्रीय वित्तीय सूचना केंद्र (एफएनसीआई) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- भारत और ओमान दोनों देशों के बीच व्यापार और प्रेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए RuPay और ई-दिरहम जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।
- दोनों ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कृषि सहयोग बढ़ाने के महत्व को पहचाना है।
- ढोफर विश्वविद्यालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) द्वारा भारतीय अध्ययन-हिंदी भाषा के आईसीसीआर चेयर की स्थापना पर।
- विज़न दस्तावेज़ 'अमृत काल' के तहत ओमान विज़न 2040 और भारत के विकास उद्देश्यों के बीच उल्लेखनीय तालमेल को स्वीकार करता है, ओमान और भारत के बीच साझेदारी को गहरा करने के लिए इन पूरकताओं का उपयोग करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

निष्कर्ष

- भारत पश्चिम एशिया में गहन जुड़ाव और सहयोग चाहता है, जिसमें ओमान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओमान इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण समूहों जैसे जीसीसी, इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी), और अरब लीग का एक अभिन्न अंग है।

संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता

GS II – भारतीय संविधान

धर्मनिरपेक्षता के बारे में

- धर्मनिरपेक्षता एक विचारधारा है जो धर्म और राज्य को अलग करने और धार्मिक मान्यताओं के संबंध में सरकार की तटस्थता पर जोर देती है।
- इसके मोटे तौर पर दो अर्थ हैं:
  o धर्म को राज्य से अलग करना अर्थात धर्म निर्पेक्षता।
  o राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान सम्मान अर्थात सर्व धर्म समभाव।
- भारतीय संविधान का लक्ष्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का है जहां सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाए।

भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 14- यह सभी को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 16 (1) - यह सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है और दोहराता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान और निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
- अनुच्छेद 25- यह 'विवेक की स्वतंत्रता' प्रदान करता है, अर्थात, सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार के हकदार हैं।
- अनुच्छेद 26- प्रत्येक धार्मिक समूह या व्यक्ति को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने तथा धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 27- इसमें प्रावधान है कि राज्य किसी भी नागरिक को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए मजबूर नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 28- यह विभिन्न धार्मिक समूहों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 29 और 30- ये अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करते हैं।
- अनुच्छेद 51ए मौलिक कर्तव्य- यह सभी नागरिकों को सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने और हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने तथा संरक्षित करने के लिए बाध्य करता है।
- 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976- प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द डाला गया। इसमें कहा गया कि 'धर्मनिरपेक्ष' का अर्थ एक ऐसा गणतंत्र है जिसमें सभी धर्मों के लिए समान सम्मान हो।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर न्यायपालिका

- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है।
- बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता के अर्थ पर विस्तार से प्रकाश डाला। कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार है।

धर्मनिरपेक्षता को खतरा

- सांप्रदायिक राजनीति- धर्म, जाति और जातीयता जैसी मौलिक पहचानों के आधार पर वोटों की गोलबंदी ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डाल दिया है।
- सामाजिक पूर्वाग्रह: धार्मिक पहचान पर आधारित गहरे सामाजिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता भेदभाव और सामाजिक विभाजन में योगदान कर सकते हैं। वास्तव में धर्मनिरपेक्ष समाज को बढ़ावा देने के लिए इन पूर्वाग्रहों पर काबू पाना महत्वपूर्ण है।
- हिंदू राष्ट्रवाद का उदय: इसके परिणामस्वरूप गाय की हत्या करने और गोमांस खाने के संदेह पर भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई। इसके अलावा, बूचड़खानों को जबरन बंद करना, 'लव जिहाद' के खिलाफ अभियान, पुन: धर्मांतरण या घर-वापसी (मुसलमानों को हिंदू धर्म में परिवर्तित होने के लिए मजबूर करना) आदि समाज में सांप्रदायिक प्रवृत्ति को मजबूत करते हैं।
- इस्लामिक राज्य: शरिया कानून पर आधारित इस्लामिक राज्य की स्थापना को इस्लामिक कट्टरवाद या पुनरुत्थानवाद द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, जो सीधे तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य के विचारों से मेल नहीं खाता है।

भारतीय इतिहास में धर्मनिरपेक्षता

- भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक परंपराओं और सामाजिक आंदोलनों का मिश्रण है।
- सम्राट अशोक ने घोषणा की कि राज्य किसी भी धार्मिक संप्रदाय पर अत्याचार नहीं करेगा।
- जैन, बौद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्म के आगमन के बाद भी धार्मिक सहिष्णुता की खोज जारी रही।
- मध्ययुगीन भारत में सूफी और भक्ति परंपराओं ने शांतिपूर्ण सामुदायिक संबंधों को बढ़ावा दिया।
- इन आंदोलनों के प्रमुख दिग्गजों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, संत कबीर दास, गुरु नानक देव, संत तुकाराम और मीरा बाई शामिल थे।
- मध्यकालीन भारत में अकबर का शासन धार्मिक सहिष्णुता और पूजा की स्वतंत्रता द्वारा चिह्नित था।
- अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के बावजूद भारतीय मुक्ति आंदोलन ने धर्मनिरपेक्षता को मजबूत किया।
- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक चरण में उदारवादियों ने धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दर्शन को अपनाया।
- पंडित मोती लाल नेहरू के 1928 के संविधान में धर्मनिरपेक्षता पर प्रावधानों का मसौदा तैयार किया गया था। गांधीजी की धर्मनिरपेक्षता धार्मिक समुदायों के भाईचारे और सत्य की खोज के प्रति सम्मान पर आधारित थी।

निष्कर्ष

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की साइट का एक हिस्सा भगवान विश्वेश्वर की संपत्ति के रूप में घोषित करने के लिए 1991 में दायर मुकदमों का एक सेट पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 द्वारा वर्जित नहीं है। इसलिए एक मस्जिद को मंदिर में बदलने के लिए अप्रत्यक्ष साधन प्रदान करना। न्यायपालिका को पूजा स्थलों की स्थिति को बदलने के लिए बार-बार होने वाले, सांप्रदायिक रूप से प्रेरित प्रयासों को वैध बनाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस तरह का दृष्टिकोण अंततः आधुनिक समाज को मध्ययुगीन लूट-खसोट का बदला लेने की विद्रोहवादी मानसिकता में धकेल सकता है।

PAPER 3

उत्तराखंड सुरंग बचाव मिशन

GS III – आपदा प्रबंधन

संदर्भ: उत्तराखंड सुरंग बचाव मिशन भारत में चलाया गया सबसे लंबा बचाव अभियान रहा है। ढही सिल्क्यारा सुरंग के अंदर 41 मजदूर लगभग 17 दिनों तक फंसे रहे। यह 57 मीटर के मलबे के दोनों किनारों पर मौजूद लोगों के लिए धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा थी, क्योंकि बचाव अभियान को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। अंततः, सभी 41 श्रमिकों की सुरक्षित निकासी के साथ मिशन सफल रहा।

उत्तराखंड सुरंग बचाव मिशन के प्रयासों का क्रम

1. भारी मिट्टी खोदने वाली मशीनें मलबा हटाने में विफल रहीं।
2. ऑगर ड्रिलिंग मशीन चालू हो गई थी, लेकिन सुरंग की ढही छत के मलबे के कारण वह लगातार खराब हो रही थी।
3. पाँच अतिरिक्त योजनाएँ प्रस्तावित की गईं, जिनमें ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग, क्षैतिज सुरंग, ड्रिफ्टिंग और बरकोट छोर से सुरंग खोलना शामिल है।
4. ऑगर मशीन खराब हो गई, जिससे 10 मीटर मलबा साफ करना बाकी रह गया।
5. रैट-होल खनिकों को सीमित स्थानों में 27 घंटे काम करने का काम सौंपा गया था।
6. बचाव अभियान राष्ट्रीय आपदा राहत बल के कर्मियों और राज्य समकक्षों द्वारा सहायता प्रदान करने के साथ समाप्त हुआ।

सुरंग बचाव मिशन से प्राप्त सीख

- आपदा प्रबंधन में हाशिए पर मौजूद श्रमिकों का अनुकूलन।
- आपदा प्रबंधन में स्वदेशी विशेषज्ञता का समावेश।
- महामारी के बाद प्रवासियों की दुर्दशा पर जोर।
- हिमालयी पारिस्थितिकी में अनावश्यक बुनियादी ढांचे के पर्यावरणीय जोखिमों पर फिर से ध्यान केंद्रित करना।
- एनडीआरएफ, ओएनजीसी, सशस्त्र बलों और राज्य एजेंसियों द्वारा प्रभावी अंतर-एजेंसी समन्वय।

इसी तरह के अभियान विदेशों में भी चलाए गए

थाई गुफा अभियान और चिली माइन ऑपरेशन

- वाइल्ड बोअर्स फुटबॉल टीम बारिश के जलभराव के कारण थाईलैंड की थाम लुआंग गुफा में फंस गई।
- दो सप्ताह के ऑपरेशन में 90 गोताखोरों को तैनात किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व थाईलैंड नेवी सील समन कुनान की मौत हो गई।
- सैन जोस की सोने और तांबे की खदान 2010 में ढह गई, जिससे 33 मजदूर जमीन से लगभग 2000 फीट नीचे फंस गए।
- 17 दिन बाद फंसे हुए मजदूरों के लिए खाना, पानी और दवा भेजी गई।
- 13 अक्टूबर को सभी मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाल लिया गया।
- अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में कुकरीक माइनिंग इंक खदान में फंसे नौ मजदूरों को 22 इंच चौड़ी लोहे की रिंग की मदद से 77 घंटे बाद बाहर निकाला गया।

सुरक्षित सुरंग निर्माण सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

- भू-तकनीकी जांच: समर्थन प्रणाली डिजाइन और स्थिरता के लिए मिट्टी और चट्टान की स्थिति को समझना।
- जोखिम मूल्यांकन: भूवैज्ञानिक, पर्यावरणीय और परिचालन जोखिमों सहित संभावित खतरों और जोखिमों की पहचान करना।
- व्यावसायिक डिजाइन और इंजीनियरिंग: जमीन की स्थिरता, पानी के प्रवेश और भूकंपीय कारकों जैसे विचारों के लिए अनुभवी सुरंग डिजाइनरों और इंजीनियरों को नियुक्त करना।
- आपातकालीन तैयारी: आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं को नियमित रूप से अद्यतन करना और कर्मियों की जानकारी के लिए अभ्यास आयोजित करना।
- गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण: सख्त गुणवत्ता नियंत्रण उपाय और नियमित निरीक्षण स्थापित करना।

COP28: CCS एंड CDR

GS III – पर्यावरण

संदर्भ: दुबई में COP28 में लिए गए मसौदा निर्णयों में कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (CCS) और कार्बन-डाइऑक्साइड निष्कासन (CDR)

प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हटाने का उल्लेख किया गया है।

सीसीएस (कार्बन कैप्चर और स्टोरेज) के बारे में

- सीसीएस उन प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है जो वायुमंडल में जारी होने से पहले उत्सर्जन के स्रोत पर कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकते हैं।
- इन स्रोतों में जीवाश्म ईंधन उद्योग (जहां बिजली पैदा करने के लिए कोयला, तेल और गैस का दहन किया जाता है) और स्टील और सीमेंट उत्पादन जैसी औद्योगिक प्रक्रियाएं शामिल हैं।
- यह तीन चरणों वाली प्रक्रिया है, जिसमें शामिल हैं:
  o उत्पादित CO2 को कैप्चर करना
  o कैप्चर किए गए CO2 का परिवहन करना
  o इसे गहरे भूमिगत भंडारण करना

सीडीआर (कार्बन-डाइऑक्साइड निष्कासन) के बारे में

- वातावरण से CO2 हटाने के लिए प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं का उपयोग करता है।
- CO2 को कैप्चर करता है और इसे वर्षों तक विभिन्न वातावरणों में संग्रहीत करता है।
- प्राकृतिक (वनरोपण या पुनर्वनरोपण) या प्रौद्योगिकी-आधारित (प्रत्यक्ष वायु ग्रहण) हो सकता है।
- उदाहरणों में उन्नत रॉक अपक्षय और BECCS (कार्बन कैप्चर और भंडारण के साथ बायोएनर्जी) शामिल हैं।

सीसीएस और सीडीआर की चिंताएं और प्रभाव

- बड़े पैमाने पर सीडीआर तरीकों के लिए महत्वपूर्ण भूमि, समानता, जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा मुद्दों को बढ़ाने की आवश्यकता होती है।
- ग्लोबल साउथ में सीडीआर परियोजनाएं स्वदेशी भूमि अधिकारों का उल्लंघन कर सकती हैं और कृषि भूमि उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। सीडीआर को बड़े पैमाने पर लागू करने की लागत और जिम्मेदारी इस बात पर सवाल उठाती है कि इन बोझों को कौन वहन करेगा।
- दशकों के विकास के बावजूद सीसीएस ने बड़े पैमाने पर व्यवहार्यता प्रदर्शित नहीं की है।

बिना किसी हस्तक्षेप के जीवाश्म ईंधन (UNABATED FOSSIL FUELS)

- उन्मूलन का अर्थ है प्रदूषणकारी पदार्थों के उत्सर्जन को स्वीकार्य स्तर तक कम करने का प्रयास।
- आईपीसीसी के अनुसार, बेरोकटोक जीवाश्म ईंधन वे हैं "बिना किसी हस्तक्षेप के जो जीएचजी उत्सर्जन को काफी हद तक कम करते हैं। इसका मतलब है कि कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस के जलने से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) और अन्य ग्रीनहाउस गैसों को कम करने के लिए कुछ नहीं करना।"
- COP28 में, "अनियंत्रित जीवाश्म ईंधन" शब्द का अर्थ उनके उत्सर्जन को कैप्चर करने के लिए सीसीएस प्रौद्योगिकियों का उपयोग किए बिना इन ईंधनों का दहन है।

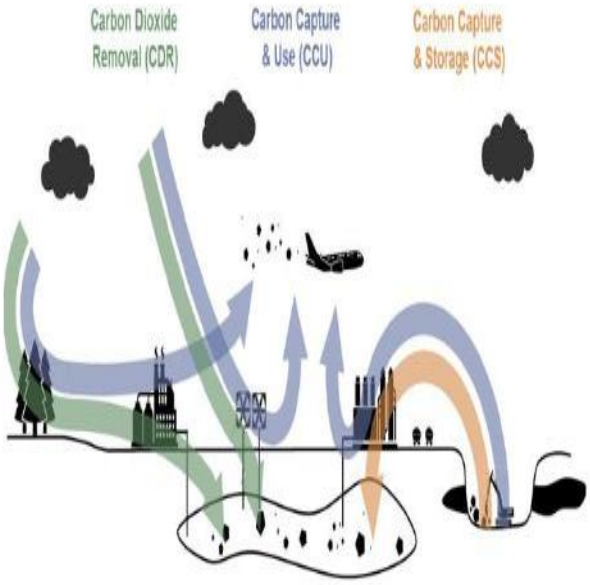

निष्कर्ष

- अगला दशक सीडीआर विधियों की व्यवहार्यता और मापनीयता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। जबकि सीसीएस और सीडीआर उत्सर्जन में कमी के लिए संभावित समाधान पेश करते हैं, अनपेक्षित परिणामों से बचने और न्यायसंगत और प्रभावी जलवायु कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उनके कार्यान्वयन को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जाना चाहिए।

शहरों के लिए COP-28 का क्या मतलब है?

GS III – पर्यावरण

संदर्भ: 2023 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या यूएनएफसीसीसी की पार्टियों का सम्मेलन, जिसे आमतौर पर COP-28 के रूप में जाना जाता है, 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जो एक्सपो सिटी, दुबई में आयोजित किया जा रहा है। सीओपी सम्मेलनों का उद्देश्य सरकारों को वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभावों के अनुकूल नीतियों पर सहमत होना है।

जलवायु कार्रवाई में शहरों का महत्व

- जलवायु कार्रवाई में शहरीकरण एक महत्वपूर्ण कारक है, 2050 तक वैश्विक आबादी का 55% शहरी होगा।
- शहरी क्षेत्र 75% प्राथमिक ऊर्जा की खपत करते हैं और 70% CO2 उत्सर्जन में योगदान करते हैं।
- पेरिस प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए शहरी मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।
- COP-28 में शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन पर एक मंत्रिस्तरीय बैठक शामिल है, जिसमें समावेशी निर्णय लेने पर जोर दिया गया है।
- शहर के प्रतिनिधि बहु-स्तरीय ग्रीन डील प्रशासन और ऊर्जा तथा जलवायु कार्रवाई नियमों को संशोधित करने की वकालत करते हैं।
- यूरोपीय शहर समूह वैश्विक जलवायु वार्ता में उपराष्ट्रीय सरकारों की भूमिका पर जोर देते हुए शहरों में सीधी कार्रवाई की वकालत करते हैं।

ग्लोबल साउथ

- ग्लोबल साउथ के शहर अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में कहीं अधिक असुरक्षित हैं।
- भारत जैसे देशों में, 40% शहरी आबादी झुग्गियों में रहती है, जो शहरी प्रक्रियाओं में आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। प्रदूषण, आर्थिक असमानताएँ और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं।
- ग्लोबल साउथ शहरों के लिए एक प्रस्तावित जलवायु एटलस, हॉटस्पॉट की मैपिंग और पहचान करने का सुझाव दिया गया है। सीओपी परिणामों सहित मौजूदा आर्किटेक्चर से वित्तीय सहायता प्रगति के लिए आवश्यक मानी जाती है।
- चुनौतियों के बावजूद, चेन्नई जैसे कुछ शहर सक्रिय कदम उठाते हैं। चेन्नई का लक्ष्य 2070 के राष्ट्रीय लक्ष्य को पार करते हुए 2050 तक शून्य उत्सर्जन हासिल करना है। महत्वाकांक्षी पहल जलवायु कार्रवाई में शहरों के नेतृत्व को उजागर करती है।

निष्कर्ष

- हालाँकि COP-28 की आलोचना अधिक होने के कारण की जा सकती है, लेकिन यह जलवायु कार्रवाई, सामाजिक न्याय और शहरी क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका के अंतर्संबंध को पहचानने पर आलोचनात्मक चर्चा को बढ़ाता है। यह आयोजन जलवायु परिवर्तन की

चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कमजोरियों को स्वीकार करने, जलवायु योजनाओं में शहर का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के शहरों के लिए वैश्विक समर्थन हासिल करने की आवश्यकता पर जोर देता है।

सुरक्षा और साइबर सुरक्षा

GS III – विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ: साइबर अपराध क्या है?

- साइबर अपराध को "कोई भी गैरकानूनी कार्य जहां कंप्यूटर या संचार उपकरण या कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किसी अपराध को करने या सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- साइबर अपराध व्यक्तियों या संगठनों द्वारा किया जा सकता है, कुछ संगठित हैं, उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं और अत्यधिक तकनीकी रूप से कुशल हैं।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश में वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में पंजीकृत साइबर अपराधों में 24% की वृद्धि देखी गई।
- भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। इसलिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश साइबर अपराध की रोकथाम, पता लगाने आदि के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत सलाह और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की पहल को बढ़ावा देती है।

भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित चुनौतियाँ

- अलग प्रक्रियात्मक कोड का अभाव: साइबर या कंप्यूटर से संबंधित अपराधों की जांच के लिए कोई अलग कोड नहीं।
- साइबर हमलों की ट्रांस-नेशनल प्रकृति: अधिकांश साइबर अपराध ट्रांसनेशनल होते हैं, जिससे विदेशी क्षेत्रों से साक्ष्य एकत्र करना मुश्किल हो जाता है।
- डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार: डिजिटलीकरण और ऑनलाइन लेनदेन भारत को संभावित हैकर्स और साइबर-अपराधियों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बनाते हैं।
- सीमित विशेषज्ञता और अधिकार: ऐसे अपराधों को हल करने की सीमित क्षमता के कारण क्रिप्टो-मुद्रा से संबंधित अपराध कम रिपोर्ट किए जाते हैं।
- साइबर सुरक्षा जागरूकता का अभाव: भारत में कई व्यक्ति और व्यवसाय साइबर सुरक्षा जोखिमों और निवारक उपायों के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं।

उठाए जाने वाले उपाय

- सरकार और निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण साइबर घटनाओं के बाद विश्लेषण और सुधार की सिफारिशों के लिए एकत्र होंगे।
- जीरो-ट्रस्ट वास्तुकला और मानकीकृत प्रतिक्रिया प्लेबुक को अपनाना।
- नेटवर्क रक्षा एवं आधुनिकीकरण हेतु योजना का क्रियान्वयन।
- साइबर घटनाओं की सूचना देना, सुरक्षा करना और निवारण करना सरकार की जिम्मेदारी है।

सरकारी पहल

- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पुलिस जांच अधिकारियों को प्रारंभिक चरण की साइबर फोरेंसिक सहायता प्रदान करता है।
- साइबर अपराध पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए 'साइट्रेन' पोर्टल का उपयोग करता है।
- सुरक्षित साइबरस्पेस के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति (एनसीएसपी) का पालन करता है।
- साइबर अपराधों को रोकने और जांच करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को बढ़ाता है।
- महिलाओं और बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हुए साइबर अपराधों की सार्वजनिक रिपोर्टिंग के लिए एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल प्रदान करता है।
- महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे को साइबर खतरों से बचाता है।
- मैलवेयर-संक्रमित सिस्टम का पता लगाता है और उसे हटाता है।
- साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता है और उन्हें कम करता है।
- व्यापक साइबर अपराध कानून के लिए आईटी अधिनियम, 2000 लागू करता है।

निष्कर्ष

- डार्क वेब पर भारतीयों के डेटा की उपलब्धता के बारे में हालिया रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साइबर घटनाओं की रोकथाम, हिरासत, मूल्यांकन और निवारण सर्वोच्च प्राथमिकता हो। इसे जनसंख्या की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक डिजिटल बुनियादी ढांचे के महत्व को भी पहचानना चाहिए।

भारत में शिपिंग उद्योग

GS III – अर्थव्यवस्था

संदर्भ: भारत में बंदरगाह और जहाजरानी उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और आर्थिक प्रगति में योगदान दे रहा है। भारत में बंदरगाह क्षेत्र बाहरी व्यापार में उच्च वृद्धि से प्रेरित हो रहा है। FY22 में, भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों ने 650.52 मिलियन टन (MT) कार्गो यातायात संभाला।

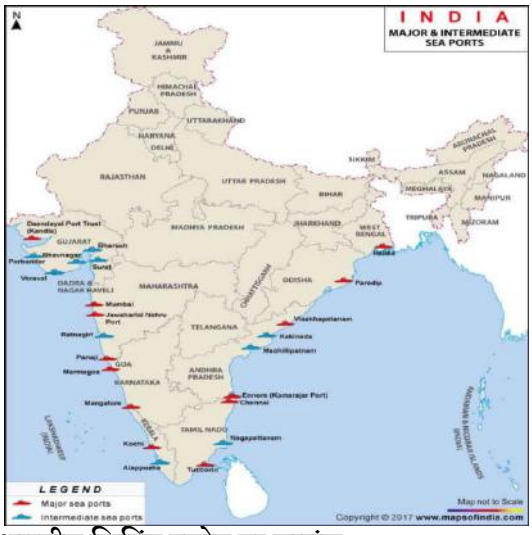

भारतीय शिपिंग उद्योग पर सारांश

- जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार की एक शाखा, शिपिंग नियम और विनियम बनाती और प्रशासित करती है।
- उद्योग में जहाज निर्माण, जहाज-मरम्मत, प्रमुख बंदरगाह, राष्ट्रीय जलमार्ग और अंतर्देशीय जल परिवहन शामिल हैं।
- भारत में पहला जहाज निर्माण कारखाना वर्ष 1941 में विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था।
- प्रमुख जहाज निर्माण केंद्रों में कोलकाता, गोवा, मुंबई और कोच्चि शामिल हैं।
- जापान के सहयोग से विकसित कोच्चि डॉकयार्ड देश में सबसे बड़ा और नवीनतम है।
- सकल पंजीकृत टन भार (जीआरटी) में भारत विश्व स्तर पर 17वें स्थान पर है।
- शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआई) की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी और 2009 में इसे 'नवरत्न' का दर्जा दिया गया था।
- भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (IMU) की स्थापना 2008 में चेन्नई में की गई थी।

शिपिंग क्षेत्र से संबंधित भारत की पहल

ग्रीन पोर्ट एवं शिपिंग में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NoCEGPS)

- भारत का पहला NoCEGPS बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) और ऊर्जा और संसाधन संस्थान के बीच एक सहयोग है। यह हरियाणा के गुरुग्राम में है।
- केंद्र का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (14) को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है ताकि समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषण, संरक्षण और महासागर आधारित संसाधनों के स्थायी उपयोग से बचाया जा सके।
- NCoEGPS MoPSW की छत्रछाया में बंदरगाहों, DG शिपिंग, CSL और अन्य संस्थानों के लिए हरित शिपिंग क्षेत्रों पर नीति, अनुसंधान और सहयोग पर आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए MoPSW की एक तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करेगा।

ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम

- ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम ग्रीन हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम द्वारा संचालित 'ग्रीन हाइब्रिड टग्स' के साथ शुरू होगा और बाद में मेथनॉल, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे गैर-जीवाश्म ईंधन समाधानों को अपनाएगा।
- लक्ष्य है कि 2025 तक सभी प्रमुख बंदरगाहों में शुरुआती ग्रीन टग काम करें और 2030 तक सभी टगों में से 50% को ग्रीन टग में परिवर्तित किया जाए।

पीएम गति शक्ति:

- ग्रीन पोर्ट्स पहल के साथ-साथ मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान - पीएम गति शक्ति के माध्यम से देश में ग्रीन लॉजिस्टिक्स आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास पहले ही तेज हो गया है।
- बंदरगाहों का लक्ष्य 2030 तक प्रति टन कार्गो द्वारा कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करना है।

हरित यात्रा 2050 परियोजना:

- यह नॉर्वे सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के बीच मई 2019 में शुरू की गई एक साझेदारी परियोजना है, जिसका लक्ष्य शिपिंग उद्योग को कम कार्बन भविष्य की ओर बदलना है।

भारत में बंदरगाहों और शिपिंग उद्योग पर डेटा

- भारत का 95% व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है, जिसमें 70% मूल्य के हिसाब से होता है।
- भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह और 205 अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं।
- भारत 30% वैश्विक हिस्सेदारी रखते हुए शीर्ष 5 जहाज रीसाइक्लिंग देशों में से एक है।
- मुंबई बंदरगाह आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
- तमिलनाडु में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या सबसे अधिक है।
- कृष्णापट्टनम बंदरगाह भारत में सबसे गहरा है।
- भारत विश्व स्तर पर सोलहवां सबसे बड़ा समुद्री देश है।
- सरकार बंदरगाह क्षेत्र का समर्थन करती है, 100% एफडीआई की अनुमति देती है।
- FY22 व्यापारिक निर्यात 417.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष से 40% अधिक है।

निष्कर्ष

- बड़े सार्वजनिक क्षेत्र की सुविधाओं के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों के उद्यम के साथ, भारत में शिपयार्ड थे जो आशा देने लगे थे कि वे वैश्विक बाजार के लिए प्रतिस्पर्धी रूप से जहाजों का निर्माण कर सकते हैं। जहाज स्वामित्व, चार्टरिंग, वित्तपोषण और निर्माण को बढ़ावा देने से न केवल भारत वैश्विक समुद्री उद्योग के केंद्र में आ जाएगा, बल्कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उपस्थिति भी बढ़ेगी।

आपदा राहत कोष

GS III – **आपदा प्रबंधन अवलोकन**

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF)

- प्रमुख आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास प्रयासों को वित्तपोषित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित है।
- इसका उद्देश्य गंभीर आपदाओं की स्थिति में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समय पर और प्रभावी वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- 2022-23 के लिए धन आवंटन: छत्तीसगढ़, मेघालय, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के लिए 1,209 करोड़ रुपए।
- 2023-24 के लिए धन आवंटन: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा के लिए 4,984 करोड़ रुपए।
- 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आवंटन: एसडीआरएफ के लिए 1,28,000 करोड़ रुपए से अधिक।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)

- विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन और प्रतिक्रिया में राज्यों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित।
- इसका उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान राहत, प्रतिक्रिया और शमन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- प्राथमिक उद्देश्य: किसी आपदा के मद्देनजर तत्काल राहत उपाय करने में राज्यों का समर्थन करना।
- उपयोग: बचाव और राहत कार्यों, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की बहाली और मरम्मत, आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों, राज्य-स्तरीय आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों के लिए समर्थन, और आपदा प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित विभिन्न आपदा-संबंधी कार्मिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल (एनडीएमए)

- वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) का नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) कर दिया गया।
- शुरुआत में 8 बटालियनें शामिल थीं, अब 15 और प्रत्येक बटालियन में 1149 कर्मी शामिल हैं।

- व्यापक, सक्रिय, बहु-आपदा, प्रौद्योगिकी-संचालित आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से एक सुरक्षित, अधिक आपदा-प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना है।

निष्कर्ष

भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की सक्रिय उपलब्धता और खतरनाक स्थितियों में पूर्व-स्थिति ने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को काफी कम कर दिया है। सरकार ताजिकिस्तान, मंगोलिया, बांग्लादेश, इटली, जापान, एससीओ, जर्मनी, सार्क, रूस और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के साथ कई समझौता ज्ञापनों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आपदा प्रबंधन और तैयारियों को भी मजबूत करती है।

Practice Questions

Q1) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की अध्यक्षता एक अध्यक्ष द्वारा की जाती है जो भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में भी कार्य करता है।

कथन-II:

यह गृह मंत्रालय के अधीन होता है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q2) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

राष्ट्रीय उद्यान	राज्य
ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान	महाराष्ट्र
बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान	तमिलनाडु
ब्लैकबक नेशनल पार्क	छत्तीसगढ़

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) केवल दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q3) गंगा डॉल्फ़िन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कछुआ, मगरमच्छ और शार्क की कुछ प्रजातियों के साथ ये दुनिया के सबसे पुराने प्राणियों में से हैं।
2. गंगा डॉल्फ़िन आमतौर पर अंधी होती हैं।
3. ये एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्सर्जित करते हैं जो शिकार तक पहुंचती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) केवल 2

Q4) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

चक्रवात	प्रकार
निवार	उष्णकटिबंधीय चक्रवात
हमून	शीतोष्ण चक्रवात
मिचौंग	उष्णकटिबंधीय चक्रवात

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q5) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

क्षुद्रग्रह एपोफिस का नाम मिस्र के अराजकता के देवता के नाम पर रखा गया है।

कथन-II:

इसका व्यास लगभग 1,100 फीट (340 मीटर) होने का अनुमान है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q6) हेमोक्रोमैटोसिस के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. फ़्लेबोटॉमी मानक उपचार है।
2. वंशानुगत हेमोक्रोमैटोसिस सबसे कम सामान्य प्रकार है।
3. मेमोरी फॉग इसके लक्षणों में से एक है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) केवल 3

Q7) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

मिशन	वर्ष
चंद्रयान प्रथम	2008
मंगल ऑर्बिटर मिशन (MOM)	2017
एस्ट्रोसैट	2001

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q8) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस मनाया जाता है।

कथन-II:

इस दिन का वार्षिक पालन 1992 में शुरू हुआ।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q9) फ़ार्लोविच्नस रैपिडस के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक छोटा सर्वाहारी जानवर था।
2. यह रेगिस्तान में रहता था।
3. यह 60-90 सेमी (2-3 फीट) लंबा था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 2 और 3

(D) केवल 2

Q10) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए :

पुरस्कार	स्थापित किया गया
भारत रत्न	1979
सरस्वती सम्मान	1991
ज्ञानपीठ पुरस्कार	1961

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q11) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

एमी अवार्ड्स की शुरुआत 1948 में की गई थी और इसकी शुरुआत 25 जनवरी 1959 को हुई थी।

कथन-II:

इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज इंटरनेशनल एम्मीज़ के लिए उत्तरदायी है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q12) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसकी स्थापना 1875 में हुई थी।
2. यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है।
3. इसका मुख्यालय मुंबई में है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 1 और 2

(D) केवल 3

Q13) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

रोग	होने वाले कारण
प्लेग	येर्सिनिया पेस्टिस
न्यूमोनिया	स्ट्रैपटोकोकस निमोनिया
टेटनस	क्लॉस्ट्रिडियम टेटानि

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q14) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

पार्किंसंस रोग एक प्रगतिशील विकार है जो तंत्रिका तंत्र और तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित शरीर के हिस्सों को प्रभावित करता है।

कथन-II:

उम्र के साथ इसके विकसित होने का खतरा बढ़ता जाता है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q15) इसरो के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसने 2005 में चंद्रयान-2 लॉन्च किया।
2. इसने 2023 में चंद्रयान-3 लॉन्च किया।
3. इसने 2012 में मार्स ऑर्बिटर मिशन (एमओएम) या मंगलयान लॉन्च किया।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) केवल 3

Q16) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

नृत्य	राज्य
भरतनाट्यम	आंध्र प्रदेश
कुचिपुड़ी	तमिलनाडु
मोहिनीअट्टम	केरल

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q17) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

डीपफेक शब्द की उत्पत्ति 2017 में हुई थी।

कथन-II:

भारत के पास डीपफेक को विनियमित करने के लिए समर्पित एक व्यापक कानूनी ढांचा है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q18) चुनावी बांड के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे भारतीय नागरिकों या भारत में स्थापित संस्थाओं द्वारा खरीदा जाता है।
2. इसे केवल व्यक्तिगत रूप से ही खरीदा जा सकता है।
3. यह जारी होने की तारीख से 25 कैलेंडर दिनों के लिए वैध है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) केवल 2

Q19) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

अंतर्राष्ट्रीय संगठन	मुख्यालय
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम	नैरोबी
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर	स्वीडन
व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन	न्यूयॉर्क

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q20) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

रोग	के कारण
एंथ्रेक्स	बैसिलस एंथ्रेस
पेप्टिक अल्सर	हेलिकोबैक्टर पाइलोरी
प्लेग	यर्सिनिया पेस्टिस

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q21) सॉवरेन ग्रीन बांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सॉवरेन ग्रीन बांड की आय का उपयोग पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं के लिए किया जाता है।
2. इन्हें कम परिपक्वता अवधि के साथ जारी किया जाता है।
3. पहला हरित बांड 2002 में जारी किया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 2 और 3

(D) केवल 3

Q22) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सार्वजनिक उपद्रव, अपराधों की रोकथाम और पत्नी, बच्चे तथा माता-पिता के भरण-पोषण से भी संबंधित है।
2. यह आरोपी के बयान को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज करने की अनुमति देता है।
3. यह एक पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय हथकड़ी का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है यदि वह अधिक बार अपराधी है और हिरासत से भाग गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) और केवल 3

(D) केवल 3

Q23) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की स्थापना 2005 में की गई थी।

कथन-II:

बोर्ड में सभी G20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q24) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

इसरो मिशन	वर्ष
EOS-04	2005
एस्ट्रोसैट	2015
मंगलयान	2011

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q25) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

रोग	के कारण
चिकनपॉक्स	वैरिसेला जोस्टर विषाणु
मेनिंगोएन्सेफलाइटिस	नेगलेरिया फाउलेरी
एंथ्रेक्स	बैसिलस एन्थ्रेसीस

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q26) दूरसंचार विधेयक, 2023 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें कहा गया है कि दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने, दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करने और रेडियो उपकरण रखने के लिए राज्य सरकार से पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता होगी।
2. मौजूदा लाइसेंस वैध नहीं रहेंगे।
3. इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे निर्दिष्ट उपयोगों को छोड़कर, स्पेक्ट्रम केवल नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 3

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) और केवल 3

(D) केवल 2

Q27) VINBAX-2023 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. VINBAX अभ्यास 2014 में शुरू किया गया था।
2. पहला संस्करण वियतनाम में आयोजित किया गया था।
3. यह भारत और वियतनाम में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 3

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 2 और 3

(D) केवल 2

Q28) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

प्रजाति	आईयूसीएन स्थिति
अफ्रीकी सवाना हाथी	लुप्तप्राय
पिग्मी हॉग	सुभेद्य
जेनकिन का अंडमान स्पाइनी क्रू	गंभीर संकटग्रस्त

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल 1

(B) सिर्फ 2

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q29) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

हैली धूमकेतु को आधिकारिक तौर पर 1P/हैली कहा जाता है।

कथन-II:
यह पहला धूमकेतु था जिसके वापस आने की भविष्यवाणी की गई थी।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q30) कवच प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
2. कवच दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली होगी।
3. पहला सफल परीक्षण 2020 में दक्षिण मध्य रेलवे के गुल्लागुड़ा-चिटगिड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच हुआ था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 1 और 2
(D) केवल 2

Q31) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

ज्वालामुखी	देश
माउंट मौना लोआ	यूएसए
माउंट यासुर	मिस्र
माउंट यासुर	इटली

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q32) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I:
भारतीय टेंट कछुआ भारत, नेपाल और बांग्लादेश का मूल निवासी है।
कथन-II:
यह CITES के परिशिष्ट I के अंतर्गत है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q33) माउंट मरापी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक स्ट्रैटोवोलकानो है।
2. यह जावा द्वीप और इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी योग्यकार्ता के केंद्र के पास स्थित है।
3. मेरापी दक्षिणी जावा का सबसे पुराना ज्वालामुखी है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 1 और 2
(D) केवल 3

Q34) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए :

संगठन	मुख्यालय
ओपेक	न्यूयॉर्क
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ)	जिनेवा, स्विट्जरलैंड
WTO	स्विट्जरलैंड

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q35) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I:
इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) का मुख्यालय जेद्दा, सऊदी अरब में है।
कथन-II:
यह दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q36) एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीसवायरस उपप्रकार (ईईएचवी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ईईएचवी मुख्य रूप से लार, रक्त या मूत्र जैसे संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क से फैलता है।
2. वर्तमान में, EEHV-HD के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है।

3. इसमें कई उपप्रकार शामिल हैं, जिनमें EEHV1A सबसे आम है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) केवल 3

Q37) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

ऑपरेशन	वर्ष
ऑपरेशन पोलो	1979
ऑपरेशन मेघदूत	1984
ऑपरेशन विजय	1961

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q38)अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका मुख्यालय वाराणसी में गिफ्ट सिटी में है।
2. यह कोई वैधानिक निकाय नहीं है।
3. इसके सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 3

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 2 और 3

(D) केवल 2

Q39) भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं देता है।
2. यह उनसे संबंधित विवादों का निपटारा करने के साथ-साथ उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है।
3. यह कोई स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) केवल 1

Q40) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए :

संगठन	मुख्यालय
SEBI	कोलकाता
NCRB	नई दिल्ली
NIA	पुणे

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q41) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किए गए।

कथन-II:

इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q42) एंथ्रोबोट्स के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये मानव कोशिकाओं से निर्मित छोटे जीवित रोबोट हैं।
2. पुनर्योजी चिकित्सा के क्षेत्र में इनके संभावित उपयोग हैं।
3. उनमें स्वयं-संयोजन क्षमताएं होती हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 3

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) केवल 2

Q43) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

मिशन	एजेंसी
मार्स ओडिसी	ESA
न्यू होराइजन	NASA
शुक्रयान	ISRO

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q44) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के दस गुरुओं में से नौवें थे।

कथन-II:

वह सिख धर्म के सबसे पुराने गुरु थे।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q45) वोयाजर-1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह इतिहास का सबसे पुराना मानव निर्मित अंतरिक्ष यान है।
2. इसे केप कैनावेरल, फ्लोरिडा/लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से लॉन्च किया गया था।
3. इसे बृहस्पति और नेपच्यून द्वारा उड़ान भरने के लिए लॉन्च किया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 1 और 2

(D) केवल 3

Q46) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

रिपोर्ट	संगठन
वैश्विक वित्तीय प्रणाली रिपोर्ट	अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस)
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सूचकांक	विश्व बैंक
अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (PISA)	आर्थिक विकास संगठन (OECD)

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q47) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

तमिलनाडु ने विभिन्न राज्यों (LEADS) 2023 रैंकिंग में लॉजिस्टिक्स सुगमता में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।

कथन-II:

यह LEADS रिपोर्ट का छठा संस्करण था।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q48) रेल कौशल विकास योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है।
2. इस योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
3. वे उम्मीदवार, जिन्होंने दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है और जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है, आवेदन करने के पात्र हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) केवल 3

Q49) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए:

टाइगर रिजर्व	राज्य
कान्हा टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश
मेलघाट टाइगर रिजर्व	छत्तीसगढ़
इंद्रावती टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q50) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

वर्ष 1990 में वाल्मिकी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई।

कथन-II:

यह बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q51) कर्रार कॉम्बैट ड्रोन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस मिसाइल का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था।
2. इसे शुरुआत में 2020 में पेश किया गया था।
3. यह दिन और रात में काम करने में सक्षम है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) केवल 3

Q52) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

प्रजाति	आईयूसीएन स्थिति
पिग्मी हॉग	गंभीर रूप से लुप्तप्राय
बड़ा चट्टानी चूहा या एल्विरा चूहा	असुरक्षित
नामदाफा उड़ने वाली गिलहरी	गंभीर रूप से लुप्तप्राय

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q53) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

चिटफंड कोई कानूनी इकाई नहीं है।

कथन-II:

यह आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q54) योगमाया मंदिर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका निर्माण 1806 से 1837 के बीच हुआ था।
2. इसका निर्माण लाला सिधू मल ने करवाया था।
3. देवी योगमाया, भगवान कृष्ण की बहन और दुर्गा का अवतार मानी जाती हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) केवल 3

Q55) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

समुद्र	ओसियन
अंडमान सागर	प्रशांत महासागर
पूर्वी चीन सागर	हिंद महासागर
ओखोटस्क सागर	अटलांटिक महासागर

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q56) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

कथन-I:

अटल बिहारी वाजपेई को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

कथन-II:

उन्हें 2002 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q57) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

कथन-I:

पेंटोइया टैगोरी का नाम देबेंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है।

कथन-II:

यह बंजर भूमि (degraded lands) को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) **कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है**

Q58) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए :

जनजाति	राज्य
कोंडा	हिमाचल प्रदेश
चकमा	त्रिपुरा
ढोडिया	गोवा

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q59) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

युद्धपोत	परियोजना
आईएनएस कोलकाता	प्रोजेक्ट 15ए
आईएनएस उदयगिरि	प्रोजेक्ट 15 बी
आईएनएस हिमगिरी	प्रोजेक्ट 17ए

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q60) watsonx.ai के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह उपयोगकर्ताओं को अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी करने में मदद करेगा।
2. यह NASA द्वारा ही बनाया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है।
3. यह एक एंड-टू-एंड टूलकिट है जिसमें डेटा और एआई गवर्नेंस दोनों शामिल हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) केवल

ONLINE

IAS BABA

Integrated Learning Program (S-ILP) - 2024

Crack UPSC 2024 - The Best Strategy for Next 365 Days (Prelims & Mains)

- High Quality Subjectwise Class Videos
- Daily Targets & Micro Tests
- Personal Mentorship
- 67 Prelims & 59 Mains Tests

Most Trusted

ADMISSION OPEN

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888